चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

www.chauthiduniya.com

1986 से प्रकाशित

दिल्ली, 03 जनवरी 2011–09 जनवरी 2011

मूल्य 5 रुपये

कैसे बोलें नया साल मुबारक हो

पेज-3

मनरेगा का काला सच

पेज-4

ग़लत समय पर सही बहस

पेज-5

साई की महिमा

पेज-12

दिशाहीन भाजपा

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

भारतीय जनता पार्टी देश का मुख्य विपक्षी दल है, पर कमज़ोर है, दिशाहीन है और जनता से कट चुकी है. न ही ऐसा कोई नेता है, जो भ्रष्टाचार और घोटालों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को राष्ट्रीय मुद्दा बना कर देशव्यापी आंदोलन चला सके. देश चलाने वाले घोटाला कर रहे हैं यह आरोप तो सही है, लेकिन विपक्ष भी अपना काम नहीं कर रहा है. देश की जनता भ्रष्टाचार और महंगाई से जूझ रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए आंदोलन की तैयारी में हैं. अफ़सोस की बात यह है कि लालकृष्ण आडवाणी जैसे अनुभवी नेता के मौजूदगी में यह सब हो रहा है.

मनीष कुमार

प्रजातंत्र में विपक्ष का एक रोल होता है. देश की जनता अगर किसी दल को यह दायित्व देती है तो इसका मतलब यह है कि अगले पांच सालों तक वह पार्टी सरकार के कामकाज और नीतियों पर नज़र रखे. सरकार अगर कोई ग़लती करती है तो उसे जनता के सामने लाए और संसद में सत्तारूढ़ पार्टी से जवाब तलब करे. अगर विपक्षी दल ही कमज़ोर हो जाए तो सरकार को बे–लगाम होने में वक़्त नहीं लगता है. देश में एक के बाद एक घोटालों का खुलासा हो रहा है. यह घोटाले केंद्र सरकार की नाक के नीचे हो रहे हैं. सरकार को जनता को जवाब तो देना ही होगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या विपक्ष अपनी जवाबदेही को सही ढंग से निभा रहा है. अगर नहीं तो इन घोटालों के लिए सरकार के साथ–साथ विपक्ष को भी ज़िम्मेदार माना जाएगा. ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ कोई कारगर आंदोलन खड़ा कर सकती है. पहले आईपीएल घोटाला हुआ. जिसमें मंत्री, नेता–अभिनेता, अंडरवर्ल्ड के लोगों का गठजोड़ सामने आया. फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में घोटाला हुआ. इसमें अधिकारियों, नेताओं और बिल्डर्स के साथ–साथ जनता के पैसों को लूटने का खेल सामने आया. फिर 2जी का खुलासा हुआ. इससे पता चला कि देश में दलाल, नेता, उद्योगपति और अधिकारी नियम–क़ानून में उलटफेर कर देश को करोड़ों का चूना लगाते हैं. फिर आदर्श घोटाला आया. पता चला कि देश के लिए जान देने की कीमत क्या है. कारगिल में मरने वाले जवानों के लिए बना घर सेना के अधिकारी और नेता मिल कर हड़प गए. ऐसे हालातों में भी भारतीय जनता पार्टी एक कमज़ोर और दिशाहीन पार्टी की तरह व्यवहार करती रही.

भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कमज़ोरी यह है कि यह पार्टी सरकार के कामकाज पर ख़ुद नज़र रखने में नाकामयाब रही है. भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने एक भी ऐसा खुलासा नहीं किया, जिससे सरकार को घेरा जा सके. जो भी मामले सामने आए हैं, वह मीडिया रिपोर्ट और सूचना के अधिकार से मिली जानकारी से उजागर हुए हैं, इसमें विपक्ष का कोई रोल नहीं है. मान लीजिए, अगर मीडिया और आरटीआई एक्टिविस्ट सजग नहीं होते और देश की जनता विपक्ष पर भरोसा करके बैठी रहती तो न नए घोटाले सामने आते और न ही इतना हंगामा मचता. अफ़सोस तो इस बात का है कि इन मामलों के उजागर होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी कोई सटीक रणनीति नहीं बना पाई, जिससे सरकार को घेरा जा सके. विपक्ष संसद में हंगामा करने के अलावा कुछ नहीं कर सका. सवाल यह है कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए क्या संसद को निष्क्रिय करना ज़रूरी है. संसद को न चलने देने से क्या हासिल हुआ? सरकार ने जेपीसी की मांग को नहीं माना, उल्टा टेलीकॉम के नए मंत्री कपिल सिब्बल ने संसद से बाहर 2जी स्पेक्ट्रम मामले में एक जांच की घोषणा कर दी. विपक्ष चिल्लाता रह गया, सरकार अपने मनमुताबिक़ काम करने में सफल हो गई.

देश की हालत यह है कि भ्रष्टाचार और महंगाई की मार के बीच जनता पिस रही है. प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं. ग़रीब तो दूर अब अमीरों पर भी महंगाई की मार का असर देखने को मिल रहा है. कीमतें आसमान छू रहीं हैं. सरकार ने कीमतों को रोकने के लिए कोई कारगर उपाय नहीं किए और न ही विपक्ष कोई असरदार विकल्प देने में समर्थ है. जनता से जुड़े सवालों को उठाने के बजाए भारतीय जनता पार्टी की युवा विंग कश्मीर चलो आंदोलन करने जा रही है. देश के लोग महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर चिंतित है तो भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने में लगे हैं. भारतीय जनता युवा मोर्चा की यह यात्रा कोलकाता से कश्मीर तक जाएगी. यह यात्रा 12 जनवरी को शुरू होकर 26 जनवरी को श्रीनगर पहुंचेगी. यह देश के लिए अफ़सोस की बात है कि मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी युवा शक्ति को ऐसे काम में लगा दिया है. हैरानी की बात यह है कि जब कश्मीर में पत्थरबाज़ी हो रही थी, तब भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता कहां थे. अब जब वहां शांति बहाल हो गई है, तब ऐसी यात्रा करने का क्या मतलब है. युवा मोर्चे के इस कार्यक्रम से तो यही लगता है कि पार्टी के पास विजन की कमी है. यह वक़्त महंगाई के ख़िलाफ़ आंदोलन करने और भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ने का है. घोटालेबाज़ों को बेनक़ाब करने का है. लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने युवाओं को एक ऐसे आंदोलन में झोंक दिया है, जिसका आम आदमी से कोई रिश्ता–नाता नहीं है. सोचने वाली बात यह है कि किसी भी आंदोलन की सफलता युवाओं की भूमिका पर निर्भर करती है. भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं को पार्टी से यह आदेश मिला है कि वे कश्मीर चलो आंदोलन में अपनी सारी ताक़त लगा दें. ज़िला और राज्य इकाइयों को इस आंदोलन को सफल बनाने की पूरी ज़िम्मेदारी दी गई है. मतलब यह है कि 26 जनवरी तक भारतीय जनता पार्टी की युवाशक्ति महंगाई, भ्रष्टाचार, जमाखोरी के ख़िलाफ़ किसी भी आंदोलन में हिस्सा नहीं ले सकेगी. इससे तो यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और इसके युवा कार्यकर्ता भावनात्मक मुद्दे को उठाकर लोगों का ध्यान बांटने, सरकार, घोटालेबाज़ों और जमाखोरों की मदद करने में जुटी है. एक कमज़ोर और दिशाहीन विपक्ष की यही निशानी है.

किसी भी प्रजातंत्र में विपक्ष का कमज़ोर होना ख़तरे की घंटी है. विपक्ष की कमज़ोरी और दिशाहीनता की वजह से ही सरकारें बे–लगाम हो जाती हैं. अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी चेतावनी दे दी है कि देश का प्रजातंत्र ख़तरे में है. लेकिन जिन लोगों पर प्रजातंत्र को बचाने की ज़िम्मेदारी है, वे ही हंगामा कर रहे हैं. भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ जनता को लामबंद करके देशव्यापी आंदोलन बनाने के बजाए राजनीति कर रहे हैं. सरकार और विपक्ष एक दूसरे को नीचा

(शेष पृष्ठ 2 पर)

देश की हालत यह है कि भ्रष्टाचार और महंगाई की मार के बीच जनता पिस रही है. प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं. ग़रीब तो दूर अब अमीरों पर भी महंगाई की मार का असर देखने को मिल रहा है. कीमतें आसमान छू रही हैं. सरकार ने कीमतों को रोकने के लिए कोई कारगर उपाय नहीं किए और न ही विपक्ष कोई असरदार विकल्प देने में समर्थ है. जनता से जुड़े सवालों को उठाने के बजाए भारतीय जनता पार्टी की युवा विंग कश्मीर चलो आंदोलन करने जा रही है.

वर्तमान चेयरपर्सन मृणाल पांडेय भी लाली की कार्यशैली पर अपनी चिंता ज़ाहिर कर चुकी थीं.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

प्रसार भारती से लाली की छुट्टी

प्रसार भारती के विवादास्पद मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी एस लाली इस बार नहीं बच सके. राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल की ओर से सुप्रीम कोर्ट द्वारा लाली के ख़िलाफ़ कई प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितताओं की जांच की स्वीकृति देने के दो सप्ताह बाद सरकार ने अंततः कार्रवाई करने का फ़ैसला किया और उन्हें निलंबित कर दिया गया. केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा 1971 बैच के आईएएस अधिकारी लाली पर गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद प्रसार भारती के भीतर अधिकारियों के बीच गुटबंदीचरम पर पहुंच चुका था. हालांकि, कई अधिकारी इससे पहले से ही लाली के काम करने की शैली और उनके द्वारा लिए गए कई विवादास्पद निर्णयों से खफा थे. प्रसार भारती के पूर्व चेयरमैन अरुण भटनागर ने तो लाली के गलत कामों की आलोचना करने के बाद से ही इस्तीफा दे दिया था. वर्तमान चेयरपर्सन मृणाल पांडेय भी लाली की कार्यशैली पर अपनी चिंता जाहिर कर चुकीं थी. लाली की इस तरह विदाई के बाद भी देश के सबसे बड़ी प्रसारण सेवा और इसके भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं.

केंद्रीय सूचना आयोग की चुनौती

केंद्रीय सूचना आयोग में पूर्व नौकरशाहों की मौजूदगी हमेशा से आरटीआई कार्यकर्ताओं के लिए विवाद का विषय रही है. नये मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में सत्यानंद मिश्रा की नियुक्ति से यह बहस और ज़ोर पकड़ने लगी है. मिश्रा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में सचिव रह चुके हैं. आरटीआई कार्यकर्ताओं का कहना है कि सूचना आयुक्त जैसे पद के लिए पूर्व बाबुओं का चयन ग़लत है. लेकिन सरकार ऐसा नहीं सोचती. मिश्रा से पहले ए एन तिवारी और वजाहत हबीबुल्लाह भी पूर्व नौकरशाह ही थे. दिलचस्प रूप से जब मिश्रा डीओपीटी में थे तो उन्होनें वजाहत हबीबुल्लाह के उस कथन की मुखालफत की थी, जिसमें फाइल नोटिंग को आरटीआई के दायरे में रखने की बात कही गई थी. अब वही मिश्रा मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं.

रामचंद्रन बने मायावती के सलाहकार

रिटायर आईएएस अधिकारी एम रामचंद्रन की उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती के सलाहकार के रूप में नियुक्ति से कई पुराने और वरिष्ठ बाबू आश्चर्य में हैं. रामचंद्रन, उत्तराखंड कैडर के अधिकारी थे और शहरी विकास मंत्रालय में सचिव पद से रिटायर हुए थे. साथ ही केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव पद की दौड़ में थे. लेकिन जैसे ही केंद्र सरकार ने वर्तमान कैबिनेट सचिव के एम चंद्रशेखरन को दो साल का सेवा विस्तार दिया, वो इस दौड़ से बाहर हो गए. विश्लेषकों के लिए सबसे हैरानी की बात यह थी कि रामचंद्रन का नाता उत्तर प्रदेश से ख़त्म हुए एक दशक हो गया था, जब वह 2000 में उत्तराखंड कैडर में चले गए थे. फिर भी मायावती ने उन्हें अपना सलाहकार बनाया.

dilipcherian@gmail..com

साउथ ब्लॉक

गुप्ता बने विकास आयुक्त

कपड़ा मंत्रालय में संयुक्त सचिव शिव शंकर गुप्ता को अब इस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले हस्तशिल्प विभाग में विकास आयुक्त का स्थायी प्रभार सौंपा गया है. गुप्ता 1982 बैच के आईए एस अधिकारी हैं. गुप्ता संजय अग्रवाल की जगह लेंगे.

राज सिंह एनसीएमइआई में

राज सिंह को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है. यह आयोग मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत आने वाले वाले उच्च शिक्षा विभाग में आता है. राज सिंह से पहले इस पद पर रंगनाथ थे. यह पद संयुक्त सचिव पद के समकक्ष है.

एनएचएआई का चेयरमैन कौन?

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर चल रहा संशय अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है. जबकि वर्तमान चेयरमैन बृजेशवर सिंह का कार्यकाल 31 दिसंबर को ही ख़त्म हो गया. सूत्रों के मुताबिक़ सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव आर एस गुजराल एनएचएआई के चेयरमैन का अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगे.

इलियास पहुंचे ट्राई

केरल कैडर और 1982 बैच के आई ए एस अधिकारी और अभी इस्पात मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में काम कर रहे जी इलियास को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण में सदस्य नियुक्त किया गया है.

महेश नए निदेशक

वर्ष 1984 बैच के आईडीएसई अधिकारी महेश कुमार गुप्ता को कपड़ा मंत्रालय में वर्तमान निदेशक ए एन शर्मा की जगह नए निदेशक के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है.

दिशाहीन भाजपा

पृष्ठ एक का शेष

दिखाने में जुटे हैं. भारत की राजनीति ऐसे दौर में है, जहां सरकार से ज़्यादा विपक्ष की ज़िम्मेदारी बढ़ गई है. देश की मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हाल में सामने आए घोटालों को लेकर सरकार पर निशाना साध रही है. आदर्श सोसायटी घोटाला और 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में भारतीय जनता पार्टी संयुक्त संसदीय समिति की मांग कर रही है. भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के दूसरे दलों ने संसद का शीतकालीन सत्र नहीं चलने दिया. जिसकी वजह से करोड़ो का नुक़सान तो हुआ ही साथ ही कोई नतीजा भी नहीं निकल सका. सरकार और विपक्ष मीडिया के ज़रिए ही एक–दूसरे पर संवाद करती नज़र आई. अब, जब शीतकालीन सत्र ख़त्म हो गया है तब कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अधिवेशन और महारैली करके अपनी–अपनी बातों को जनता और कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया. कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को जहां यदुरप्पा के मामले में घेरने की कोशिश की, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सीधे प्रधानमंत्री पर हमला बोल दिया. नई दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित एक रैली में भाजपा के लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि प्रधानमंत्री उनके कार्यकाल में हुए घोटाले की जवाबदेही से बच नहीं सकते. अरुण जेटली ने कहा कि प्रधानमंत्री जेपीसी गठन की इजाज़त दें और फिर उसके सामने हाज़िर होकर सभी आरोपों का जवाब दें और यदि वे ऐसा नहीं कर सकते तो नैतिकता के आधार पर अपना पद छोड़ दें.

लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने मुख्य सतर्कता आयुक्त पी जे थॉमस की ताजपोशी के लिए सीधे प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि उनके मना करने के बावजूद प्रधानमंत्री ने थॉमस को सीवीसी बना दिया. आरोप लगाना एक बात है और सरकार के फ़ैसलों का सही विश्लेषण करना और बात होती है. सरकार जब नेता प्रतिपक्ष की बात को दरकिनार करने का साहस दिखाती है तो इसका मतलब यही है कि विपक्ष कमज़ोर है और सरकार को लगता है कि इनकी सहमति और असहमति का कोई असर नहीं पड़ने वाला है. अगर उन्हें यह डर रहता कि विपक्ष की बात नहीं मानी गई तो जनता उनके ख़िलाफ़ हो जाएगी तो प्रधानमंत्री ऐसे फ़ैसले करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते. समस्या यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक विपक्ष की ज़िम्मेदारियों और कर्तव्यों को ठीक से समझ ही नहीं पाई है.

भारतीय जनता पार्टी संयुक्त संसदीय समिति जांच की मांग पर अडिग है. भाजपा को जब भी और जहां भी मौका मिल रहा है, वह संयुक्त संसदीय समिति की मांग दोहराती रही है. साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री से इस्तीफ़े की मांग की है. भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति का समर्थन जनता नहीं कर रही है. देश की जनता भ्रष्टाचार से मुक्ति चाह रही है, प्रधानमंत्री से नहीं. फिर क्या वजह है कि वह भ्रष्टाचार से लड़ने के बजाए कांग्रेस से लड़ रही है. यह भारतीय जनता पार्टी की ग़लती है कि एक वैचारिक लड़ाई की जगह उसने इस लड़ाई को व्यक्तिगत बना दिया है. भाजपा ऐसी ग़लती पहले भी कर चुकी है. पिछले चुनाव में आडवाणी ने मनमोहन सिंह को एक कमज़ोर प्रधानमंत्री बताया. लोगों ने आडवाणी की बातें नहीं मानीं. लोकसभा के चुनाव परिणाम सामने हैं. अब आडवाणी जी जैसे अनुभवी नेता को अगर कमज़ोर और नम्र नेता का अंतर पता नहीं है, तो कोई क्या कर सकता है. यूपीए के शासनकाल में 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ खेलों के दौरान हुआ भ्रष्टाचार, मुंबई के आदर्श सोसायटी घोटाला या फिर आईपीएल घोटाला देश के सामने आया है. यह एक ऐतिहासिक मौका है, जब भारतीय जनता पार्टी देश की तस्वीर बदल सकती है. लेकिन विपक्ष बेबस और दिशाहीन नज़र आ रहा है. विपक्ष के पास भ्रष्टाचार से लड़ने का न कोई विजन है और न ही ताक़त. यही वजह है कि लोगों की नाराज़गी के बावजूद विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों का असर नहीं हो रहा है. विपक्ष की दिशाहीनता की वजह से यह ख़तरा और भी गहरा गया है.

विपक्ष की साख ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है. सरकार की आलोचना करने से पहले यह देखना भी ज़रूरी है कि कहीं वही ग़लती विपक्षी पार्टी ख़ुद तो नहीं कर रही है. लोगों को जब यह पता चलता है कि जिस बात के लिए विपक्ष सरकार की अलोचना कर रही है, अगर वही ग़लती वह ख़ुद कर रही है तो जनता का भरोसा विपक्ष पर से उठ जाता है. विपक्ष लोगों की नज़रों में गिर जाता है. अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने यदुरप्पा के ख़िलाफ़ एक्शन क्यों नहीं लिया. आदर्श घोटाले के सामने आते ही कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को हटा दिया. यह ऐसी सोची–समझी रणनीति थी, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है. यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ाई के सारे दावे फीके दिखते हैं. हैरानी की बात यह है कि भ्रष्टाचार में लिप्त होने के साथ–साथ यदुरप्पा ने पार्टी के अनुशासन को तोड़ा. दिल्ली बुलाए जाने पर वह नहीं आए और जब आए तो अपने समर्थकों की परेड करा दी. क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता यदुरप्पा से इस्तीफा मांगने की हिम्मत नहीं जुटा सका.

भारतीय जनता पार्टी में लीडरशिप क्राइसिस है. पार्टी में जो नेता फ़ैसले लेते हैं या फिर जिनकी बातों को मानकर फ़ैसला लिया जाता है, उनमें से ज़्यादातर लोग राज्यसभा से आते हैं. उन्हें चुनाव नहीं लड़ना पड़ता है. पार्टी संगठन में अपनी पैठ की वजह से वे संगठन की ऊंची कुर्सियों पर विराजमान हैं. पार्टी में ज़मीन से जुड़े हुए लोगों की कमी है. जो जनता से जुड़े हैं, उन्हें एक–एक करके साइडलाइन कर दिया गया है. इसलिए पार्टी के डिसिजन मेकर्स तक जनता की बात नहीं पहुंचती. ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी याद आते हैं. वाजपेयी छह साल तक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन भारतीय राजनीति में उनकी पहचान एक विपक्ष के नेता की है. विपक्ष में रहते हुए उन्होंने न सिर्फ़ अपनी लोकप्रियता बढ़ाई, लोगों के दिल भी जीते. यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के विरोधी भी उन्हें राइट मैन इन द रौंग पार्टी कहते थे. अटल बिहारी वाजपेयी अगर सक्रिय होते तो वह कभी भी मनमोहन सिहं को एक कमज़ोर प्रधानमंत्री नहीं बताते. हां, यह बात ज़रूर है कि उनकी नीतियों एवं घोटालों के लिए सरकार को छोड़ते भी नहीं. भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कुछ और होती. वाजपेयी राजनीति में व्यक्तिगत हमला नहीं करते थे. दूसरा अंतर यह होता कि आज भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ विपक्ष अलग–थलग है. वाजपेयी सबसे पहले विपक्ष के सभी दलों को एकजुट करते और उसके बाद सरकार पर नीतिगत हमला करते. वाजपेयी के रहते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री यदुरप्पा अपनी कुर्सी पर विराजमान नहीं रहते. अगर ऐसा होता तो वह पार्टी की रैलियों में नहीं जाते और अपना विरोध सार्वजनिक करने से नहीं चूकते. अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता थे, जब वह विपक्ष में थे तो सरकार भी उनके आरोपों को गंभीरता से लेती थी. उसकी वजह यह थी कि वह सरकार की नीतियों का सही आकलन करते थे, वह आकलन ऐसा होता था, जिसे जनता भी सच मानती थी. जब अटल जी बोलते थे तो देश की जनता को लगता था कि वह उनकी ज़ुबान बोल रहे हैं. अटल जी की इसी ख़ासियत की वजह से सत्तारूढ़ दल के नेता भी उनकी इज़्ज़त करते थे. वह जनता की नब्ज़ को पहचानते थे. अटल जी सिर्फ़ विरोध करने के लिए सरकार या मंत्री का विरोध नहीं करते थे. ऐसे कई मौके हैं, जब लोकसभा में उन्होंने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की तारीफ़ भी की. अटल बिहारी वाजपेयी ने जब भी ऐसा किया उनकी लोकप्रियता तो बढ़ी ही, साथ ही उनकी अपनी साख जनता में मज़बूत होती चली गई. यही वजह है कि वह हमेशा देश के सबसे लोकप्रिय नेता बने रहे. देश की जनता को लगता था कि विपक्ष का नेता ऐसा है, जो जनता की बातों और भावनाओं को सरकार तक पहुंचाता था. प्रजातंत्र में विपक्ष का सही रोल यही है. आज भारतीय जनता पार्टी जनता से कट चुकी है.

विपक्ष की जो विश्वसनीयता होनी चाहिए, वह भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है. भारत–अमेरिका न्यूक्लियर डील में भाजपा की भूमिका क्या थी. जब सारे विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना रुख़ नरम क्यों किया. विकीलीक्स के खुलासे में पता चला कि इस दौरान अमेरिकी अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात कर रहे थे. भारतीय जनता पार्टी ने अगर न्यूक्लियर डील में सरकार का साथ नहीं दिया होता तो आज वह भ्रष्टाचार, घोटालों और महंगाई के ख़िलाफ़ सफल आंदोलन कर सकती थी. भारतीय जनता पार्टी ने न्यूक्लियर डील में दूसरे विपक्षी दलों का साथ नहीं दिया तो अब दूसरे दल भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दे रहे हैं. उन्हें भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं है. दूसरी बड़ी समस्या यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी ऐसा नेता नहीं है जो विपक्ष के सभी दलों को एकजुट कर सके. भारतीय जनता पार्टी को इस काम के लिए जनता दल यूनाइटेड के नेता शरद यादव पर आश्रित होना पड़ता है. भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने पूर्व प्रधानमंत्री वी पी सिंह का उदाहरण मौजूद है. बोफोर्स के मामले को उठाकर उन्होंने भ्रष्टाचार को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया. अलग–अलग राजनीतिक दलों को एकजुट किया. देशव्यापी आंदोलन चलाया और राजीव गांधी को चुनाव में परास्त किया. आज देश में ठीक वैसा ही माहौल है, जैसा वी पी सिंह के समय था. लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई नेता नहीं है, वो विजन नहीं है, जिससे भ्रष्टाचार को राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर सत्तारूढ़ दल को परास्त कर सके.

manish@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
देश का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 2 अंक 43
दिल्ली, 03 जनवरी 2011–09 जनवरी 2011
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63, नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–4783999/11–23418962
विज्ञापन + 91 9810017924
प्रसार + 91 9013478398
फैक्स न. 0120–4783950

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड एवं उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

संसद से सड़क तक. यह साल हंगामे और विरोध-प्रदर्शन के नाम रहा. लेकिन सालों बाद दिल्ली ने किसानों को एकजुट होकर अपने हक़ के लिए सड़क पर उतरते देखा.

कैसे बोलें नया साल मुबारक हो

साल 2010, जनवरी. बीस रुपये किलो में मिलने वाली प्याज दिसंबर तक आते-आते 80 रुपये किलो मिलने लगी. दूध 35 और पेट्रोल 60 रुपये तक पहुंचने को बेताब. जनवरी में सोना 16 हज़ार प्रति दस ग्राम था तो दिसंबर तक इसकी चमक बढ़ कर 20 हज़ार रुपये से ज़्यादा हो गई. चांदी 24 से बढ़ कर 45 हज़ार रुपये प्रति किलो के आकड़ें को पार कर गई. ज़ाहिर है, नए साल का स्वागत करने के लिए आम आदमी को अपनी जेब ढीली नहीं, काटनी पड़ेगी. वह आम आदमी, जो एक सरकारी आकड़े के मुताबिक़ रोज़ाना 20 रुपये में अपनी ज़िंदगी गुजारता है, नए साल के पहले दिन का स्वागत कैसे करेगा, यह सोचने की बात है. लेकिन इन सब की फ़िक्र किसे है? अगर फ़िक्र होती, तो क्या 1 लाख 76 हज़ार करोड़ रुपये का 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला होता. फ़िक्र होती तो क्या संसद का शीतकालीन सत्र बिना एक दिन बिना काम किए ख़त्म हो जाता? फ़िक्र होती तो क्या करगिल शहीदों के लिए आवंटित ज़मीन पर सेना के पूर्व अधिकारियों और नेताओं की मिलीभगत से क़ब्ज़ा हो पाता? शायद नहीं.

शशि शेखर

सवाल कई हैं. लेकिन ये चंद सवाल ही इस देश के शासक वर्ग की मंशा को साफ कर देते हैं. आम आदमी के साथ खड़े होने का दावा करने वाले नेताओं की कलई खोल देते है. बीता साल ऐसी कई यादें हमें दे गया, जो बहुत जल्द भुलाई नहीं जा सकेंगी. उदाहरण के लिए टेप कांड. मीडिया, दलाल और कॉरपोरेट के गठजोड़ का पर्दाफाश हुआ. पता चला, आम आदमी की आवाज़ समझा जाने वाला मीडिया एक सुपर दलाल नीरा राडिया के माध्यम से कॉरपोरेट घरानों की आवाज़ बन गया. नामचीन पत्रकारों, नेताओं और उद्योगपतियों को एक दलाल से बात करते और उसकी हां में हां मिलाते, दुनिया ने सुना. आम आदमी के पैसों को अपना मान कर लूट की खुली छूट दी गई. बिहार चुनाव के दौरान केंद्र सरकार कहती रही कि बिहार का विकास केंद्र के पैसे से हुआ है? लेकिन स्पेक्ट्रम घोटाले में डूबे पौने दो लाख करोड़ रुपये किसके थे, इसका जवाब सरकार नहीं दे सकी. स्पेक्ट्रम मामले पर जेपीसी की मांग को लेकर विपक्ष ने संसद के शीतकालीन सत्र को एक दिन भी नहीं चलने दिया. इस साल, संसद में काम के नाम पर इतना ही हुआ कि सांसदों ने अपना वेतन-भत्ता बढ़वाने संबंधी विधेयक पारित करवा लिया. राज्य सभा में महिला आरक्षण विधेयक पास तो हुआ, लेकिन लोकसभा में आकर अटक गया. कुल मिला कर संसद जैसी महत्वपूर्ण संस्था से भी जनता को निराशा ही हाथ लगी.

संसद से सड़क तक. यह साल हंगामे और विरोध-प्रदर्शन के नाम रहा. लेकिन सालों बाद दिल्ली ने किसानों को एकजुट होकर अपने हक़ के लिए सड़क पर उतरते देखा. विकास के नाम पर जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हज़ारों-लाखों किसानों की ज़मीन सरकार ने जबरन अधिग्रहित की, वो भी बहुत कम दर पर, उससे इस देश के किसानों को संगठित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. 15 अगस्त, इस दिन देश आज़ादी का जश्न मना रहा था. दूसरी ओर, अलीगढ़ और मथुरा की सड़कों पर पुलिस किसानों पर लाठियां और गोलियां बरसा रही थी. लेकिन, इस देश की सरकार को 114 साल पुराने भू-अधिग्रहण क़ानून को बदलने या संशोधित करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई.

इतिहास के पन्नों में यह साल घोटालों के साल के रूप में भी याद रखा जाएगा. चौथी दुनिया ने सबसे पहले आईपीएल में महाघोटाले का संकेत दे दिया था. बाद में क्या हुआ, सब जानते हैं. कॉमनवेल्थ गेम्स कॉमन मैन (आम आदमी) की संपत्ति के लूट का खेल बन गया. बाद में, जांच शुरू होने के बाद भी कलमाड़ी अपने पद पर बने रहे. सबसे दुख की बात तो यह थी कि जिन प्रवासी मज़दूरों ने राष्ट्रमंडल खेलों को सफल बनाने में अपनी जान तक गंवाई, उन्हें ही हमारे देश के गृह मंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री सारी समस्याओं की जड़ बता रहे थे. चौथी दुनिया ने अपनी एक्सक्लुसिव ख़बर में बताया था कि ए के एंटनी को आदर्श घोटाले की सूचना बहुत पहले से थी. उन्हें यह जानकारी समाजवादी पार्टी के एक सांसद यशबीर सिंह ने अगस्त 2010 में ही पत्र के माध्यम से दे दी थी. अपने पत्र में यशबीर सिंह ने साफ-साफ लिखा था कि आदर्श कोऑपरेटिव सोसायटी (लि.) ने ग़ैर क़ानूनी तरीक़े से कोलाबा के आवासीय क्षेत्र नेवी नगर और रक्षा प्रतिष्ठान के आस-पास इमारत का निर्माण किया है. इस पत्र का जवाब ए के एंटनी ने दिया तो ज़रूर, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ. हां, घोटाला सामने आने पर हाईकमान (जैसा कि अक्सर होता है) के आदेश पर मुख्यमंत्री अशोक च्वहाण से इस्तीफ़ा ले लिया गया. कार्रवाई के नाम पर सरकार ने बस यही किया. यूपीए सरकार को भ्रष्टाचार के आरोप में अपने कई मंत्रियों मसलन राजा, थरूर से इस्तीफ़ा लेना पड़ा, लेकिन विवादास्पद सीवीसी पीजे थॉमस की नियुक्ति पर विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे पाई. थॉमस की विश्वसनीयता पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संदेह ज़ाहिर करने के बाद भी सरकार कोई कार्रवाई करने से बचती रही.

भ्रष्टाचार के मामले में राजनीतिक पार्टियों के बीच कोई खास अंतर नहीं दिखा. कर्नाटक में बीजेपी सरकार के मुखिया वी एस येदुरप्पा भूमि आवंटन घोटाले में साफ-साफ फंसते दिखे, लेकिन बीजेपी चाह कर भी उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकी. हद तो तब हो गई, जब सेना पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे. सुकना भूमि घोटाले में ख़ुद आर्मी की कोर्ट ने सेना के दो अधिकारियों की संलिप्तता की बात कही. लेफ्टीनेंट जनरल और मेजर जनरल स्तर के इन अधिकारियों के ख़िलाफ़ सेना को कोर्ट ने कार्रवाई के आदेश दिए. आम आदमी का सेना और न्यायपालिका से भरोसा दरकता नज़र आया जब सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कहीं कुछ सड़ गया है और यहां भाई-भतीजावाद चरम पर है.

नक्सलवाद की समस्या को लेकर भी सरकार सिर्फ़ जवाबी हमला करने में ही मशगूल रही. प्रधानमंत्री ने कांग्रेस महाधिवेशन में यह ज़रूर कहा कि इस समस्या के ख़िलाफ़ लड़ाई केवल सुरक्षा बलों के ज़रिए ही नहीं जीती जा सकती, क्योंकि इस समस्या का एक पहलू विकास के मुद्दे से भी जुड़ा हुआ है. लेकिन संसाधन के असमान वितरण और लूट-खसोट को रोकने के लिए सरकार के पास कोई मशीनरी ही नहीं है. हालांकि बिहार चुनाव के दौरान वहां के मतदाताओं पर माओवादियों की धमकी अपना असर नहीं दिखा सकी. इसका मतलब साफ है कि जब विकास होते हुए दिखेगा तो इस तरह की समस्याएं अपने-आप ख़त्म हो जाएंगी. इसके अलावा, 2010 में भी सुरक्षा एजेंसियां आतंकवादी गतिविधियां रोक पाने में नाकाम रहीं. पुणे में हुए ब्लास्ट में हेडली का नाम सामने आया. लाख कोशिशों के बाद भी सुरक्षा एजेंसियां उसे भारत ला पाने में नाकाम रही. साल के अंत में एक बार फिर बनारस की शाम धमाकों से गूंज उठी.

लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं, जिसे सुलझाने के बजाए उलझाने में ही सरकार को ज़्यादा फ़ायदा दिखता है. ऐसी ही एक समस्या है कश्मीर की. सरकार कश्मीर को लेकर इस साल भी केंद्र सरकार पशोपेश की स्थिति में थी. जब घाटी में हिंसा की आग भड़की तो दिल्ली से एक मध्यस्थ दल को भेजा गया. लेकिन, वरिष्ठ पत्रकार और कश्मीर पर बने मध्यस्थ दल की अध्यक्षता कर रहे दिलीप पडगांवकार ने श्रीनगर में कह दिया कि कश्मीर में शांति बहाली के लिए जारी बातचीत में पाकिस्तान को भी शामिल किया जाना चाहिए. पडगांवकर का कहना था कि अगर लोग यह मानते हैं कि बिना पाकिस्तान के साथ बातचीत किए हालात को सुधारा जा सकता है तो यह ग़लत होगा. पाकिस्तान, कश्मीर मामले में 1947 से ही जुड़ा हुआ है. इसलिए शांति बहाली के लिए उनसे बातचीत आवश्यक है. सवाल है कि जिस आदमी पर कश्मीर में शांति बहाली के लिए रास्ता खुलवाने की ज़िम्मेदारी थी, वही आदमी इस मामले में ऐसे ग़ैर ज़िम्मेदाराना बयान देकर आख़िर क्या साबित करना चाहता था. बात अगर नीयत की ही की जाए तो संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार येन-केन-प्रकारेण बड़े भाई की भूमिका में ही ख़ुद को देखना चाहता है. ज़ाहिर है, कश्मीर के मामले में भी केंद्र सरकार की नीयत भी कुछ-कुछ ऐसी ही है.

वैसे जब बात नीयत की हो रही है तो बीते साल एक और महत्वपूर्ण मसला केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करता दिखा. यह मसला था, सूचना का अधिकार क़ानून के कुछ नियमों में संशोधन के प्रस्ताव का. सूचना का अधिकार क़ानून (आरटीआई) स्वतंत्र भारत में बना पहला ऐसा क़ानून है, जिसने आम आदमी को भ्रष्ट व्यवस्था से सवाल पूछने की ताक़त दी. नेता और नौकरशाहों को पहली बार लगा कि कोई उनसे भी सवाल पूछ सकता है. सरकार को आम आदमी की यही आदत अच्छी नहीं लगती. इसलिए, इस क़ानून को निष्प्रभावी बनाने के लिए इस क़ानून के कुछ महत्वपूर्ण नियमों में संशोधन की बात की गई. ये संशोधन ऐसे हैं, जो अगर पास हो गए तो आम आदमी के लिए सवाल पूछना उतना ही कठिन काम हो जाएगा, जितना कि एक भ्रष्ट व्यवस्था को जनता के सवालों का जवाब देना. इसके अलावा, 2010 के पहले सात महीने में आठ ऐसे सूचना के सिपाहियों की हत्या कर दी गई, जिन्होंने भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी. इनके सवालों ने अवैध खनन करने वालों की पोल-पट्टी खोल दी थी. भूमि घोटाले का पर्दाफाश हुआ. ये ऐसे सवाल थे, जिनसे भ्रष्टाचारियों की नींद हराम हो गई थी. सच और सूचना के ये सिपाही भ्रष्टाचारियों के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बन गए थे.

अंतरराष्ट्रीय पटल पर भी भारत की तस्वीर चमकती हुई तो दिखी लेकिन कोई बड़ी उपलब्धि मिली हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता. इस साल के अंत में बराक ओबामा, निकोलस सरकोजी, वेन जियाबाओ और दिमित्री मेदवेदेव भारत की यात्रा पर आए. इन यात्राओं में से जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा हुई, वह भारत के हिसाब से सफल नहीं माना जा सकता. सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के मामले पर अमेरिका का रुख़ स्पष्ट नहीं था. कश्मीर के लोगों के लिए नत्थी वीजा के मसले और सीमा विवाद पर जियाबाओ का बयान भी आम आदमी की समझ में नहीं आया. हां, फ्रांस ने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का खुल कर समर्थन किया और भारत में दो परमाणु रिएक्टर लगाने पर भी सहमति बनी. रूस चूंकि भारत का सबसे पुराना दोस्त रहा है, इस नाते मेदवेदेव ने अपनी यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच तेल, गैस, अंतरिक्ष और तकनीक के क्षेत्र में समझौते किए. साथ ही आतंकवाद के ख़िलाफ़ भी जम कर बोले. अंतरराष्ट्रीय पटल पर 2010 का आख़िरी महीना कुछ ज़्यादा ही चर्चा में रहा. वजह, विकीलीक्स के खुलासे. जूलियन असांज और विकीलीक्स के खुलासों ने अमेरिका सहित भारतीय नेताओं के दोहरे चरित्र को भी उजागर किया. अमेरिका के लोकतांत्रिक चेहरे की असलियत तब सामने आ गई, जब खुलासों के बाद अमेरिका ने असांज को फंसाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया. साथ ही दो देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय संबंधों की पोल भी इन खुलासों की वजह से खुली. अमरीकी राजनयिक भारत या अन्य देशों के बारे में क्या सोचते हैं, यह जगज़ाहिर हुआ. राजनयिकों के मुस्कुराते चेहरों के पीछे की असलियत भी सामने लाने में विकीलीक्स सफल रहा.

एक आख़िरी उम्मीद. नवंबर 2010 में जब बिहार विधान सभा चुनाव के परिणाम आएं, तो ऐसा लगा कि एक आख़िरी उम्मीद अभी भी बची है. ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है. जिस तरह से बिहार की जनता ने जाति और धर्म को भुला कर विकास के नाम पर वोट किया, वह देश के लिए एक संदेश बन गया. उम्मीद तब और भी मज़बूत हुई जब नीतीश कुमार ने राइट टू सर्विस एक्ट, अवैध संपत्ति ज़ब्त करने के लिए क़ानून बनाने और विधायक फंड ख़त्म करने की घोषणा की. और हां, इस देश की जनता को ख़ुशी के कुछ पल सचिन तेंदुलकर भी दे गए. टेस्ट क्रिकेट में शतकों का अर्धशतक लगा कर.

बहरहाल, 2010 ने आम आदमी को एक संदेश ज़रूर दिया है. संदेश यह कि अब पार्टी बदलने से व्यवस्था में बदलाव नहीं आने वाला. आपके पास चुनने के नाम पर विकल्पों का अभाव है. यही सबसे बड़ी समस्या है. समाधान आपको ख़ुद ढूंढना है. तो तमाम, बुराइयों के बाद भी हमारे पास ख़ुश होने के लिए थोड़े ही सही, लेकिन कुछ कारण ज़रूर हैं. इसलिए, नए साल पर चौथी दुनिया की ओर से आप सभी को शुभकामनाएं.

shashishekhar@chauthiduniya.com

मनरेगा से जुड़े भ्रष्टाचार की ठुमरी और कजरी काफी समय से गांवों में सुनाई दे रही है. इसे संचालित करने वाले वही नौकरशाह हैं जो बिहार में चारा खा गए.

मनरेगा का काला सच

अमरेंद्र किशोर

बीते तीन सालों से तमाम आशंकाओं और अटकलों के बीच देश में ठीक-ठाक बारिश होती रही है. औसत बारिश का 78 प्रतिशत, जैसा कि विशेषज्ञ बताते हैं. दैनिक ज़रूरतों और दूसरे कामों के लिए हमें जितना पानी चाहिए, उससे दोगुनी मात्रा में पानी बरस कर जल- संकायों एवं धरती के गर्भ में जमा हो रहा है. वर्ष 2009 की सबसे अच्छी बात यह रही कि जब सौ सालों की अवधि में इस दौरान चौथा भयंकर सूखा पड़ने की आशंका बन रही थी तब सरकार राहत के लिए कमर कसकर तैयार थी. समूचे देश में तक़रीबन आठ लाख जल संकायों के पुर्नजीवन, निर्माण एवं उनकी मरम्मत का काम महात्मा गांधी नेशनल रूरल अप्वाइंटमेंट गारंटी एक्ट (मनरेगा) के ज़रिए चल रहा था तो सरकार इस बात से निश्चिंत थी कि पानी के बग़ैर लोग अपने गांवों से रोज़गार की तलाश में कहीं और नहीं जाएंगे. ऐसा ही हुआ और यह काम आज भी जारी है. यह देश के सेवा-प्रबंधन, परंपरागत जल संस्कृति, सामाजिक संतुलन एवं सार्वजनिक पानी की संभावनाओं को लेकर एक सुखद भविष्य के संकेत हैं.

ज़्यादा पुरानी बात नहीं है. पूरे देश में वर्षा जल संग्रह की एक बेहद मज़बूत संस्कृति थी, जो स्थानीय समाज के लिए गौरव और गरिमा की बात थी. लोगों के पास आहर था. पोखर और तालाब थे. इन्हीं से लोग पानी से जुड़ी हर ज़रूरत पूरी किया करते थे. लेकिन फिर अंग्रेज आए. आते ही देश में बर्बादी की नई परिभाषा गढ़ते चले गए. उन्होंने जोरिया-आहर-पोखर-तालाब और कच्चे कुंओं को आम जनता से दूर कर दिया. 60-70 साल में स्थानीय किसानों द्वारा बनाए गए चार हज़ार सालों के अभिक्रमों का गला घोंट दिया.

लेकिन साल 2006 से देश भर में नई तस्वीर उभर कर सामने आ रही है. घाल घोटालों से जूझते हुए भी मनरेगा के तहत जो काम चल रहे हैं, उससे क़रीब 20 लाख जल-संकायों का उज्जवल भविष्य देखा जा सकता है. इनमें झारखंड के कुछ जल संकाय भी हैं, जिनकी महिमा वहां के लोक गीतों से लेकर सर्वे सेंटलमेंट अधिकारी जॉन रिड की रिपोर्ट में भी दर्ज है.

यह जानकारी सर्वसुलभ है कि मनरेगा के ज़रिए गांव को सूखे से मुक्ति दिलाई जाएगी. हर ज़रूरतमंद को, जिसे रोज़गार की ज़रूरत है, उसे सौ दिन के रोज़गार की व्यवस्था मनरेगा योजना में है. उचित मज़दूरी और रोज़गार मिलने की वजह से गांवों के श्रमिक मनरेगा को स्वीकार कर रहे हैं. देश में चारों ओर मनरेगा लागू करना सरकार की जिद है और जनता को उसकी ओर से काम और रोज़गार दिए जाने का एक पक्का भरोसा भी है. उम्मीद है कि एक करोड़ हेक्टेयर ज़मीन मनरेगा के बूते सूखे से मुक्त हो सकेंगी, क्योंकि इन तालाबों-पोखरों में बारिश का 52.30 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी इकट्ठा होगा और धरती की कोख को तरावट भी मिलेगी. इस अनुमान से जुड़े आकड़ें अविश्वसनीय हैं. साथ ही सुखद भी. यह मामला गांवों के विकास का है और इसका सरोकार शहरों से नहीं है. इसीलिए शायद मनरेगा में शहरी बाबुओं का हस्तक्षेप भी नहीं है.

यह एक रोज़गारपरक कार्यक्रम है, जो गांव के समूचे आर्थिक तंत्र को मज़बूत करने के मिशन पर लगा है. खासतौर से उन लघु किसानों के जीवन में उम्मीदें भर रहा है, जो किसान देश के सकल घरेलू उत्पादन में 20 प्रतिशत का योगदान देते हैं.

जब-जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तब-तब देश में अनाज और पानी की कमी होती है. कुछ सालों के लिए देश में अन्न के भरपूर भंडार हैं और पानी की ज़रूरत मनरेगा के प्रयासों से पूरा किए जाने की दावेदारी है. इस स्थिति में हम सूखे और अकाल से लड़ने और जूझने में पूरी तरह सक्षम हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि जानकारों का कहना है कि भविष्य में लगातार दो मानसून भी दगा दे जाएं तो देश में न अनाज की कमी होगी और न ही रोज़गार की. मनरेगा के ज़रिए गांव से शहरों की ओर पलायन रोकने की कोशिश सरकार की है, ऐसा मानना है.

मगर हम आंकड़ों और इन दावेदारियों के कृष्ण पक्ष में भी जाना ज़रूरी समझते हैं. मनरेगा सूखे से मुक्ति, रोज़गार की उपलब्धता, जल संकायों के पुनर्निर्माण से लेकर आम आदमी के जीवन की हकदारी का एक व्यापक मिशन है. अभी 200 से कहीं ज़्यादा ज़िलों में इसके तहत ग्रामीण विकास की लोरियां गाई जा रही हैं और आने वाले तीन सालों में यह समूचे भारत में यह योजना लागू की जा सकेगी. सपनों की दुनिया बेहद रुपहली होती है, लेकिन यथार्थ की ज़मीन उससे कहीं ज़्यादा रूख़ी और पथरीली होती है.

मनरेगा से जुड़े भ्रष्टाचार की ठुमरी और कजरी काफी समय से गांवों में सुनाई दे रही है. इसे संचालित करने वाले वही नौकरशाह हैं जो बिहार में चारा खा गए और झारखंड में जंगलों और खदानों को बेच डाला. आज मनरेगा पर गांव के सामंतों का और समाज के बाहुबलियों का वर्चस्व होता जा रहा है. ग्राम्य स्वराज्य के नाम पर मुखिया सरपंच विकास का वैसा ही बंदरबांट कर रहे हैं, जैसा उन्होंने जवाहर रोज़गार योजना से लेकर जल-छाजन कार्यक्रम में किया. वर्षों से भ्रष्टाचार के सारथी बने सरपंचों का साहस इतना खुल चुका है कि वह उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले के कलमपुर प्रखंड के 31 गांवों में सड़क निर्माण के लिए जिन ट्रैक्टरों को मिट्टी ढोने के लिए उपयोग में ला रहे हैं, उन ट्रेक्टरों की नंबर प्लेट स्थानीय जनता की मोटर साइकिल में पाई गईं.

बिहार के चारा घोटालाबाज़ों ने स्कूटर पर गाय और भैंस ढोई थीं, अब उड़ीसा, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में मुखिया सरपंच बाइक पर मिट्टी ढो रहे हैं. नतीजतन अभी निर्धारित अवधि में लक्ष्य का 50 फ़ीसदी काम भी मनरेगा में पूरा नहीं किया जा सका है. 28 अगस्त 2010 तक मात्र 16 प्रतिशत जल संकायों से जुड़े काम हो सके हैं और अकाल से निपटने से जुड़े कार्यों का 10 प्रतिशत काम पूरा किया जा सका है. हालांकि योजना मद की राशि नियमित रूप से तेजी से ख़र्च की जा रही है. जितने काम पूरे भी किए गए हैं, उनसे कोई लाभ होता नहीं दिख रहा है. उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले में कुल 7981 काम किए जाने की योजना थी, जिनमें मात्र 29 योजनाएं पूरी होने की ख़बर है. इसके अलावा जो सबसे दुखद बात है, वह यह कि मनरेगा के कामों में मज़बूती नहीं है और पूरे किए गए कामों के टिकाऊपन को लेकर शक़ और आलोचनाओं की परछाइयां लगातार लंबी होती जा रही हैं. विशेषज्ञ बताते हैं कि जल-संग्रह से संबंधित कार्यों में 90 प्रतिशत की कोई उपयोगिता नहीं है.

1990 का दशक तमाम राजनीतिक दावेदारियों के बावजूद रोटी, कपड़ा और मकान के नाम लड़े गए संग्राम का एक हारा हुआ दशक था. विकास के नाम पर ग़रीबों के उद्धार के लिए जो काम हुए, उनसे लोगों की भूख ज़रूर शांत हुई लेकिन जीवन के हर स्तर पर असंतुलन एवं विद्रुपताएं बढ़ती चली गईं. लोगों में जागरूकता आई, लेकिन साथ ही साथ लोगों में अपने अधिकार को लेकर चिंताएं ज़्यादा गहराईं. साथ ही लोगों में कर्तव्यों को लेकर चिंतन की परंपरा ख़त्म होती चली गई. संसाधनों को हड़पने और मानवीय श्रम के दोहन का सिलसिला जारी रहा. नतीजतन, समाज में असंतोष गहराता चला गया. सुदूरवर्ती इलाक़ों में चल रहे लाल सलाम के कारोबार का भयंकर रूप इसी वजह से देखने को मिल रहा है. आज मनरेगा को भ्रष्टाचारियों से कहीं ज़्यादा लाल आंतक से ख़तरा है. नौकरशाही के शिकंजे में जा फंसे मनरेगा को नागरिक संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों, सहकारी संस्थाओं और स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जाना, इसीलिए ज़रूरी होता जा रहा है. मनरेगा में ऐसे प्रावधान भी हैं लेकिल शायद नौकरशाह ऐसा चाहते ही नहीं हैं. इसलिए करोड़ों ज़रूरतमंद लोगों तक मनरेगा का लाभ पहुंचाने की चुनौती ऐसी है, जिसके लिए लोगों को जनकेंद्रित भागेदारी प्रक्रियाओं से जोड़ना ज़रूरी है. ग़ैरसरकारी संगठनों, ज़मीनी स्तर पर सक्रिय समाजसेवियों, बुद्धिजीवियों, सार्वजनिक सुविधाओं तथा ग्रामीण विकास के प्रबंधकों का वैविध्यपूर्ण गठबंधन इस काम के लिए बहुत ज़रूरी है.

मनरेगा के ज़रिए जल-प्रबंधन में जुटी राज्य-व्यवस्था को पानी से जुड़े अन्य उपायों पर भी ध्यान देना होगा. इस देश का भला तब होता जब जल-छाजन कार्यक्रम को समेटने के बजाय इसे मनरेगा से जोड़ा जाता, साथ ही इसे नौकरशाहों के हस्तक्षेप से अलग रखा जाता. ध्यान रहे मनरेगा के ज़रिए हम आमजनों तक रोटी-रोज़गार पहुंचाना चाहते हैं. यह वोट की सौदागरी का कोई माध्यम नहीं है. मनरेगा राजनीतिक आकाओं के दुमछल्लों के रोज़गार तथा ऐशपरस्ती का साधन न बने, इस पर भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है.

feedback@chauthiduniya.com

पूरे देश में वर्षा जल संग्रह की एक बेहद मज़बूत संस्कृति थी, जो स्थानीय समाज के लिए गौरव और गरिमा की बात थी. लोगों के पास आहर था. पोखर और तालाब थे. इन्हीं से लोग पानी से जुड़ी हर ज़रूरत पूरी किया करते थे. लेकिन फिर अंग्रेज आए. आते ही देश में बर्बादी की नई परिभाषा गढ़ते चले गए.

शिवराज सिंह चौहान द्वारा छेड़ी गई बहस के बीच राज्यसभा के जन्मकाल की चर्चा भी ज़रूरी है. इससे पता चलेगा कि यह कितना ज़रूरी और औचित्यपूर्ण है तथा आज हो क्या रहा है.

ग़लत समय पर सही बहस

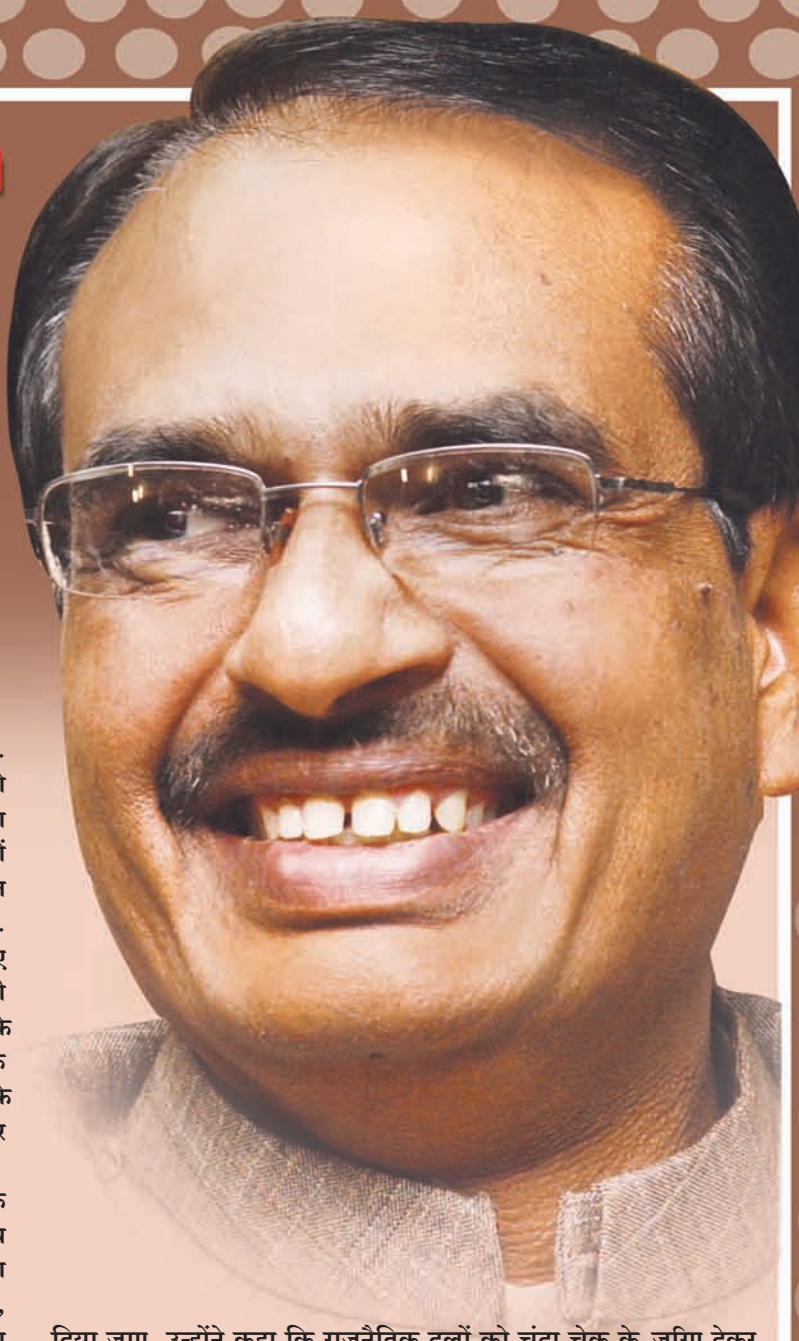

राजीव रंजन तिवारी

भले ही मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सभा के औचित्य के सवाल पर दिया गया अपना बयान वापस ले लिया है, फिर भी इस पर बहस तो छिड़ ही गई है. जिस तरह भारतीय राजनीति का अपराधीकरण, भ्रष्टाचारीकरण व आर्थिकीकरण हो रहा है, उसे देखकर शिवराज सिंह चौहान के बयान को अप्रासंगिक नहीं ठहराया जा सकता. हां, इतना ज़रूर कह सकते हैं कि उन्होंने ग़लत समय पर एक सही बहस छेड़ी है. ग़लत समय इसलिए, क्योंकि आए दिन उल्टे-सीधे बयान देकर नेताओं द्वारा सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वह विवादास्पद ही क्यों न हो. और सही बहस इसलिए, क्योंकि उन्होंने जिन मुद्दों को उठाया है, उसे सभी जानते हैं. भले वह संविधानसम्मत न हों, लेकिन व्यवहारिक तो है ही.

शिवराज सिंह चौहान द्वारा छेड़ी गई बहस के बीच राज्यसभा के जन्मकाल की चर्चा भी ज़रूरी है. इससे पता चलेगा कि यह कितनी ज़रूरी और औचित्यपूर्ण है तथा आज हो क्या रहा है. काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसे राज्यसभा भी कहा जाता है, एक ऐसा नाम है जिसकी घोषणा सभापीठ द्वारा 23 अगस्त 1954 को की गई थी. भारत में द्वितीय सदन का प्रारंभ 1918 के मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन से हुआ. भारत सरकार अधिनियम, 1919 में तत्कालीन विधानमंडल के द्वितीय सदन के तौर पर काउंसिल ऑफ स्टेट्स का सृजन करने का उपबंध किया गया, जिसका विशेषाधिकार सीमित था और जो वस्तुत: 1921 में अस्तित्व में आया. गवर्नर-जनरल तत्कालीन काउंसिल ऑफ स्टेट्स का पदेन अध्यक्ष होता था. भारत सरकार अधिनियम, 1935 के माध्यम से इसके गठन में शायद ही कोई परिवर्तन किए गए. संविधान सभा, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ने भी 1950 तक केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य किया, फिर इसे अनंतिम संसद के रूप में परिवर्तित किया गया. इस दौरान, केंद्रीय विधानमंडल जिसे संविधान सभा (विधायी) और आगे चलकर अनंतिम संसद कहा गया, 1952 में पहले चुनाव कराए जाने तक, एक-सदनी रहा. भारत में द्वितीय सदन की उपयोगिता के संबंध में संविधान सभा में विस्तृत बहस हुई. अंतत: एक द्विसदनी विधानमंडल बनाने का निर्णय इसलिए किया गया, क्योंकि परिसंघीय प्रणाली को अपार विविधताओं वाले इतने विशाल देश के लिए सर्वाधिक सहज स्वरूप की सरकार माना गया. अत: काउंसिल ऑफ स्टेट्स के रूप में ज्ञात एक ऐसे द्वितीय सदन का सृजन हुआ, जिसकी संरचना और निर्वाचन पद्धति प्रत्यक्षत: निर्वाचित लोकसभा से भिन्न थी. इसे एक ऐसा सदन समझा गया, जिसकी सदस्य संख्या लोकसभा (हाउस ऑफ पीपुल) से कम है. इसका आशय परिसंघीय सदन से था, जिसका निर्वाचन राज्यों और दो संघ राज्य क्षेत्रों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया गया. जिनमें राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया. राज्यसभा में सभा का नेता सामान्यत: प्रधानमंत्री होता है, यदि वह इसका सदस्य है, अथवा कोई ऐसा मंत्री होता है, जो इस सभा का सदस्य है और जिसे उनके द्वारा इस रूप में कार्य करने के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया हो. उसका प्राथमिक उत्तरदायित्व सभा में सौहार्दपूर्ण और सार्थक वाद-विवाद के लिए सभा के सभी वर्गों के बीच समन्वय बनाए रखना है. इस प्रयोजनार्थ, वह न केवल सरकार के बल्कि विपक्ष, मंत्रियों और पीठासीन अधिकारी के भी निकट संपर्क में रहता है. वह सभा-कक्ष (चैम्बर) में सभापीठ के दाईं ओर की पहली पंक्ति में पहली सीट पर बैठता है ताकि वह परामर्श हेतु पीठासीन अधिकारी को सहज उपलब्ध रहे.

राज्यसभा में वर्ष 1969 तक वास्तविक अर्थ में विपक्ष का कोई नेता नहीं होता था. उस समय तक सर्वाधिक सदस्यों वाली विपक्षी पार्टी के नेता को बिना किसी औपचारिक मान्यता, दर्जा या विशेषाधिकार दिए विपक्षी नेता मानने की प्रथा थी. बहरहाल, राज्यसभा के औचित्य पर उठाए गए सवाल पर हुई तीखी प्रतिक्रिया के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बैकफुट पर आकर स्पष्टीकरण देना पड़ा. चौहान ने निर्वाचन आयोग और विधि मंत्रालय द्वारा आयोजित चुनाव सुधारों के लिए क्षेत्रीय विचार-विमर्श कार्यक्रम में राज्यसभा को औचित्यहीन क़रार देते हुए कहा था कि सदस्यों के चुनाव के चलते विधायक ख़रीद फरोख्त की मंडी बन जाते हैं. चौहान के इस बयान से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई थी. इतना ही नहीं चौहान के बयान पर उनकी पार्टी के ही नेता असहमति जताने लगे थे. बयान पर बढ़ते विवाद के चलते चौहान ने देर रात को स्पष्टीकरण देना पड़ा. इसमें कहा गया कि उनकी चिंता विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा की गरिमा को बनाए रखने को लेकर है. जहां तक राज्यसभा की बात है वह संवैधानिक संस्था है और उसका वह सम्मान करते हैं. उन्होंने आगे कहा कि उनके बयान का अन्यथा अर्थ लगाया गया है तो उसके लिए वह क्षमा प्रार्थी हैं. दरअसल, उन्होंने कहा था कि राज्यसभा का गठन ब्रिटिश काल में संस्कृति और अन्य विषयों से जुड़े जानकारों को संसद में प्रतिनिधित्व देने के लिए किया गया था. उन्होंने सवाल उठाया कि वर्तमान दौर में इसे बरक़रार रखने का क्या औचित्य है. राज्यसभा को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि इसके सदस्य बनने के लिए बड़ी संख्या में राशि ख़र्च की जा रही है, जिससे संसद का यह ऊपरी सदन एक बाज़ार की तरह हो गया है. चौहान ने किंगफिशर कंपनी के मालिक विजय माल्या का परोक्ष रूप से उल्लेख करते हुए कहा कि किंगफिशर से लोग राज्यसभा में आ रहे हैं. माल्या के अन्य क्षेत्रों के अलावा शराब और उड्डयन उद्योग में व्यापारिक हित हैं. वे दूसरी बार राज्यसभा सांसद बने हैं.

भाजपा नेता ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, जो लोग ख़र्च करते हैं, एक तरह का निवेश करते हैं और इसे बाद में वे निकाल लेते हैं. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा में चुनाव सुधारों पर क्षेत्रीय परिचर्चा में कहा, मेरा मानना है कि समय आ गया है जब राज्यसभा को समाप्त कर दिया जाए, जिसके लिए प्रत्याशी मोटी राशि ख़र्च करते हैं. इसके स्थान पर राज्यसभा सदस्यों के लिए लोकसभा में ही कोटा निर्धारित कर दिया जाना चाहिए. राज्यसभा चुनाव के दौरान जो हालात दिखते हैं, उससे नेताओं की इज़्ज़त खाक में मिल जाती है. मेरा सुझाव है कि यदि समाज के प्रतिष्ठित लोगों की सदन में उपस्थिति ज़रूरी है, तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय की तरह इनके लिए भी सीटें तय कर दी जाएं. अंग्रेजों द्वारा बनाए गए उच्च सदन का उद्देश्य पवित्र था. एक समय इसमें बुद्धिजीवी और सम्मानित लोग हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है. जो कहीं से नहीं जीत पाते वे राज्यसभा में बैकडोर एंट्री ले लेते हैं. उन्होंने कहा कि चुनावों में काले धन पर अंकुश लगाने के लिए प्रत्याशियों के चुनाव पर ख़र्च की व्यवस्था स्टेट फंडिंग से होनी चाहिए. राष्ट्रपति प्रणाली के आधार पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव सीधे जनता के ज़रिए कराने की भी वकालत की. स्टेट फंडिंग के लिए केंद्र सरकार अपने बजट से 25 से 50 हज़ार करोड़ रुपये चुनाव आयोग को दे और वह इस राशि से उम्मीदवारों का चुनावी ख़र्च वहन करे. इसके बाद कोई एक पैसा भी ख़र्च करता है तो उसे अयोग्य घोषित करते हुए जीवन भर चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाए. उन्होंने कहा कि राजनैतिक दलों को चंदा चेक के ज़रिए देकर इसका ब्योरा वेबसाइट पर डाला जाए. ख़र्च का लेखा-जोखा सीएजी से कराया जाए. चौहान के उक्त विचार को व्यक्तिगत बताकर भाजपा ने पल्ला झाड़ लिया.

चौहान ने किंगफिशर कंपनी के मालिक विजय माल्या का परोक्ष रूप से उल्लेख करते हुए कहा कि किंगफिशर से लोग राज्यसभा में आ रहे हैं. माल्या के अन्य क्षेत्रों के अलावा शराब और उड्डयन उद्योग में व्यापारिक हित हैं. वे दूसरी बार राज्यसभा सांसद बने हैं. भाजपा नेता ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, जो लोग ख़र्च करते हैं, एक तरह का निवेश करते हैं और इसे बाद में वे निकाल लेते हैं. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा में चुनाव सुधारों पर क्षेत्रीय परिचर्चा में कहा, मेरा मानना है कि समय आ गया है जब राज्यसभा को समाप्त कर दिया जाए, जिसके लिए प्रत्याशी मोटी राशि ख़र्च करते हैं. इसके स्थान पर राज्यसभा सदस्यों के लिए लोकसभा में ही कोटा निर्धारित कर दिया जाना चाहिए.

शिवराज का बयान अप्रासंगिक नहीं है, इसका उदाहरण राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव 2010 को देखकर कहा जा सकता है. 12 राज्यों की 55 सीटों के लिए दो चरणों में चुनाव संपन्न कराए गए. इसमें 14 ऐसे सदस्य चुने गए जिनके ख़िलाफ़ आपराधिक मामले लंबित हैं. इनमें से छह सांसदों के ख़िलाफ़ हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, धोखाधड़ी और जालसाज़ी, भ्रष्टाचार जैसे संगीन मामले दर्ज हैं. इसे देख कह सकते हैं कि देश में प्रशासनिक सुधार और चुनाव सुधार की दुहाई देने वाले राजनैतिक दलों ने संसद के उच्च सदन राज्यसभा में दागियों का दामन थामना शुरू कर दिया है, जो अभी तक लोकसभा के चुनाव में ही दिखता रहा है. यानी राजनीतिक पार्टियां अपराधियों को अधिक तरजीह देती आ रही है, जिसका परिणाम है कि बुद्धिजीवियों की जगह आज राज्यसभा में दागियों की संख्या बढ़ने लगी है. कांग्रेस व भाजपा जैसे बड़े दल भी अपराधियों को गले लगाने में पीछे नहीं हैं, बल्कि उन्हें संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में लाने का काम कर रहे हैं. नेशनल इलेक्शन वॉच एवं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट बताती है कि राजनीति का अपराधीकरण तेजी से हो रहा है. इसके तहत कुछ सदस्यों की चर्चा भी की जा सकती है. इसमें राकांपा के महाराष्ट्र से निर्वाचित तारिक अनवर व ईश्वर लाल जैन के ख़िलाफ़ आपराधिक मामले लंबित हैं. इनके अलावा यूपी से बसपा के प्रो. एसपीएस बघेल, सपा के रशीद मसूद, बिहार से जदयू के उपेंद्र प्रसाद सिंह कुशवाह तथा राजद के रामकृपाल यादव, शिवसेना के महाराष्ट्र से संजय राउत, आंध्र प्रदेश से तेदपा की गुंडु सुधा रानी तथा कर्नाटक से निर्दलीय सांसद विजय माल्या दागियों में शामिल हैं. जिन पांच सांसदों पर संगीन अपराधों में मामले दर्ज हैं, उनमें शिवसेना के संजय राउत, तेदपा की गुंडु सुधा रानी, कांग्रेस के वी.हनुमंत राव, भाजपा के नंद किशोर साय तथा बसपा के प्रो.एसपीएस बघेल शामिल हैं. राज्यसभा में बढ़ते अपराधियों के ग्राफ पर यदि नज़र डाले तो इस समय 245 सदस्यों में से 41 सांसद आपराधिक प्रवृत्ति के मौजूद हैं. इन चुनाव से पहले यह संख्या 37 थी, जिसमें से कांग्रेस के संतोष बरगोडिया, जद-यू के डा.एजाज अली, राजद के सुभाष यादव तथा सपा के कमाल अख्तर और भगवती सिंह तथा एडीएमके के टीटीवी दीनाकरण का कार्यकाल समाप्त हो गया है, लेकिन इन्हीं संख्या में से संजय राउत, नंद किशोर साय, हनुमंत राव व तारिक अनवर ने फिर से निर्वाचित होकर वापसी की है. अब जहां छह दागियों की विदाई हुई है तो दस दागी उम्मीदवार नए सांसद के रूप में सदन में आए हैं. इस प्रकार राज्यसभा में कुल दागी सांसदों में कांग्रेस के दस, भाजपा आठ, बसपा के पांच, सपा के चार, सीपीएम के चार, शिवसेना के चार, जद-यू के तीन, सीपीआई के तीन, राजद का एक, तेदेपा का एक सदस्य है.

ख़ैर, राज्यसभा के मुद्दे पर शिवराज सिंह चौहान के बयान को विस्तृत नज़रिए से देखा जाना चाहिए. उस पर व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए. लगता है, वही देशहित में होगा. क्योंकि आज जो भी हो रहा है, उसके साइड इफेक्ट अच्छे नहीं होंगे.

feedback@chauthiduniya.com

देश की सबसे बड़ी आबादी की समस्याओं तथा आवश्यकताओं के अध्ययन एवं उनके कल्याण के लिए आयोग बनाने की ज़हमत उठाने की ज़रूरत का अहसास भी नहीं हुआ.

युवा आयोग बनाओ

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

नहीं तो भटक जाएगी युवाओं की फ़ौज

सरोज सिंह

पूरी दुनिया की एक चौथाई युवा आबादी भारत में बसती है. इस देश के दो–तिहाई से अधिक नागरिकों की औसत आयु सत्ताईस वर्ष से कम है. मानव संसाधन की अक्षय ऊर्जा से लबरेज यह भारतीय स्त्रोत विश्व की किसी भी महाशक्ति को ईर्ष्या पर उतारू होने को मजबूर कर सकता है. स्वभाविक भी है, युवा मन का उमंग असंभव को भी संभव के खांचे में ढ़ालने की क्षमता जो रखता है. तभी तो कहा गया है कि जवानी के जोश में आदमी पत्थर को भी पानी बना डालता है. जवां दिलों के जज़्बे के भरोसे ही बालू से तेल निकालने का अफसाना भी गढ़ा गया.

लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि कि भारत अपनी इस सबसे बड़ी संपदा का समुचित उपयोग नहीं कर पा रहा है. बल्कि, यह सबसे बड़ी ताक़त ही, इसके गले की हड्डी बनती जा रही है. दिग्भ्रमित युवा शक्ति देश के लिए अभिशाप का स्वरूप अख्तियार कर रही है. इसकी लक्ष्यविहीन हलचल समाज के बीच जलजले का अहसास करा देती है. मसलन कश्मीर में पत्थरबाज़ युवकों का हिंसक प्रतिरोध, उग्र वामपंथ से प्रभावित युवा चरमपंथियों का लाल आतंक, मुंबई में राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के रंगरूटों का प्रवासियों पर प्रहार, इंडियन मुजाहिद्दीन एवं सिमी के ख़ौफ़नाक कारनामे तथा उत्तर–पूर्व के पर्वतीय प्रदेशों में अलगाववादी शक्तियों की सबसे बड़ी ताक़ त वहां के युवाओं की कुंठा ही है. इस हीनभावना को दूर करने की मंशा का सर्वथा अभाव नीति–निर्धारकों में दिखता है. असीम संभावनाओं वाले इस संसाधन को देश की मुख्यधारा से जोड़ने की सार्थक पहल का भी घोर अभाव नज़र आता है. मानो सिवाए ज़ुबानी लफ्फाजी के अलावा कोई भी ठोस क़दम न उठाने की कसम खा रखी हो. कांग्रेस के सर्वशक्तिमान नेता राहुल गांधी भी बुराड़ी के कांग्रेस महाधिवेशन में भारत की युवा आबादी के रूप में मौजूद मानव संसाधन के विशाल भंडार के सदुपयोग करने की बात को काफी संजीदगी से उठाते हैं. वह मानव संसाधन के इस अतुलनीय स्त्रोत को इस युग का ईंधन क़रार देते हैं, इसे विकास के इंजन से जोड़ने की ज़रूरत को भी रेखांकित करते हैं. वह मानते हैं कि अगर इस वर्ग को मौक़ा नहीं मिला तो यह बोझ बन जाएगा. लेकिन युवा वर्ग के एक बड़े तबके में राहुल गांधी के प्रति भी असंतोष के भाव परिलक्षित होने लगे हैं. इन लोंगो की राय है कि विगत छह साल से राहुल गांधी देश और सरकार की दशा–दिशा तय करने में सक्षम हैं, लेकिन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी युवाओं के लिए कोई समग्र नीति नहीं बनवा पाए हैं. देश की सबसे बड़ी आबादी की समस्याओं तथा आवश्यकताओं के अध्ययन एवं उनके कल्याण के लिए आयोग बनाने की ज़हमत उठाने की ज़रूरत का अहसास भी नहीं हुआ. जबकि जाति और संप्रदाय के आधार पर कई आयोग बन गए. बिहार प्रदेश युवक कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष ललन कुमार के अनुसार कांग्रेस ही युवाओं की सबसे बड़ी शुभचिंतक है. पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अठारह वर्ष के युवाओं को मताधिकार प्रदान कर नए युग के शुभारंभ का संकेत दिया था. वहीं राहुल गांधी ने पार्टी के युवा एवं छात्र इकाई में लोकतंत्र स्थापित कर युवा राजनीति को नया आयाम दिया है. कांग्रेस युवाओं के हक़ एवं न्याय के लिए संघर्षरत रहने को कृतसंकल्पित है. इसके नेतृत्व में नई पीढ़ी के उत्थान एवं कल्याण के लिए निश्चय ही भविष्य में युवा आयोग एवं युवा नीति भी बनाया जाएगा. हालांकि, भायुजमो के महामंत्री एंव विधायक नितिन नवीन युवा आयोग की आवश्यकता को ही बेमानी क़रार देते हैं. वह कहते हैं कि आयोग तो दबे हुए तबके के लिए बनाया जाता है. युवा वर्ग तो आगे आकर नेतृत्व करता है. वह भी युवाओं की दुर्दशा के लिए कांग्रेस को दोषी मानते हैं. कांग्रेस ने देश में पांच दशक तक शासन किया है. इस दौरान युवा वर्ग को सिर्फ़ मुलम्मा देकर ठगती रही है. नितिन नवीन कांग्रेस दिग्गज राहुल गांधी पर भी प्रहार करते हैं. कॉलेज, विश्वविद्यालयों में छात्र–छात्राओं से बुके लेकर वह यूथ आइकॉन बनते हैं, लेकिन संसद में एक बार भी युवाओं के मुद्दे पर उन्होंने अपनी ज़ुबान नहीं खोली. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष के जे जोसमन इस अवधारणा से इत्तेफ़ाक़ नहीं रखते. वह दावा करते हैं कि युवाओं की समस्याओं का समग्र अध्ययन एवं उन्हें मुख्य धारा में लाए बग़ैर देश तरक़्क़ी नहीं कर सकता है. जोसमन लगातार युवा वर्ग के मुद्दों पर सवाल उठाते रहे हैं. उनके अनुसार युवा आयोग, राष्ट्रीय युवा विकास परिषद गठित कर एवं उन्हें स्वरोज़गार के साधन उपलब्ध करवाकर ही इस वर्ग को देश की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है. बिहार में युवा नीति एवं बेरोज़गारी भत्ते के सवाल पर लगातार संघर्ष करने वाले लोजपा के महासचिव रोहित कुमार सिंह की राय में इस तबके का सिर्फ़ इस्तेमाल किया जाता है. इसके कल्याण के लिए समग्र सोच का घोर अभाव है. जातिगत आयोग के गठन के लिए होड़ मची है. लेकिन जाति–संप्रदाय की संकीर्ण भावना से मुक्त युवा समुदाय इस दौड़ में उपेक्षित है. कोई भी शासनाधीश इसके प्रति ज़िम्मेदारी निर्वाह करने को उत्सुक नहीं है. हिंदी पट्टी के राज्यों उत्तर प्रदेश एवं बिहार में दशकों से छात्र संघ का चुनाव तक नहीं करवाया जा रहा है. राहुल गांधी युवाओं को राजनीति में आगे आने की लगातार अपील करते हैं. लेकिन छात्र–युवा की प्रथम राजनीतिक पाठशाला पर ही ताला लटका दिया गया है. विडंबना है कि बिहार में विगत दो दशक से छात्र राजनीति के सूरमा रहे लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी सत्ता के सूत्रधार बने हुए हैं. जदयू के युवा नेता छोटू सिंह इसे झुठलाते हुए कहते हैं कि पूरे देश में सिर्फ़ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही युवा के आशा के एकमात्र केंद्र हैं. उन्होंने बिहार में नई क्रांति का सूत्रपात कर दिया है. यही कारण है कि बिहार के युवाओं ने उन्हें पुन: गद्दी पर बिठाया. इनकी स्कूली विद्यर्थियों को साइकिल प्रदान करने की योजना भावी युवा के सशक्तिकरण का ही प्रतीक है. जदयू के दिग्गज के दावों की कलई खोलते हुए रांकापा के युवा नेता उपेंद्र यादव कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को युवाओं की चिंता होती तो वह बिहार में बंद बेरोज़गारी भत्ते को शुरू करवाते. यहां का नियोजनालय तक ठप्प है. नीतीश कुमार पुन: मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने के बाद अपने जातीय वोट बैंक की मज़बूती के लिए स्वर्ण आयोग तो बना रहे हैं, लेकिन युवा आयोग बनाने के लिए जहमत उठाना उन्हें गंवारा नहीं है.

ग़ौरतलब है कि देश में युवाओं की सबसे बड़ी तादाद है. विश्व का यह सबसे युवा देश है. लेकिन अंतरराष्ट्रीय खेलों में यह फिसड्डी रह जाता है. एक अरब से अधिक आबादी वाला यह देश ओलंपिक खेल में एक पदक के लिए भी तरस जाता है. हाल ही में संपन्न ग्वांगझू एशियाई खेल में भी भारत कई छोटे राष्ट्र से काफी पीछे छूट गया. युवा देश के इस थके हुए प्रदर्शन के लिए यहां की युवा प्रतिभा ज़िम्मेदार नहीं है. बल्कि, विभिन्न सरकारों का युवाओं एवं खेलों के प्रति दोयम दर्जे के व्यवहार के कारण नैसर्गिक प्रतिभा भी कुंठित होकर रह जाती है. वजह है, देश का युवा एवं खेल मामलों का मंत्रालय हाथी का दांत है. केंद्र सरकार में प्रशासनिक सेवा से रिटायर अधिकारी एम एस गिल को इस मंत्रालय का ज़िम्मा दिया गया है. कांग्रेस में युवा ब्रिगेड की लंबी–चौड़ी फौज होने के बावजूद इस बुज़ुर्ग को यहां बिठाना युवाओं के प्रति उनकी घातक लापरवाही को ही दर्शाता है. ऐसा भी नहीं है कि एम एस गिल का खेल के प्रति कोई विशेष लगाव है. हाल ही में ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार के कोच के साथ उनका शर्मनाक व्यवहार सुर्ख़ियों में रहा था. केंद्र सरकार में ही नहीं, राज्य सरकारों का रुख़ भी इससे इतर नहीं है. बिहार में वर्ष 2005 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार गठन के बाद इस विभाग की ज़िम्मेदारी जनार्दन सिंह सिग्रिवाल को दी गई थी. तब वह काफी कम संसाधन में अपनी कार्यकुशलता के बूते नीतीश सरकार के सफल मंत्रियों में गिने जाते थे. लेकिन वह भी राजनीति के शिकार हो गए. मंत्रीपरिषद के फेरबदल में उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. इसके बाद रेणु देवी और चुनावोपरांत सुखदा पांडेय जैसी बुज़ुर्ग महिला विधायक को इस विभाग का प्रभार दिया गया. स्वाभाविक है कि इस परिस्थिति में बेहतर परिणाम की अपेक्षा करना बेमानी है.

सच ही कहा गया है कि जिस ओर जवानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है. लेकिन देश के नेताओं को इसकी दिशाहीनता की कोई फ़िक्र नहीं है.

feedback@chauthiduniya.com

पूरे देश में नीतीश कुमार ही युवाओं के लिए आशा के एकमात्र केंद्र हैं. उन्होंने बिहार में नई क्रांति का सूत्रपात कर दिया है. यही कारण है कि बिहार के युवाओं ने उन्हें पुन: गद्दी पर बिठाया.इनकी स्कूली विद्यर्थियों को साइकिल प्रदान करने की योजना भावी युवा के सशक्तिकरण का ही प्रतीक है. –छोटू सिंह

युवाओं की समस्याओं का समग्र अध्ययन और उन्हें मुख्य धारा में लाये बगैर देश तरक्की नहीं कर सकता है. युवा आयोग, राष्ट्रीय युवा विकास परिषद गठित कर एवं उन्हें स्वरोज़गार के साधन उपलब्ध करवाकर ही इस वर्ग को देश की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है.
–के.जे. जोसमन

उत्तर प्रदेश एवं बिहार में दशकों से छात्र संघ का चुनाव तक नहीं करवाया जा रहा है. राहुल गांधी युवाओं को राजनीति में आगे आने की लगातार अपील करते हैं. लेकिन छात्र–युवा की प्रथम राजनीतिक पाठशाला पर ही ताला लटका दिया गया है.
–रोहित कुमार सिंह

कांग्रेस ही युवाओं की सबसे बड़ी शुभचिंतक है. कांग्रेस युवाओं के हक एवं न्याय के लिए संघर्षरत रहने को कृतसंकल्पित है. इसी के नेतृत्व में नई पीढ़ी के उत्थान के लिए युवा आयोग और युवा नीति भविष्य में निश्चित बनाई जाएगी.
–ललन कुमार

विकीलीक्स के गोपनीय दस्तावेजों का स्रोत अमेरिकी रक्षा विभाग के नेटवर्क सिप्रनेट को माना जाता है.

विकीलीक्स की दुनिया

विकीलीक्स का नाम सुनते ही कई बातें दिमाग़ में घूमने लगती हैं. क्या यह इंटरनेट का आतंकवाद है. क्या विकीलीक्स को चलाने वाले अमेरिका के दुश्मन हैं या फिर क्या यह अमेरिकी ख़ुफ़िया एजेंसी के सीआईए या इजराइल के मोसाद की करतूत है. क्या यह नए ज़माने की पत्रकारिता का एक रूप है. ये खुलासे क्या हैं. इन खुलासों की सच्चाई क्या है. इन खुलासों का मतलब क्या है. जिस देश या जिन नेताओं केख़िलाफ़ खुलासे हो रहे हैं, वे इन खुलासों का खंडन क्यों नहीं करते हैं. क्या विकीलीक्स के सारे खुलासे सौ फ़ीसदी सच हैं. विकीलीक्स से जुड़ी तमाम जानकारी हम अपने पाठकों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं.

रीतिका सोनाली

नसनीखेज़ ख़ुलासों से दुनिया को हिला देने वाली विकीलीक्स, एक वेबसाइट है. यह अंतरराष्ट्रीय मीडिया संगठन है, जिसका घोषित तौर पर कोई मुख्यालय नहीं है. यह ऑस्ट्रेलिया में लाइब्रेरी के तौर पर, फ्रांस में फाउंडेशन केतौर पर और स्वीडन में अख़बार के तौर पर रजिस्टर्ड है. यह गुप्त दस्तावेजों को सामने लाने में माहिर है. यह दुनिया के तमाम देशों, उनकी सरकारों और नीतियों संबंधित ख़ुफ़िया जानकारियों को सार्वजनिक करता है. विकीलीक्स वेबसाइट साल 2006 में लांच हुई. यह वेबसाइट, द सनशाइन प्रेस द्वारा संचालित है. इसकी शुरुआत कई देशों के तकनीकी विशेषज्ञों ने मिल कर की. इनमें कुछ पत्रकार हैं तो कुछ गणितज्ञ. विकीलीक्स वेबसाइट से चीन, अमेरिका, ताइवान, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों के लोग जुड़े हैं. इसका असल मालिक कौन है, इसका प्रबंधन किसके हाथों में है यह एक रहस्य है. ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेट एक्टिविस्ट जूलियन असांजे का दावा है कि वो इस वेबसाइट केसंस्थापक हैं, जबकि इसी संस्था से जुड़े डैनियल डॉम्सी बर्ग का कहना था कि वह इस वेबसाइट के संस्थापक हैं. हालांकि, नवंबर 2010 में डैनियल ने विकीलीक्स को छोड़कर इसी के अनुरुप नई वेबसाइट ओपनलीक्स शुरू की. तब से जूलियन असांजे को ही विकीलीक्स का संस्थापक माना जाता है.

यह वेबसाइट कैसे संचालित होती है

विकीलीक्स ने हाल में ढाई लाख गोपनीय दस्तावेज का पर्दाफाश कर खलबली मचा दी. इन सबको दस्तावेजों को केबल कहते हैं या फिर लीक्स के नाम से हम जानते हैं. इन खुलासों से सबसे ज़्यादा नुक़सान अमेरिका का हुआ है. विकीलीक्स उन जानकारियों को सार्वजनिक कर रहा है जिसे अलग-अलग अमेरिकी दूतावासों ने अपनी सरकार को भेजे हैं. इन जानकारियों से अमेरिका की सरकार शर्मसार हुई है और विकीलीक्स को अमेरिका और शांति का दुश्मन बताया. विकीलीक्स का यह पहला खुलासा नहीं है. इराक युद्ध, अफगान युद्ध से जुड़े कई गुप्त दस्तावेजों को सार्वजनिक कर चुका है. इस वेबसाइट के निशाने पर दुनिया भर के देश और राजनायिक हैं, इसलिए इस बेवसाइट को तबाह करने की कई बार कोशिशें हुई हैं. लेकिन विकीलीक्स को चलाने वाले लोग इतने तेज़ हैं कि आज तक इस बेबसाइट की सुरक्षा को कोई भेद नहीं सका. इसकी वजह यह है कि यह एक मल्टीसर्वर पर अलग-अलग डोमेन नेम से उपलब्ध है. विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे का कहना है कि वेबसाइट के सर्वर स्वीडन केअलावा उन देशों में ही मौजूद हैं, जो इसकेखुलासे को क़ानूनी सुरक्षा देते हैं. स्वीडन का क़ानून वहां की प्रशासनिक व्यवस्था को किसी अख़बार के स्त्रोत के बारे में जानकारी लेने की अनुमति नहीं देता है. यह क़ानून विकीलीक्स को इंटरनेट पर बने रहने में मदद करता है.

विकीलीक्स के गोपनीय दस्तावेज़ों को कहां छुपा रखता है, यह रहस्य अबतक अनसुलझा है. उसकी वजह बुलेटप्रूफ होस्टिंग है. इसका मतलब यह है कि विकीलीक्स गोपनीय स्थानों पर सर्वर बनाता है, जिसमें सारे दस्तावेजों को रखा जाता है. और इंटरनेट पर किसी रिकॉर्ड को नहीं रखता है. विकीलीक्स मीडियाविकी, फ्रीनेट, टोर और पीजीपी जैसे सॉफ्टवेयर पर काम करता है. वेबसाइट सबसे ज़्यादा टोर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती है, क्योंकि इस पर यूजर्स की प्राइवेसी की सुरक्षा अन्य के मुकाबले ज़्यादा है.

विकीलीक्स का ख़र्च

इस वेबसाइट के संचालन का सालाना ख़र्च 2 लाख यूरो, एक करोड़ 17 लाख रुपया है. विकीलीक्स से 500 कर्मचारी जुड़े हुए हैं. इसके अलावा दुनिया भर में आठ सौ कर्मचारी फैले हैं, जिन्हें वेतन नहीं दिया जाता है. अगर उन्हें वेतन दिया जाए तो इसका सलाना ख़र्च 6 लाख यूरो यानी साढ़े तीन करोड़ रुपये से ज़्यादा आएगा. यह वेबसाइट केवल चंदे के पैसे से चलती है. विकीलीक्स को जो पैसा दान में मिलता है वह जर्मनी के वाउ होलैंड फाउंडेशन के ज़रिए आता है. ये पैसा कौन देता है यह पता नहीं चल पता है, क्योंकि जर्मनी के क़ानून केअनुसार यह ऑर्गनाइजेशन चालू फर्म नहीं है और इसलिए इसके दानकर्ताओं के नाम का खुलासा करने की ज़रूरत नहीं होती है. इस तरह दानकर्ताओं का पैसा सुरक्षित रहता है. विकीलीक्स के दो टैक्स फ्री चैरिटेबल संस्थान अमरीका में हैं, जो वेबसाइट केलिए सुरक्षा पटल का काम करती हैं. जनवरी 2010 में पे पाल यानी ई कॉमर्स बिजनेस में इंटरनेट के ज़रिए होने वाले मनी ट्रांसफर ने विकीलीक्स के डोनेशन अकाउंट को सीज कर

शर्मिंदा करने वाली टिप्पणियां

विकीलीक्स वेबसाइट ने ऐसे-ऐसे गोपनीय संदेशों का पर्दाफ़ाश किया, जिसके चलते अमेरिका दूसरे देशों से नज़र नहीं मिला सकता:

- मॉस्को स्थित अमेरिकी राजदूतों ने रूस के पूर्व राष्ट्रपति व्लादिमीर पूतिन को अल्फ़ा कुत्ते की संज्ञा दी थी.
- जर्मनी की चांसलर एंगेला मरकेल के बारे में ख़ुलासा किया गया कि अमेरिका की नज़र में वो हमेशा ख़तरों से बचना चाहती हैं और उनमें रचनात्मकता की काफ़ी कमी है.
- फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोज़ी को पतली खाल वाला सत्तावादी नेता बताया गया.
- इटली के प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी को अमेरिकी गोपनीय संदेशों में कमज़ोर और बेअसर बताया गया.
- अफ़ग़ानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करज़ई के बारे में बेहद कमज़ोर, भ्रम से पीड़ित और षडयंत्रकारी नेता बताया गया.
- वहीं लीबिया के नेता कर्नल मुअम्मर ग़द्दाफ़ी को हमेशा आकर्षक महिलाओं के संपर्क में रहने का आदी बताया गया.
- विकीलीक्स के ख़ुलासे में चीन पर आरोप लगाया गया है कि उसके नेताओं ने इंटरनेट कंपनी गूगल के ख़िलाफ़ कंप्यूटर हैकिंग का अभियान चलाया था.

क्या है गोपनीय दस्तावेज़ों का स्रोत

विकीलीक्स के गोपनीय दस्तावेजों का स्रोत अमेरिकी रक्षा विभाग के नेटवर्क सिप्रनेट को माना जाता है. सिप्रनेट यानी सीक्रेट इंटरनेट प्रोटोकॉल रॉइटर. इस नेटवर्क को 9/11 हमले के बाद गोपनीय जानकारियों के आदान-प्रदान के लिए बनाया गया था. अमेरिका के क़रीब 25 लाख सैनिक और असैनिक कर्मचारी इससे जुड़े हैं. इसकी सिक्योरिटी ज़बरदस्त है. इसे सामान्य इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ना मना है. अमेरिका के ज़्यादातर दूतावास सिप्रनेट से जुड़े हैं. माना जा रहा है कि ये सारे गोपनीय दस्तावेज अमेरिकी सेना के ख़ुफ़िया विशेषज्ञ ब्रैडली मैनिंग ने विकीलीक्स वेबसाइट तक पहुंचाए हैं. साथ ही, अफ़ग़ान-इराक में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई से जुड़ी कई तस्वीरें भी उपलब्ध करवाईं, जिसमें स्थानीय लोगों की मौत होते दिखाया गया था. इससे पहले विकीलीक्स के गोपनीय दस्तावेजों का स्रोत टोर नेटवर्क के माध्यम से चाइना के हैकरों को बताया गया था. लेकिन असांजे ने बाद में इन ख़बरों का भी खंडन कर दिया था. ख़ुलासे दर ख़ुलासे कर असांजे ने दुनिया को हैरान तो किया लेकिन अपने लिए मुश्किलें मोल ली.

भारत से जुड़े विकीलीक्स के खुलासे

- आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी की हत्या की साज़िश रची थी.
- मुंबई में 26/11 हमले के बाद आतंक के ख़िलाफ़ लड़ाई में अमेरीका ने भारत का साथ नहीं दिया, क्योंकि भारत की जांच एजेंसियों पर उसे भरोसा नहीं था.
- भारतीय पुलिस और जांच एजेंसियां अपराध और आतंक से लड़ने में अक्षम हैं. भारतीय पुलिस पूछताछ के लिए अमानवीय तरीका अपनाती है.
- दिल्ली पुलिस में विदेशी जासूस की घुसपैठ.
- राहुल गांधी ने अमेरिकी राजदूत टिमोथी जे. थोमर से कहा था- भारत के लिए हिंदूवादी संगठन इस्लामिक संगठनों से ज़्यादा ख़तरनाक हैं.
- अमेरिका ने भारतीय सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की थी. अमरीकी अधिकारियों ने स्पेशल सेल यानी एंटी टेरर सेल के तहक़ीक़ात के तरीकों के बारे में जानना चाहा था.
- जिहादी संगठन जैविक हथियारों का इस्तेमाल कर भारत पर हमला कर सकते हैं.
- आतंकी डेविड हेडली के मन में भारत के लिए नफ़रत है. उसने कहा था कि अमेरिका क़बूलनामे की ख़बर भारत को देगा तो वो जांच में सहयोग नहीं करेगा.
- आतंकी हेडली से पूछताछ मामले पर गृह मंत्री चिदंबरम ने अमरीकी राजदूत से गुज़ारिश की थी. कहा था कि हमें पूछताछ करने दीजिए, ताकि हम अपने नागरिकों को कम से कम आश्वासन दे सकें.
- परमाणु करार मुद्दे पर लेफ्ट पार्टियों के विरोध का सामना करने में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अक्षम बताया गया.
- अमरीका ने मुंबई हमलों में पाकिस्तानी जांच एजेंसियों की मिलीभगत से जुड़ी जानकारियों को दबाने का प्रयास किया था.
- ईरानी राष्ट्रपति महमूद अहमदीनिजाद के भारत दौरे से गुस्साए अमेरिका को भारतीय विदेश सचिव शिवशंकर मेनन ने शांत करने की कोशिश की थी. मेनन ने अमेरीकी विदेश सचिव मलफर्ड से कहा था कि अमेरिका खुलेआम भारत को सलाह न दे.

असांजे का हेडक्वार्टर

विकीलीक्स के कुछ सर्वर स्वीडन के स्टॉकहोम में अंडरग्राउंड गुफ़ानुमा ढांचे में बने हैं. इसे पायनेन व्हाइट माउंटेन डाटा सेंटर कहा जाता है. इतिहास में इस सेंटर को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान स्वीडन के प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया था, ताकि स्टॉकहोम पर हाइड्रोजन बम गिरने पर इन्हें बचाया जा सके. इसके इंटीरीयर को ऑर्किटेक्चर्स ने 1960 में फिर से डिजाइन किया, लेकिन पूरी तरह विकसित नहीं किया जा सका. असांजे ने स्वीडन के क़ानून की आड़ लेते हुए इस जगह को चुना और न्यूक्लियर बंकर के तौर पर कोल्ड वॉर में इस्तेमाल होने वाली इस जगह को अपने सर्वर के सीक्रेट्स को सुरक्षित रखने के लिए चुना. असांजे के इस ड्रीम ऑफिस को बैंहॉफ कंपनी ने अल्बर्ट फ्रांस और लैनोल्ड आर्किटेक्ट्स की मदद से तैयार किया था. इन्होंने इस डाटा सेंटर को जेम्स बांड की फिल्मों के सेट से प्रेरित होकर रिडिजाइन किया. इस तरह के सेटअप को परमाणु हथियारों की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है. डाटा सेंटर की बात करें तो इस 1200 वर्गमीटर सेंटर की ज़मीन से 30 मीटर यानी सौ फुट नीचे स्टॉकहोम के बीटा बर्ग पार्क के सख्त पत्थरों को काट कर बनाया गया है. इस डाटा सेंटर में लगे ग्रेनाइट बम ब्लास्ट को झेलने की ताक़त रखते हैं. यदि इस सेंटर के ठीक बाहर बम धमाका हो जाए, तब भी इसे कोई नुक़सान नहीं पहुंचेगा. डाटा सेंटर में बना लूनर लैंडस्केप फ्लोर इसका कार्यक्षेत्र है, जिसे डिजाइनर रॉक कंम्प्यूटिंग फर्नीचर से सजाया गया है. कम जगह घेरने के मक़सद से यहां केडाटा सेंटर के ऊपर कांच का फ्लोटिंग कांफ्रेंस रूम बनाया गया है. ज़मीन से नीचे होने की वजह से यहां का वातावरण भी काफ़ी अलग है. इसे नियमित रखने के लिए दीवार के एक ओर हरे पौधों की पंक्ति है, तो दूसरी तरफ़ वॉटर बॉडी. इस हाइटेक सेंटर में सोलर लाइटिंग और ह्यूमीडिटीफायर मशीन लगाई गई है. सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी को अंदर आने से रोकने केलिए यहां सिर्फ़ एक ही प्रवेश द्वार है, जिसमें आधे गज की मोटाई वाला मज़बूत धातु का दरवाजा लगा है. इस डाटा सेंटर में इमरजेंसी पावर बैक अप के लिए पनडुब्बियों में लगने वाला जर्मन डीजल इंजन बैक-अप जेनेरेटर के तौर पर लगा है. विकिलीक्स के हज़ारों दस्तावेज इस डाटा सेंटर के 250 टर्मिनल में सुरक्षित रखे हैं.

आलोचनाएं भी, प्रशंसाएं भी

असांजे के किए ख़ुलासों की वजह से जहां एक ओर उसकी आलोचानाएं हो रही हैं, वहीं प्रशंसाएं भी मिली हैं. साल 2008 में द इकोनॉमिक्स ने विकिलीक्स को न्यू मीडिया अवार्ड दिया. 2009 में एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से यूके मीडिया अवार्ड दिया गया. तो 2010 में न्यूयॉर्क सिटी के डेली न्यूज ने विकीलीक्स का नाम दैट कुड टोटली चेंज द न्यूज में शामिल किया गया. इसके अलावा असांजे को 2010 में टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाज़ा. विकिलीक्स के समर्थकों ने असांजे की ख़ूब वाहवाही की. वहीं अमेरीकी सरकार ने विकीलीक्स को इसे राष्ट्रीय सुरक्षा पर आघात करने और दूसरे देशों से राजनीतिक संबंधों पर आहत पहुंचाने का आरोप लगाया. अमेरिकी उप राष्ट्रपति ने असांजे को एक हाइटैक आतंकी करार दिया.

असांजे स्वीडन क्यूं नहीं जाना चाहते

असांजे को स्वीडन में प्रेस की आज़ादी मिली. स्वीडन से ही उन्होंने अपने मंसूबों को अंजाम देने की शुरुआत की. लेकिन असांजे का कहना है कि अब अगर वो स्वीडन जाते हैं तो वहां का क़ानून उनपर पाबंदी लगाएगा और यहां तक की उनके वकील से भी मिलने से रोका जाएगा. वहीं असांजे स्वीडन में दो महिलाओं द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप को बेबुनियाद बताते हैं. जूलियन असांजे को ब्रिटिश पुलिस ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के चलते गिरफ्तार किया था. लेकिन फिर वहां की अदालत ने उन्हें जुर्माने के साथ सशर्त ज़मानत दे दी. असांजे ने कहा कि दुनिया से न्याय ख़त्म नहीं हुआ है और उनकी ज़मानत इस बात का सबूत है. उन्होंने कहा कि सच के ख़ुलासे जारी रहेंगे जो बदस्तूर जारी हैं.

ritika@chauthiduniya.com

विकीलीक्स के ख़ुलासों से जुड़े कुछ अहम तथ्य

- दिसंबर 2006- सोमालिया से संबंधित विकीलीक्स ने पहला डॉक्यूमेंट पोस्ट किया.
- सितंबर 2008 - अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव प्रचार के दौरान सारा पालिन ने कुछ संदेश भेजने केलिए याहू का प्रयोग किया.
- जनवरी 2009 - संयुक्त राष्ट्र की 600 आंतरिक रिपोर्ट का ख़ुलासा
- जनवरी 2009 - यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंजिलिया के एक विवादास्पद दस्तावेज़ का ख़ुलासा.
- 19 मार्च 2009 - विभिन्न देशों की कई ग़ैरक़ानूनी साइट्स की प्रतिबंधित सूची का पर्दाफ़ाश.
- 28 जनवरी 2009 - पेट्रोगेट ऑयल स्कैंडल से जुड़ी पेरू के राजनेताओं और बिजनेसमैन के बीच हुई बातचीत का ख़ुलासा.
- 16 जनवरी 2009 - ईरान की परमाणु सामग्री संबंधी नीति का ख़ुलासा
- 25 नवंबर 2009 - पेंटागन अधिकारियों और न्यूयॉर्क सिटी पुलिस विभाग के बीच संदेश का ख़ुलासा
- 25 जुलाई 2010 - अफ़ग़ान युद्ध से संबंधित 92 हज़ार गोपनीय दस्तावेज जारी किए गए.
- अक्टूबर 2010 - इराक युद्ध से संबंधित चार लाख गोपनीय दस्तावेज जारी किए गए
- 22 अक्टूबर 2010 - अल जजीरा ने पहली बार इस ख़ुलासे का विश्लेषण किया.
- 15 मार्च 2010 - अमेरिकी रक्षा विभाग की ख़ुफ़िया रिपोर्ट का ख़ुलासा.

पायनेन व्हाइट माउंटेन डाटा सेंटर

दुर्भाग्य से यदि बिहार की कहानी एक बार फिर दोहराई तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कहीं की भी नहीं रहेगी.

हिंदू राजा भी हिंदू किसानों का शोषण करते थे. और यदि मुस्लिम राजा, हिंदू कृषकों का ख़ून चूसते थे तो उसका कारण यह नहीं था कि किसान हिंदू थे.

मेघनाद देसाई

यह कांग्रेस के लिए परीक्षा की घड़ी है

वेलिंगटन के ड्यूक ने वाटरलू में कहा था कि वह नेपोलियन की सेना की तुलना में अपनी सेना से ज़्यादा डरे हुए थे. भारत के प्रधानमंत्री को भी कुछ–कुछ ऐसा ही एहसास जल्द ही हो सकता है. सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के बीच संबंध पर कांग्रेस के प्रवक्ता जनार्दन द्विवेदी ने कहा कि इन दोनों के बीच आज जो समझ है, उससे बेहतर कभी नहीं हो सकती.

इस बयान को ध्यान से पढ़ें. असल में यह एक बुरी ख़बर है. चूंकि यह समझ आज जितनी अच्छी है, उससे बेहतर कभी नहीं हो सकती. इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में यह ख़राब हो सकती है. हो सकता है कि द्विवेदी यह कहना चाहते हों कि यह समझ आज जितनी अच्छी है, उतनी कभी नहीं थी. हो सकता है ऐसा न भी हो. वह शायद एक जटिल संकेत दे रहे हों कि जहां तक कांग्रेस के वफादारों की बात है, मनमोहन सिंह के दिन अब गिनती के रह गए हैं. कांग्रेस के सबसे वफादार लोग भी मनमोहन सिंह को ज़्यादा हस्तक्षेप या दूसरों के अधिकार क्षेत्र में बेवजह हाथ डालने वाला व्यक्ति नहीं मानते. अर्जुन सिंह तो कैबिनेट की उस मीटिंग में भी जाना ज़रूरी नहीं समझते थे, जिसकी अध्यक्षता मनमोहन सिंह करते थे. कारण, अर्जुन सिंह ख़ुद को उनसे ज़्यादा वरिष्ठ समझते थे.

आज कांग्रेस में यह चर्चा हो रही है कि कांग्रेस ने जेपीसी की मांग को इसलिए भी नहीं माना क्योंकि प्रधानमंत्री जेपीसी के सामने उपस्थित नहीं होना चाहते थे. यह भी एक कारण है कि कांग्रेस के लोग अब मध्यावधि चुनाव की बात गुपचुप ढंग से करने लगे हैं. अगर इन अफवाहों में ज़रा सी भी सच्चाई है, तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस को ख़ुद की जांच करनी चाहिए. यूपीए के लिए प्रधानमंत्री कोई समस्या नहीं है. यह तो गठबंधन के वे लोग हैं जो उनकी सुनते ही नहीं. जब 2009 में कांग्रेस जीती, तो इसके पास पर्याप्त अवसर थे कि वह ख़ुद की सरकार बना सके. इसके पास पर्याप्त सीटें थीं, लेकिन इसने गठबंधन को चुना और यहीं से सारी समस्या की शुरुआत हुई. इसके मुख्य साथी जैसे तृणमूल, डीएमसी और एनसीपी के मन में कांग्रेस के प्रति कोई आदर भावना नहीं है और इनके पास इतनी ताक़त भी है कि वे कांग्रेस को ब्लैकमेल कर सकें. सोनिया गांधी ने कांग्रेस को पुनर्जीवित करने और इसमें जान फूंकने के प्रयास किए और इसमें वह सफल भी रहीं. लेकिन वह रिस्क लेने वाली महिला नहीं हैं. यही वजह है कि कांग्रेस इन सब अपमानों को सहती रही है, ताकि 2014 तक सत्ता में बनी रहे. उत्तर प्रदेश में 2012 की जीत के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं, डॉक्टर सिंह को शिष्टाचारपूर्वक 2012 में रिटायर कर दिया जाएगा ताकि राहुल गांधी को 2014 से पहले प्रधानमंत्री के रूप में काम करने के लिए दो साल मिल जाएं. 2012 तक और इसके आगे तक ख़ुद को बचाए रखने की कांग्रेस की इस जद्दोज़हद को इसके गठबंधन के साथी अच्छी तरह समझ रहे हैं और इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं.

दुर्भाग्य से यदि बिहार की कहानी एक बार फिर दोहराई तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कहीं की भी नहीं रहेगी. ऐसा इसलिए नहीं कि राहुल गांधी का करिश्मा कम हो गया है, बल्कि एक नेता के करिश्मे की बदौलत बहुत दिनों तक चुनाव नहीं जीता जा सकता. इसके लिए आपको स्थानीय और योग्य नेताओं की ज़रूरत होती है, जो जनता को यह समझा सकें कि हम आपकी समस्या को समझते हैं. उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास ऐसा कोई नेता नहीं है. असल में, क्षेत्रीय स्तर पर बिना चुनाव कराए और सिर्फ़ सोनिया गांधी की मर्जी से नेता चुने जाते हैं. इससे साबित होता है कि कांग्रेस को स्थानीय नेताओं पर भरोसा नहीं है. आंध्र प्रदेश में, कांग्रेस इसलिए बुरी फंसी क्योंकि उसके पास जगन मोहन के मुक़ाबले कोई नेता ही नहीं है. गुजरात में कांग्रेस के पास एक भी ऐसा नेता नहीं है जो मोदी को चुनौती दे सके. महाराष्ट्र में कांग्रेस सिर्फ़ मुख्यमंत्री बदलने में व्यस्त है. इस तरह, कांग्रेस के वफादार सिपाही सोचते हैं कि वे डॉक्टर सिंह का पत्ता आसानी से साफ कर सकते हैं. यदि मध्यावधि चुनाव होते हैं तो इस बार कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकेगी, क्योंकि इतना तय है कि यूपीए के कुछ घटक दल अपना रास्ता नहीं सुधारेंगे. उदाहरण के लिए, ममता बनर्जी, शरद पवार और कुछ हद तक डीएमके अब विषाक्त हो चुके हैं. इसलिए, कांग्रेस को मैदान में अकेले उतरना होगा और अपना भाग्य आजमाना होगा. और, यदि ऐसी स्थिति आती है तो कांग्रेस मध्यावधि चुनाव के बारे में सोच कर परेशान क्यों हो. इसे तो चाहिए कि यूपीए के सभी घटक दलों का साथ छोड़ कर अकेले ही अपनी लड़ाई लड़े.

अंततः, एक बड़ी समस्या यह है कि मनमोहन सिंह के बाद कौन? राहुल गांधी अभी भी तैयार नहीं हैं और शायद इच्छुक भी न हों. यदि कांग्रेस डॉक्टर सिंह पर पद छोड़ने का दबाव बनाती है तो कुछ ऐसे परिणाम निकलेंगे जो निश्चित हैं. मसलन, दोपहर तक सेंसेक्स 5000 प्वांइट नीचे गिर जाएगा और इससे भारत की छवि को धक्का पहुंचेगा. विश्वास की पुनर्बहाली होते–होते एक लंबा वक़्त लग जाएगा. कांग्रेस 2014 से पहले इस सवाल का जवाब देने के लिए बेहतर सोच सकती है.

आज कांग्रेस में यह चर्चा हो रही है कि कांग्रेस ने जेपीसी की मांग को इसलिए भी नहीं माना क्योंकि प्रधानमंत्री जेपीसी के सामने उपस्थित नहीं होना चाहते थे. यह भी एक कारण है कि कांग्रेस के लोग अब मध्यावधि चुनाव की बात गुपचुप ढंग से करने लगे हैं.

feedback@chauthiduniya.com

आख़िर क्यों मानें क़ानून?

कपिल देव दुबे

वैसे तो कहा जाता है कि क़ानून अंधा होता है, जिसका तात्पर्य यह है कि क़ानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध न्यायिक प्रक्रिया बिना भेदभाव के चलनी चाहिए पर यह कथन केवल कथन मात्र ही है. वास्तविकता इससे अलग है. तुलसीदास जी की चौपाई समरथ को नहीं दोष गोसाईं इसी यथार्थ का समर्थन करती है. इस कटु सच्चाई को अन्य विद्वान भी स्वीकार करते हैं. क़ानूनी कार्रवाई में भेदभाव आज देश और अपने प्रदेश की हक़ीक़त है. आरोपी की हैसियत देख कर ही क़ानून को क्रियान्वित किया जाता है. सज़ा निर्धारित करते समय भी आरोपी की हैसियत का प्रभाव झलकता है. भारतीय संविधान का अनुच्छेद–14, जो समानता के अधिकार की बात करता है, यह भी वस्तुतः बड़ी–बड़ी क़ानूनी पुस्तकों की विषय वस्तु तक ही सीमित है. धरातलीय सच्चाई ठीक इसके विपरीत है.

उत्तर प्रदेश में हाल ही में घटित कुछ घटनाएं राज्य की इसी धरातलीय राजनीति को उजागर करती हैं. अधिकतर घटनाओं के आरोपी उत्तर प्रदेश के माननीय विधायक हैं. इनका आचरण राज्य की क़ानून व्यवस्था की दशा व दिशा तय करता है. लेकिन इन घटनाओं से तो यही लगता है कि बिहार नाहक ही हिंसक राजनीति व नेताओं के अपराधी चरित्र के नाम पर बदनाम है. इन मामलों में यह प्रदेश सबसे आगे निकलता दिखाई दे रहा है. ऐसा हो भी क्यों न, जब प्रदेश विधानसभा में ऐसे विधायकों की भरमार है, जिनके ख़िलाफ़ पुलिस थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.

उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास के पतन की शुरुआत वैसे तो बहुत पहले से हो गई थी, लेकिन उस समय नेता अपनी जीत के लिए अपराधियों का इस्तेमाल करते थे. फिर एक समय ऐसा आया, जब राजनीतिक दलों ने अपराधियों को ही नेता बनाना शुरू कर दिया. राजनीति में अपनी बादशाहत क़ायम रखने के लिए सब कुछ जायज़ है, यह उत्तर प्रदेश के नेताओं के लिए उनका उसूल बन चुका है. फिर क्या अच्छा सोचना और क्या बुरा. वर्ष 2002 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनावों में अपराधियों को टिकट देने की ऐसी होड़ मची कि लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले नेताओं को ख़ुद पर तरस आने लगा. वर्ष 2002 में हुए विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश के जिन 403 निर्वाचन क्षेत्रों से, जो विधायक चुन कर आए, उनमें से 206 के ख़िलाफ़ किसी न किसी तरह का आपराधिक मामला दर्ज था. तस्वीर एकदम साफ है कि उस समय विधानसभा के अंदर साफ–सुथरी छवि वाले विधायकों के मुक़ाबले दागदार छवि वाले विधायकों की संख्या अधिक थी. इसके बावजूद राजनीतिक दल नहीं चेते. वर्ष 2007 में हुए विधानसभा चुनावों में आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों की संख्या में 74 फ़ीसदी की बढ़ोत्तरी देखने को मिली. इन सभी को प्रमुख राजनीतिक दलों ने टिकट दिए थे. 2007 के विधानसभा चुनावों में आपराधिक छवि के जिन उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, उनमें मऊ से मुख्तार अंसारी का नाम सबसे ऊपर है. मुख्तार की जीत इस वजह से भी अहम रही कि चुनाव के दौरान वह झांसी जेल में बंद था. मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में फंसे अमरमणि त्रिपाठी ने भी जेल में रहते हुए इन चुनावों में गोरखपुर की लक्ष्मीपुर सीट से जीत दर्ज की. कुंडा से जीत दर्ज करने वाले रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से कौन परिचित नहीं है. मुख्तार अंसारी के भाई एस.अंसारी ने मोहम्मदाबाद सीट से विधानसभा में प्रवेश किया. वर्तमान में बसपा के टिकट से विधायक हुए चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू के ख़िलाफ़ आपराधिक मामलों की लंबी सूची है.

उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास के पतन की शुरुआत वैसे तो बहुत पहले से हो गई थी, लेकिन उस समय नेता अपनी जीत के लिए अपराधियों का इस्तेमाल करते थे. फिर एक समय ऐसा आया, जब राजनीतिक दलों ने अपराधियों को ही नेता बनाना शुरू कर दिया.

सोनू के ख़िलाफ़ पंचायत चुनाव में जिस क़ानूनगो रामकुमार की हत्या का आरोप है, उसका कसूर महज़ इतना ही था कि वह अपनी पत्नी को प्रधानी का चुनाव लड़ाना चाहता था. सोनू ने उसे मना किया लेकिन रामकुमार नहीं माना, लिहाजा उसे मौत के घाट उतार दिया गया. जनता ने लोकतांत्रिक तरीक़े से इसका जवाब देते हुए रामकुमार की पत्नी को प्रधान तो बनवा दिया, लेकिन सवाल यह उठता है कि जनतंत्र को बचाए रखने के लिए रामकुमार जैसे कितनों की बलि चढ़ेगी. 2007 के चुनाव में जीत दर्ज करने वाले आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों की इस लिस्ट में डॉन बृजेश सिंह के भतीजे सुशील सिंह, बादशाह सिंह, बृजेश मिश्र, शहनवाज, दाऊद अहमद, आनंद सेन यादव, दद्दन मिश्र, जमुना निषाद, अवधपाल सिंह यादव, संग्राम सिंह, एस. इस्लाम अंसारी, हरपाल सिंह, डीपी यादव, धनंजय सिंह, अखिलेश कुमार सिंह समेत कई नाम शामिल हैं. इनके आगे क़ानून ख़ुद को बौना महसूस करता है. वर्ष 2007 में हुए विधानसभा चुनावों में बसपा को स्पष्ट बहुमत मिलने से राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति तो ख़त्म हो गई, लेकिन इस चुनाव में आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों की जीत ख़तरनाक रही. सत्ता हासिल करने के बाद इन अपराधी नेताओं का चरित्र और अधिक खूंखार हो गया है. क़ानूनगो रामकुमार की हत्या हो या फिर बरेली में विधायक के पुत्र की फायरिंग से राहगीर की मौत, यह आम जनता के लिए ख़ामोश रहने की चेतावनी ही तो है.

बात क़ानून के पालन की हो रही है. यह बात इसलिए हो रही है, क्योंकि हमारे देश में गणतंत्रात्मक पद्धति से सरकार चलाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें क़ानून का शासन सर्वोपरि है. जब जनता स्वयं अपना शासक चुनती है तो इतना कष्ट क्यों उठाती है, क़ानून का इतना उल्लंघन क्यों होता है?

(लेखक अवकाश प्राप्त आईपीएस अधिकारी हैं)

feedback@chauthiduniya.com

भ्रष्टाचार पर सार्थक लेख

संपादक जी ने भ्रष्टाचार पर बहुत ही सार्थक लेख लिखा है. इसका गंभीर पक्ष रखने के लिए वह साधुवाद के पात्र हैं. जब हम लोग अपने वोट का अधिकार जताने जाते हैं तो सबको यह मालूम होता है की सब चोर हैं. कोई बड़ा चोर है तो कोई छोटा चोर है. पर कौन छोटा चोर है और कौन बड़ा चोर, इसका फ़ैसला तो हमें ही करना है और यहीं से शुरू होता है भ्रष्टाचार का सफ़र.

मनोज सरदाना, ई–मेल से

सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी

चौथी दुनिया अख़बार में कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी पढ़ा. बहुत ही बढ़िया लगा. वैसे भी अब सरकार के रवैये को देखने का समय आ गया है, जब जनता को वोट डालते समय सोचना होगा कि वह किसे चुन कर भेज रही है. रही सेना के शासन करने की बात, अगर सेना के हाथ शासन आ गया तो इससे भी बुरा हाल होगा. आज सेना में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है. सरकारी भ्रष्टाचार की तो बाहर ख़बर भी आ जाती है परंतु सेनाओं में जो भ्रष्टाचार है वह तो पूरी तरह से ही सुरक्षित है. उसकी ख़बर मीडिया में नहीं पहुंचती. कोर्ट भी डिफेंस का मामला समझ कर चुप्पी साध लेता है.

राम, ई–मेल से

सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के परिणाम कुछ न कुछ तो निकलेंगे. भले ही आज हर तरफ़ भ्रष्टाचार का भय है लेकिन आपने लिखा, पाठकों ने सराहा, यह व्यर्थ नहीं जाएगा. भारत में अभी किसी सैनिक क्रांति की आवश्यकता नहीं है. न ही किसी मुल्क में सैनिक शासन कल्याणकारी प्रमाणित हुआ है. बाज़ारवाद और उदारवाद का मतलब ही पैसे का हेर–फेर है. सरकार जनता से टैक्स वसूल करके पूंजीवादियों पर लुटा रही है. शेयर मार्किट जनता को लूटने का माध्यम बन चुके हैं. लेकिन यह हाल पूरे हिंदुस्तान का नहीं है. आपकी चिंताए प्रतिफल ज़रूर देंगी.

अनिल त्यागी, ई–मेल से

आतंकियों का ट्रांजिट रूट उत्तर प्रदेश

चौथी दुनिया उत्तर प्रदेश में छपी आवरण कथा आतंकियों का ट्रांजिट रूट बना उत्तर प्रदेश पढ़ी. यह ख़बर देश सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है. इस ख़बर पर प्रदेश व केंद्र सरकार को ध्यान देते हुए सुरक्षा के समुचित इंतज़ाम करने चाहिए.

जयंत, ई–मेल से

घोटाला और नौकरशाह

भारत में भ्रष्टाचार के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ नौकरशाह ज़िम्मेदार हैं. पूरे भारत में नौकरशाहों की संख्या नेताओं की संख्या से कहीं ज़्यादा हैं. नेताओं को यह पता नहीं होता कि क़ानून को कैसे तोड़ा–मरोड़ा जाता हैं. नेता हर मामले से बच निकलते हैं. सज़ा के नाम पर उनसे इस्तीफ़ा ज़रूर ले लिया जाता हैं और कहा जाता है कि कार्रवाई होगी.

अमित कुमार गुप्ता, ई–मेल से

कैसे निजात मिलेगी

भ्रष्टाचार पर बहुत ही सार्थक ढंग से बात कही गई है और गंभीर विचार विमर्श सामने आए हैं. आप साधुवाद के पात्र हैं. पेड़ के पत्तों पर पानी डालने से कभी पेड़ को हरा रखने का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता है. इतना अवश्य है कि चिंतन के स्तर पर इसका विश्लेषण आशा जगाता है.

सुरेश यादव, ई–मेल से

जन–जागरण का काम कर रहा है आरटीआई

चौथी दुनिया समाचार पत्र में सूचना का अधिकार क़ानून 2005 के विषय में हर सप्ताह पढ़ने को मिलता है. ग्रामीण क्षेत्र में अभी इस क़ानून के विषय में लोगों को कम जानकारी है. समाचार पत्र में अपने कॉलम के द्वारा इस क़ानून के बारे में जो आम जनमानस में आप जनजागरण कर रहे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं. आशा करता हूं कि चौथी दुनिया अख़बार इसी तरह अच्छी जानकारी पाठकों को देता रहे, यही मेरी शुभकामना है.

मनोज कुमार, ज़िला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, कानपुर

आप अपने स्वतंत्र विचार तथा प्रतिक्रियाएं हमें इसी पते पर भेजें. संपादक, चौथी दुनिया, एफ़-2, सेक्टर-11 नोएडा, (उत्तर प्रदेश) पिन-201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

जब तोप मुक़ाबिल हो

संतोष भारतीय

हम हमेशा आपको याद करेंगे अटल जी

अटल बिहारी वाजपेयी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देनी चाहिए. इसलिए नहीं कि वे भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, बल्कि इसलिए कि वे भारत के उन गिने–चुने जीवित राष्ट्रीय नेताओं में हैं, जिनका नाम उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक अपने देश में रहने वाले किसी भी शख्स के लिए अनजान नहीं है. अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के होते हुए भी जब मोरारजी देसाई की सरकार में विदेश मंत्री थे तो उन्होंने पहली बार पाकिस्तान की ओर खुलने वाले भारत के दरवाज़े को खोल दिया था. पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिए वीज़ा के नियम न केवल शिथिल किए गए, बल्कि कुछ हद तक बदल भी दिए गए. आज तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग इस बात को नहीं भूले, क्योंकि दोनों देशों के बहुत से लोगों के रिश्तेदार यहां–वहां दोनों जगह हैं. अटल जी की वजह से न केवल मरने से पहले बहुत से लोग, जो सालों पहले बिछड़ गए थे, एक दूसरे का चेहरा भी देख पाए और अपने पुरखों की क़ब्र पर जाकर श्रद्धांजलि भी दे पाए.

पूरे जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमत न होने वाले भारत के मुसलमान केवल अटल बिहारी वाजपेयी से कुछ नज़दीकी महसूस करते रहे हैं. अटल बिहारी वाजपेयी कभी कट्टर हिंदुत्व का चेहरा नहीं बनें बल्कि भारतीय मानस के उस पक्ष का चेहरा बने जो कहता है कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, तुम मेरी बात सुनो. अटल जी के मुस्लिम दोस्तों की अच्छी–ख़ासी तादाद है, जो उन्हें अक्सर याद करती है.

देश अटल जी को उनके शब्दों, अभिव्यक्ति और भाषण कला के लिए तो याद करता ही है, उनकी समझदारी के लिए भी याद करता है. अटल जी ने कभी अपने को खांचे में नहीं बांधा, इसीलिए नेहरू जी व शास्त्री जी उन्हें बहुत पसंद करते थे. अटल जी को विपक्ष में नेहरू स्टाइल राजनीति करने वाला भी कहा जाता रहा है. अटल जी को इंदिरा जी ने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में भी भेजा था. अटल जी ने भारत–पाकिस्तान के युद्ध में भारतीय नेतृत्व करने वाली महिला इंदिरा गांधी को बिना किसी लाग लपेट के दुर्गा कहा था.

अटल जी अपने दल के अलावा विपक्ष के दूसरे दलों के नेताओं के साथ भी हमेशा संपर्क में रहते थे. किसी भी राष्ट्रीय नेता का नाम लीजिए, उसका आत्मीय रिश्ता अटल जी के साथ निकल आएगा. चंद्रशेखर जी के साथ अटल जी का रिश्ता बहुत ही अजीब था. चंद्रशेखर जी, अटल जी को गुरु जी कहते थे. दोनों जब भी मिलते थे, घंटों बातें करने की चाह रखते थे. भैंरो सिंह शेखावत भारत की राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी के बाद भाजपा के दूसरे नेता थे, जिनका रिश्ता और संबंध सभी दलों में था. ये ऐसे लोग रहे, जिन्होंने आपसी बातचीत में कभी भी राजनीति नहीं आने दी.

आज अटल बिहारी वाजपेयी बीमार हैं. यह बीमारी उम्र की वजह से है. अफ़सोस इस बात का है कि लोग उन्हें भुलाने लगे हैं. उनसे मिलने जाने वालों की संख्या कम से कम हो रही है. उनकी अपनी पार्टी के लोग भी अब उनसे मिलने नहीं जाते. पिछले लोकसभा चुनाव मे तो उनकी पार्टी में उनकी अपील या उनकी फोटो तक पोस्टरों पर नहीं छापी. उस चुनाव में आडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनाने के नारे के साथ भाजपा ने चुनाव लड़ा था. भाजपा इतनी ओवरकॉन्फीडेंट थी कि उस ने अटल जी को इस लायक़ नहीं समझा कि उनसे अपील कराई जाए. जनता को अटल जी की अनदेखी पसंद नहीं आई और भाजपा को वो वोट भी नहीं मिले, जो अक्सर मिल जाते थे.

अटल जी के राजनीति से ग़ायब होने या उन्हें अनदेखा करने से भाजपा में एक बड़ा शून्य उभर आया है. आडवाणी जी उस स्थान को न भर पाए और न भर पाएंगे, ऐसा लगता है. सुषमा स्वराज, वेंकैय्या नायडू, अरुण जेटली, अनंत कुमार जैसे नेताओं में भी अटल जी का एक भी गुण दिखाई नहीं देता. इनकी राजनीति दायरे की राजनीति है. भाजपा का सिकुड़ना अटल जी की अनुपस्थिति का सबसे बड़ा कारण है.

अटल जी बेबाक थे. वे सही मायने में राजनेता और दूरदर्शी हैं. गुजरात दंगों पर वे नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े आलोचक थे और आज भी हैं. उन्हें पता था कि यदि मोदी गुजरात में बने रहते हैं तो देश भाजपा के हाथ से चला जाएगा. उन्होंने पूरी ताक़त लगा दी, लेकिन भाजपा के अपने साथियों और शिष्यों को वे नहीं समझा पाए. आडवाणी जी के नेतृत्व में पार्टी मोदी के पक्ष में खड़ी हो जाए. अटल जी ख़ून के आंसू पी कर रह गए. वही हुआ, जो अटल जी नहीं होने देना चाहते थे. गुजरात बच गया, लेकिन सारा देश भाजपा के हाथ से निकल गया.

आज भाजपा के पास आडवाणी भी नहीं हैं क्योंकि उनकी भी बात अब भाजपा में नहीं सुनी जाती. भाजपा के पास मोदी हैं, येदुरप्पा हैं. भाजपा ने अनुशासन का मिथ तोड़ दिया है. अब उसे कोई अनुशासित पार्टी नहीं कहता. अटल जी की अनुपस्थिति का सबसे बड़ा नुक़सान भारत के लोकतंत्र को हुआ है. भारत में कोई विपक्ष है ही नहीं. अटल जी हमेशा देश की तकलीफ की आवाज़ थे. मैंने ख़ुद उनके पास महाराष्ट्र के आदिवासियों को भेजा था, अटल जी ने उनकी तकलीफ को न केवल सुना बल्कि संसद में भी उठाया. आज भाजपा के नेताओं के पास अपने ही कार्यकर्ताओं की बात सुनने का वक़्त नहीं है तो वे देश के ग़रीबों की आवाज़ कैसे सुनेंगे.

अटल जी का जन्मदिन इस तरह मनाना चाहिए कि लगे कि देश के लिए बहुत कुछ करने वाले नेता को हम याद कर रहे हैं. मैं जानता हूं कि भाजपा या संघ अटल जी के जन्मदिन की खानापूरी करेंगे. क्या देश की जनता भी खानापूरी करेगी? शायद नहीं.

क्रिसमस बीत गया, ईसा मसीह को याद करने का समय है. क्रिसमस की, देर से ही सही, देश को बधाई. लेकिन आज अटल जी को भी जन्म दिन की फिर से एक बार बधाई. अटल जी हमारे बीच रहें और उन कमियों का एहसास कराते रहें जो हमारे आसपास घिर रही हैं. हम हमेशा आपको याद करेंगे अटल जी.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

संघ, अयोध्या निर्णय व भारतीय राष्ट्रवाद

अयोध्या निर्णय की जिन आधारों पर आलोचना की जा रही है, उनमें से कुछ हैं, ज़मीन के मालिकाना हक़ संबंधी मूल मुद्दे की उपेक्षा व 23 दिसंबर, 1949 की आधी रात को मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्तियों की स्थापना और 6 दिसंबर 1992 को संघ परिवार द्वारा मस्जिद को ढहाए जाने के घोर अवैधानिक व अनैतिक कृत्यों को नज़रअंदाज़ किया जाना. हाल में इस मुद्दे में एक नया आयाम जुड़ गया है. और यह आयाम है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा इस निर्णय की प्रशंसा व स्वागत. भागवत ने कहा है कि इस निर्णय से भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है, क्योंकि अदालत ने उस भूमि, जहां मस्जिद स्थित थी, का दो तिहाई हिस्सा हिंदुओं को आवंटित कर दिया है. उन्होंने यह भी फरमाया कि भूमि का विभाजन अनावश्यक था, क्योंकि विभाजन से हमेशा समस्याएं ही पैदा होती हैं, जैसा कि कश्मीर के मामले में हुआ.

उन्होंने यह मांग की कि पूरी ज़मीन हिंदुओं को सौंप दी जानी चाहिए. इससे विदेशी शासन की प्रतीक, बाबरी मस्जिद, का नामो–निशां मिट जाएगा और भारतीय राष्ट्रीयता का गौरव बढ़ेगा. राम मंदिर बनने से, भागवत के अनुसार, भारत की आत्मचेतना का उदय होगा.

संघ की भविष्य की रणनीति की ओर संकेत करते हुए भागवत ने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत के मूल चरित्र व उसकी असली छवि को प्रतिविंबित करने वाले उन सभी प्रतीकों की पुन:स्थापना की जाए, जो विदेशी शासन के दौरान नष्ट–भ्रष्ट कर दिए गए थे.

भागवत का बयान, संघ की राजनीति, विचारधारा व एजेंडे के अनुरूप है. कहने की आवश्यकता नहीं है कि विवादित स्थल की ज़मीन के विभाजन की तुलना कश्मीर के विभाजन से करना बेमानी व अतार्किक है. कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य था, जिस पर पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया था. इस आक्रमण के बाद, कश्मीर भारत का हिस्सा बना लेकिन इस शर्त पर कि रक्षा, संचार, मुद्रा व विदेशी मामलों को छोड़कर, अन्य सभी क्षेत्रों में उसे पूर्ण स्वायत्ता हासिल रहेगी. जब भारतीय सेना कश्मीर पहुंची, तब तक पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर के एक–तिहाई हिस्से पर क़ब्ज़ा कर लिया था. कश्मीर का विभाजन किसी क़ानूनी प्रक्रिया से नहीं हुआ. वह तो पाकिस्तान के आक्रमण का नतीजा था. कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान का ग़ैर–क़ानूनी क़ब्ज़ा बना हुआ है. संयुक्त राष्ट्रसंघ ने कश्मीर में जनमत संग्रह कराने की बात कई बार कही परंतु वह आज तक नहीं हो सका है.

बाबरी मस्जिद, एक वैध भारतीय क़ानून के अंतर्गत, संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक थी. सन 1949 में 23 दिसंबर की रात को, हिंदू राष्ट्रवाद से प्रेरित, अज्ञात व्यक्तियों ने इस स्मारक में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर, वहां रामलला की मूर्तियां रख दीं. उसके बाद, सन 1980 के दशक में, आडवाणी व उनके साथियों ने इस मुद्दे का दामन थाम लिया और 1992 में मस्जिद को ढहा दिया गया. यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में घटित सबसे बड़े अपराधों में से एक था. यह भारतीय संविधान पर हमला भी था.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस मामले में पंचायती फ़ैसला सुना दिया. मूल प्रश्नों व मुद्दों को दरकिनार कर दिया गया. संभवत:, न्यायालय भी सांप्रदायिक हिंसा व दुष्प्रचार के चलते, समाज के सांप्रदायिकीकरण से प्रभावित हो गया था. ज़रूरत इस बात की है कि इस मामले में भारतीय संविधान व क़ानूनों के प्रकाश में उचित, न्यायोचित निर्णय किया जाए. सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड, विवादित भूमि पर इतने लंबे समय से क़ाबिज़ था, कि भूमि पर उसके मालिकाना हक़ को कोई वैधानिक चुनौती नहीं दी जा सकती. पूरी ज़मीन को सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड को सौंपा जाना ही इस विवाद का न्यायपूर्ण हल होगा.

मध्यकाल में निर्मित इमारतों को विदेशी शासन का प्रतीक मानना, भारतीय राष्ट्रीयता की अवधारणा के विरुद्ध है. भारतीय राष्ट्रवादियों ने केवल ब्रिटिश शासन को विदेशी शासन माना था और उसके विरुद्ध संघर्ष किया था. इसके बावजूद, भारतीय राष्ट्रवादियों ने कभी ब्रिटिश शासन के दौरान निर्मित इमारतों, जिनमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन व नॉर्थ तथा साउथ ब्लॉक शामिल हैं, को नष्ट किए जाने की बात तक नहीं की. संघ और उसकी विचारधारा के अन्य संगठनों ने विदेशी शासन के विरुद्ध चले लंबे संघर्ष में तनिक भी भागीदारी नहीं की. वे शायद केवल मुस्लिम बादशाहों के दौर को विदेशी राज मानते हैं, ब्रिटिश शासन को नहीं. यह सोच भी भारतीय राष्ट्रवाद के विरुद्ध है. बादशाहों और राजाओं–नवाबों के शासनकाल को राष्ट्रीयता से जोड़ना अनुचित व अवांछनीय है. राजा–चाहे वे किसी धर्म के क्यों न रहे हों–केवल सत्ता और संपत्ति के उपासक थे. वे न तो जनता के प्रतिनिधि थे और न ही अपने धर्मों के. चूंकि संघ की विचारधारा का उदय ही हिंदू राजाओं, जमींदारों व पुरोहितों के अस्त होते वर्गों से हुआ था, इसलिए आश्चर्य नहीं कि संघ, राजाओं के शासनकाल को राष्ट्रवाद से जोड़ता है. ठीक यही दृष्टिकोण मुस्लिम सांप्रदायिक तत्वों का है. वे भी मुस्लिम बादशाहों के राज को राष्ट्रवाद का प्रतीक मानते हैं. सांप्रदायिक विचारधारा के पोषक, जानबूझकर, राजशाही व आधुनिक राष्ट्र–राज्यों के बीच अंतर नहीं करते. उनकी यह मान्यता है कि विभिन्न धार्मिक समुदाय, हमेशा से एक–दूसरे के शत्रु हैं और आपस में युद्धरत रहे हैं.

मध्यकाल में निर्मित इमारतों को विदेशी शासन का प्रतीक मानना, भारतीय राष्ट्रीयता की अवधारणा के विरुद्ध है. भारतीय राष्ट्रवादियों ने केवल ब्रिटिश शासन को विदेशी शासन माना था और उसके विरुद्ध संघर्ष किया था. इसके बावजूद, भारतीय राष्ट्रवादियों ने कभी ब्रिटिश शासन के दौरान निर्मित इमारतों, जिनमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन व नॉर्थ तथा साउथ ब्लॉक शामिल हैं, को नष्ट किए जाने की बात तक नहीं की.

हिंदू राजा भी हिंदू किसानों का शोषण करते थे. और यदि मुस्लिम राजा, हिंदू कृषकों का ख़ून चूसते थे तो उसका कारण यह नहीं था कि किसान हिंदू थे. मुस्लिम बादशाहों का मुस्लिम कृषकों के साथ भी यही व्यवहार रहता था. कुछ अपवादों को छोड़कर, राजाओं–बादशाहों ने कभी किसी धर्म की ध्वजा नहीं उठाई. बेशक, शुरुआती दौर में कुछ मुस्लिम आक्रांताओं ने लूटपाट मचाई लेकिन एक बार हिंदू राजाओं के साथ संधियां आदि करके, भारत में उनका राज जम गया. उसके बाद उन्होंने भारत से संपत्ति लूट कर देश के बाहर ले जाना बंद कर दिया. इसके विपरीत, ब्रिटिश शासन का तो मूल उद्देश्य ही भारत के प्राकृतिक संसाधनों को लूटकर ब्रिटेन को धनी बनाना था.

संघ व अन्य सांप्रदायिक तत्व, ब्रिटिश शासन के शोषक चरित्र को नज़रअंदाज़ कर, मुस्लिम शासकों के अत्याचारों का राग अलापते रहते हैं. यह राग उनके धार्मिक राष्ट्रवाद के एजेंडे के अनुरूप है. उस राष्ट्रवाद के, जो स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के मूल्यों के विरुद्ध है.

इसके विपरीत, आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद, इतिहास को धर्म के चश्मे से नहीं देखता. इसका मुख्य लक्ष्य, संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप, भविष्य के भारत को समृद्ध, शक्तिशाली व सबके साथ न्याय करने वाला देश बनाना है. इसी कारण, पंडित नेहरू, उद्योगों, बांधों और उच्च शिक्षण संस्थाओं को आधुनिक भारत के नए मंदिर कहा करते थे. इसके उलट संघ की रुचि केवल प्राचीन भारत के पुरातन मंदिरों में है. उसकी रुचि, भारतीय इतिहास के उस दौर में है, जिसमें हिंदू राजा, मनुस्मृति के सिद्धांतों के अनुरूप शासन करते थे, जब जन्म–आधारित ऊंच–नीच का बोलबाला था.

अंग्रेज शासकों ने एक सोची–समझी रणनीति के तहत, भारतीय इतिहास का पुनर्लेखन किया, राजाओं को हिंदू व मुस्लिम के रूप में प्रस्तुत किया और भारतीयों के बीच विभाजन के बीज बोए. एक ओर हिंदू महासभा–आरएसएस व दूसरी ओर मुस्लिम लीग ने इस खेल में अंग्रेजों का साथ दिया. उन्होंने इतिहास के ब्रिटिश संस्करण को सहर्ष स्वीकार कर लिया व एक–दूसरे के धार्मिक समुदायों को बदनाम करने व उनके विरुद्ध घृणा फैलाने के लिए हर संभव प्रयास किए. दूसरे से घृणा करो, के इसी अभियान ने, भारत के विभाजन और सांप्रदायिक हिंसा की नींव डाली. भारत का विभाजन, फूट डालो और राज करो की ब्रिटिश नीति की सफलता का प्रतीक था और इस सफलता में सांप्रदायिक संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान था. आज, भारत में विघटनकारी राजनीति को एक बार फिर हवा दी जा रही है, ताकि रोटी, कपड़ा और मकान के मूलभूत मुद्दों को हाशिए पर पटका जा सके और आम आदमी के सम्मान व गरिमा से जीवन बिताने के अधिकार का दमन किया जा सके.

पुरातन प्रतीकों की पुन:स्थापना करने का संघ प्रमुख का आह्वान ख़तरों का घर है. सवाल यह है कि हम कितने पीछे जाएंगे? हम कितने सौ या कितने हज़ार साल पुराने प्रतीकों को पुन:स्थापित करेंगे? कुछ लोग उस युग में वापस जाना चाहेंगे, जब हिंदुओं द्वारा बौद्ध विहारों को नष्ट किया जा रहा था. क्या हम उस दौर में वापस जाएंगे, जब आर्य भारत में आए और उन्होंने स्थानीय निवासियों व आदिवासियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया?

हम भारतवासियों ने 15 अगस्त 1947 को एक नए युग की शुरुआत माना था. हमने तय किया था कि इस दिन से हम कल की बातें छोड़ कर, नए दौर में मिलकर नई कहानी लिखेंगे.

आरएसएस, उसकी विचारधारा और उसकी मांगें व आह्वान, भारतीय राष्ट्रवाद से कतई मेल नहीं खाते. अगर हमें उस भारत को संरक्षित रखना है, जिसका जन्म हमारे स्वाधीनता आंदोलन की कोख से हुआ था और जिसे हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने गढ़ा था, तो हमें संघ की व उसके जैसी विचाराधाराओं का प्राणप्रण से विरोध करना होगा.

अयोध्या निर्णय को भारतीय क़ानून की कसौटी पर कसा जाना आवश्यक है. आरएसएस का लोगों को बांटने का एजेंडा, किसी विवाद को सुलझाने, किसी समस्या का हल निकालने का आधार नहीं हो सकता. जो लोग सांप्रदायिक सौहार्द के पक्षधर हैं, जो भारतीय संविधान के प्रति प्रतिबद्ध हैं, जो मानवाधिकारों का सम्मान करते हैं, उन सब लोगों का यह पावन कर्तव्य है कि वे आगे आएं और भारतीय राष्ट्रवाद की सही अवधारणा के बारे में जनजागृति फैलाएं, धार्मिक समुदायों के बीच सेतु बनें और मानवाधिकारों की रक्षा करते हुए देश को औद्योगिकरण और शिक्षा के प्रसार के रास्ते प्रगति पथ पर आगे बढ़ाने का यत्न करें. मंदिरों और मस्जिदों को, वे जैसी और जहां हैं, वैसी व वहीं छोड़ दिया जाना चाहिए.

राम पुनियानी
feedback@chauthiduniya.com

(लेखक आईआईटी मुंबई में पढ़ाते थे, और सन 2007 के नेशनल कम्यूनल हार्मोनी एवार्ड से सम्मानित हैं.)

पंचायती राज व्यवस्था के असफल होने के पीछे सबसे बड़ी वजह भी यही है. लेकिन, सूचना के अधिकार क़ानून के आने से अब सरपंच अपनी मर्जी नहीं चला सकता.

सूचना का अधिकार
जानने का अधिकार
जीने का अधिकार
चौथी दुनिया की पहल

पंचायत के ख़र्च का हिसाब मांगे

गांधी जी का सपना था कि देश का विकास पंचायती राज संस्था के ज़रिए हो. पंचायती राज को इतना मज़बूत बनाया जाए कि लोग ख़ुद अपना विकास कर सकें. आगे चल कर स्थानीय शासन को बढ़ावा देने के नाम पर त्री-स्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू भी की गई. ज़िला स्तर पर ज़िला परिषद. खंड स्तर पर एक इकाई और सबसे नीचे के स्तर पर ग्राम पंचायत. ग्राम पंचायत की अवधारणा लागू हो गई. इसके साथ ग्राम सभा नाम की भी एक संस्था बनाई गई. ग्राम सभा एक स्थायी संस्था के रूप में काम करती है, जिसमें पंचायत के सभी वयस्क मतदाता शामिल होते हैं. ग्राम सभा की संकल्पना इसलिए की गई थी ताकि पंचायत के किसी भी विकास कार्य में गांव के लोगों की सीधी भागीदारी हो. उनकी सहमति से विकास कार्य की कोई भी रूपरेखा बने. लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा. आज देश की किसी भी पंचायत में ग्राम सभा की हालत ठीक नहीं है. ग्राम सभा की बैठक महज़ खानापूर्ति के लिए की जाती है. किसी भी विकास योजना में ग्रामीणों से न तो कोई सलाह ली जाती है और न ही ग्राम सभा की बैठक में उस पर चर्चा की जाती है. पंचायती राज व्यवस्था के असफल होने के पीछे सबसे बड़ी वजह भी यही है. लेकिन, सूचना के अधिकार क़ानून के आने से अब सरपंच अपनी मर्जी नहीं चला सकता. बशर्ते, आप सरपंच और पंचायत से सवाल पूछना शुरू करें. एक पंचायत में विकास कार्यों के लिए लाखों रुपये सलाना आते हैं. इसके अलावा, विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाएं आती हैं. ज़रूरत सिर्फ़ इस बात की है कि एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते अगर आपको लगता है कि सरपंच और अन्य अधिकारी मिल कर इन रुपयों और योजनाओं में घोटाले कर रहे हैं तो बस आप सूचना का अधिकार क़ानून के तहत एक आवेदन डाल दें. आप अपने आवेदन में किसी एक ख़ास वर्ष में आपकी पंचायत के लिए कितने रुपये आवंटित हुए. किस कार्य के लिए आबंटन हुआ? वह कार्य किस एजेंसी के द्वारा करवाया गया? कितना भुगतान हुआ? भुगतान की रसीद इत्यादि की भी मांग कर सकते हैं. इसके अलावा, आप कराए गए कार्यों का निरीक्षण करने की भी मांग कर सकते हैं. इसके साथ ही आप केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं के बारे में भी सवाल पूछ सकते हैं. मसलन, इंदिरा आवास योजना के तहत आपके गांव में किन-किन लोगों को आवास आवंटित हुए. ज़ाहिर है, जब आप ये सवाल पूछेंगे, तो भ्रष्ट सरपंचों और अधिकारियों पर एक तरह का दबाव बनेगा. और यह काम आप चाहें तो कई लोगों के साथ मिल कर भी कर सकते हैं. जैसे अलग-अलग मामलों पर या एक ही किसी मामले में कई लोग मिल कर आवेदन डालें. इसका असर यह होता है कि चाह कर भी कोई दबंग सरपंच या अधिकारी आप पर दबाव नहीं डाल पाएगा या आपको धमकी नहीं दे पाएगा. तो, हम उम्मीद करते हैं कि इस अंक में प्रकाशित आवेदन का इस्तेमाल आप ज़रूर करेंगे और अन्य लोगों को भी इसके इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ताकि आपकी पंचायत में यदि भ्रष्टाचार है तो उसे ख़त्म किया जा सके, उसे करारा जवाब दिया जा सके.

पंचायती राज व्यवस्था के असफल होने के पीछे सबसे बड़ी वजह भी यही है. लेकिन, सूचना के अधिकार क़ानून के आने से अब सरपंच अपनी मर्जी नहीं चला सकता. बशर्ते, आप सरपंच और पंचायत से सवाल पूछना शुरू करें. एक पंचायत में विकास कार्यों के लिए लाखों रुपये सलाना आते हैं. इसके अलावा, विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाएं भी आती हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

ग्राम पंचायत के ख़र्चे का विवरण

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन.

महोदय,
.....ग्राम पंचायत के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:

1. वर्ष.....के मध्य.....ग्राम पंचायत को किन-किन मदों/योजनाओं के तहत कितनी राशि आवंटित की गई? आबंटन का वर्षवार ब्योरा दें.
2. उपरोक्त ग्राम पंचायत द्वारा इस दौरान करवाए गए सभी कार्यों से संबंधित निम्नलिखित विवरण दें:

1. कार्य का नाम
2. कार्य का संक्षिप्त विवरण
3. कार्य केलिए स्वीकृत राशि
4. कार्य स्वीकृत होने की तिथि
5. कार्य समाप्त होने की तिथि अथवा चालू कार्य की स्थिति
6. कार्य कराने वाली एजेंसी का नाम
7. कार्य शुरू होने की तिथि
8. कार्य समाप्त होने की तिथि
9. कार्य के लिए ठेका किस दर पर दिया गया?
10. कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है
11. कार्य के रेखाचित्र की प्रमाणित प्रति
12. कार्य कराने का निर्णय कब और किस आधार पर लिया गया? इससे संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति भी उपलब्ध कराएं.
13. उन अधिकारियों/कर्मचारियों का नाम व पद बताएं जिहोंने कार्य का निरीक्षण किया और भुगतान की स्वीकृति दी.
14. कार्य के वर्क ऑर्डर रजिस्टर एवं लेबर रजिस्टर/मस्टर रोल की प्रति उपलब्ध कराएं.

3. उपरोक्त ग्राम पंचायत में वर्ष.....के दौरान कार्यो/योजनाओं पर होने वाले खर्चो की जानकारी निम्न विवरणों के साथ दें:

क. कार्य का नाम जिसके लिए ख़र्च किया गया
ख. कार्य का संक्षिप्त विवरण
ग. कार्य के लिए स्वीकृत राशि
घ. कार्य कराने वाली एजेंसी का नाम
ड. कार्य शुरू होने की तिथि
च. कार्य के रेखाचित्र की प्रमाणित प्रति
छ. कार्य कराने का निर्णय कब और किस आधार पर लिया गया? इससे संबंधित दस्तावेजों की प्रति भी उपलब्ध कराएं.

मैं आवेदन फीस के रूप में 10रुपये अलग से जमा कर रहा /रही हूं.
या
मैं बी.पी.एल. कार्ड धारी हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बी.पी.एल. कार्ड नं.....है.

यदि मांगी गई सूचना आपकेविभाग/कार्यालय से संबंधित नहीं हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों की समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बताएं.

भवदीय

नाम:
पता:
फोन नं:

संलग्नक:
(यदि कुछ हो)

ज़रा हट के

खुदाई में निकला सूप

माना जा रहा है कि ये चीन का पहला बोन सूप है. चीन की राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक़ देश के भूगर्भशास्त्रियों को एक ऐसा कटोरा हाथ लगा है, जिसमें मौजूद सूप 24 सौ साल पुराना हो सकता है. यह सूप कांसे के एक बर्तन में सुरक्षित रखा था और इस बर्तन का ढक्कन ऊपर से बंद था. बंद बर्तन के अंदर सूप का तरल पदार्थ और उसमें हड्डियां सुरक्षित पाई गई हैं. यह बर्तन एक खुदाई के दौरान चीन के प्राचीन शहर सियान में मिला. चीन केमशहूर मिट्टी के लड़ाके यानी टेराकोटा वॉरियर्स इसी शहर के हैं. अब इस तरल पदार्थ की जांच यह पता करने के लिए हो रही है कि यह किससे बना था और इसमें किन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ था. इस खुदाई के दौरान बिना किसी गंध वाला एक और तरल पदार्थ मिला, जिसके बारे में माना जा रहा है कि वह एक किस्म की शराब, वाइन है.

स्थानीय एयरपोर्ट तक जाने के लिए एक उपमार्ग बनाने के उद्देश्य से की जा रही खुदाई के दौरान ये बर्तन एक क़ब्र की खुदाई के समय मिले. चीन की मीडिया में कहा गया है कि यह चीन के इतिहास में पहले बोन सूप की खोज है. चीन की मीडिया के मुताबिक़ यह खोज 475-221 ईसा पूर्व के मध्य देश में रह रहे लोगों के बारे में, उनकी सभ्यता और खान-पान वग़ैरह के बारे में पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. वैज्ञानिकों ने कहा है कि जिस क़ब्र से सूप और उसका मर्तबान मिला है, वह या तो किसी ज़मींदार या फिर निम्न स्तर के किसी सैनिक अधिकारी का रहा होगा. सियान 11 सौ साल से ज़्यादा लंबे समय तक चीन की राजधानी रहा था. चीन के पहले बादशाह, किन शिहुआंग की क़ब्रगाह केस्थल पर 1974 में इसी शहर में चीन की मशहूर टेराकोटा आर्मी मिली थी. 221 ईसा पूर्व में किन शिहुआंग ने चीन के एकीकरण का नेतृत्व किया था. उन्होंने 210 ईसा पूर्व तक चीन पर शासन किया था.

जेल में मौज

क्या कभी आपने जेल में अपराधियों को पिज़्ज़ा खाते देखा है? नहीं न, मगर दिल्ली के एक जेल में आपको ऐसा शख्स मिल जाएगा. वैसे तो हर मुजरिम को जेल का खाना-खाना पड़ता है. मगर अब अपराधी ही हाई-फाई हो तो भला खाना भी तो उसके स्टैंडर्ड का होना चाहिए. दरअसल हाल ही में कॉरपोरेट जासूसी के आरोप में गिरफ़्तार आईएएस अधिकारी रवि इंदर सिंह इन दिनों दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में पिज़्ज़ा का लुत्फ उठा रहे हैं. गृह मंत्रालय से संवेदनशील सूचनाएं लीक करने के आरोप में गिरफ़्तार रवि इंदर अब दिल्ली पुलिस पर भी अपना रौब दिखा रहे हैं. दिल्ली की न्यू फ्रेंडस कालोनी में बनी दिल्ली पुलिस की इस विशेष सेल में बंद रवि फोन से अपने लिए पिज़्ज़ा का ऑर्डर देता है. साथ ही आला अधिकारियों से अपनी आव-भगत भी करवाता है.

ग़ौरतलब है कि रवि इंदर 1944 बैच का पश्चिम बंगाल कैडर का आईएएस अधिकारी है. जिसे गृह मंत्रालय की अति संवेदनशील आंतरिक सुरक्षा शाखा के निदेशक की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन लड़की और पैसे के चक्कर में उसने अपने देश से गद्दारी की. उस पर आरोप है कि उसने गृह मंत्रालय की ख़ुफ़िया जानकारी एक दूरसंचार कंपनी को देने की कोशिश की. उसके ख़िलाफ़ प्रशासनिक कार्रवाई के चलते उसे बाद में सीवीसी में निदेशक के पद से भी हटा दिया गया. ख़ैर यह तो पुरानी बात हो गई है, लेकिन अभी तो वह जेल में मौज काट रहा है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

राशिफल

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
यह सप्ताह आपके लिए सुखद रहेगा. आपकी पर्सनैलिटी और पोजिशन से चिढ़ने वालों की कमी नहीं होगी लेकिन आप ऐसे लोगों पर ध्यान न दें. अपने काम करने के ढंग को दूसरों के कहने पर बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
यह सप्ताह आपके लिए सामान्य रहेगा. राजनीतिक या सोशल मामले ऐसे सिर उठाएंगे कि आपको किसी न किसी संगठन को ज्वाइन करना पड़ सकता है. सप्ताह के उत्तरार्ध में जब आप किसी ऐसे निर्णय को लेने की सोच रहें हैं.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
यह सप्ताह आपके लिए अच्छा है. बिज़नेस में आए उतार चढ़ाव का हल निकालने में कामयाब हो जाएंगे. रूटीन के काम को आप ज़िंदादिल बनाने में सफल हो जाएंगे. नए प्रोजेक्ट या काम के नए तरीक़े को शुरू करने के लिए सप्ताह का उत्तरार्ध काफी अच्छा है.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
यह सप्ताह काफी शांति से गुजरेगा. ऑफिस में काम का ज़्यादा बोझ नहीं होगा. ऐसे में आप काफी राहत महसूस करेंगे. अपने सारे कामों को शांत वातावरण में निपटाने की कोशिश करें. सप्ताह के अंत तक सभी समस्याओं का हल आप निकाल ही लेंगे.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
इस सप्ताह के आरंभ में ही आपके ऊपर ढेर सारी ज़िम्मेदारियां आएंगी. सड़क पर चलते समय सावधानी बरतें. ऑफिस में ज़्यादा काम करना पड़ सकता है. अपने कामों को कुछ इस तरह से शेड्यूल करें कि आपके काम आसान हो जाएं.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
यह सप्ताह आपके लिए काफी बदलाव लेकर आ रहा है. ऑफिस में कोई बड़ा चेंज आ सकता है. रोमांस के मामले में कोई बदलाव आ सकता है. कोई नया दोस्त आपको किसी इवेंट के लिए इनवाइट कर सकता है जहां आपको एक अनूठा संसार मिलेगा.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
यह सप्ताह आपके लिए चैलेंजिंग है. अपनी क्रिएटिविटी का जितना हो सके उतना प्रयोग करें. मांगलिक कार्यों के लिए किया जा रहा प्रयास सफल होगा. फाइनेंस के मामले में कठिनाई हो सकती है.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
यह सप्ताह मिले-जुले असर वाला होगा. काम के मामले में अपने पांव ज़्यादा पसारना ठीक नहीं होगा. आपके प्रमोशन के बारे में ऑफिस में चर्चा हो रही है लेकिन ख़ुद पूछने की बजाए अपने बॉस के आदेश का इंतज़ार करें.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
यह सप्ताह प्यार के मामले में काफी अच्छा है. पिछले कुछ दिनों से चले आ रहे किसी विवाद को सुलझाने का सही समय आ गया है. अपने और अपने प्रेमी के बीच की ग़लतफहमी को दूर कर दें. किसी मुद्दे पर साफ साफ बात करने से समस्या का हल निकल सकता है.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
इस सप्ताह में आपको घूमने फिरने और मौज मस्ती करने का प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आपके लिए आपके दोस्त और भाई बहन यह काम करेंगे. मौसम का मिजाज़ आपके पक्ष में होगा. पढ़ाई लिखाई के मामले में ध्यान लगाने का मौक़ा मिलेगा.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
यह सप्ताह सामान्य रहेगा. आजकल आप अपने आसपास के लोगों के बीच पॉपुलर होते जा रहे हैं. कोई ऐसा शख्स जिससे आप हाल फिलहाल में ही मिले हैं, आपके क़रीब आने की कोशिश करेगा. अपनी सीमाओं में रहकर उसके साथ रिश्ता आगे बढ़ाएं, ध्यान रखें कि कोई आपको फ़ायदा उठाने की कोशिश न करे.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
यह सप्ताह आपके लिए मिला जुला सा रहेगा. घर में किसी से बहस हो सकती है, इसलिए छोटी छोटी बातों को दिल से लगाना छोड़ दें. किसी दूसरे सोशल ग्रुप में शामिल होने का मौक़ा मिले तो कतई न हिचकिचाएं.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित ही चीन की एक और पॉलिसी है, जिसे रिंग ऑफ़ पर्ल्स का नाम दिया गया है. यह एक मिलिट्री डॉक्टराइन भी है.

चीन से संबंध दोधारी तलवार

फोटो–सुनील मल्होत्रा

इस कॉरपोरेट युग में हमें भी राज, काज, समाज और आवाज़ को परिवर्तित करने की ज़रूरत है. बीते माह भारत आए अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का जिस अंदाज़ में स्वागत हुआ, उन्होंने जो–जो कहा, सो–सो भारत ने मान लिया, लेकिन विकीलीक्स के खुलासे ने सारे किए–धरे पर पानी फेर दिया. फिर अफसोस भी हुआ कि आख़िर हमने ख़ुद को ओबामा के क़दमों में क्यों बिछा दिया. चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ की तीन दिवसीय भारत यात्रा के दरम्यान भी यही दिखा. चीन ने भारत से अपनी सारी बातें मनवा लीं और जब ख़ुद मानने की बारी आई तो चुप्पी साध ली. चीन के साथ भारत के रिश्ते हमेशा से दोधारी तलवार रहे हैं. 1962 के युद्ध के समय भी हिंदी–चीनी भाई–भाई से हमें छल लिया गया था. भारत को चीन के प्रति एक व्यवहारिक नज़रिया अपनाने की ज़रूरत है. चीन के वेन जियाबाओ भारत आए, व्यापार से संबंधित मुद्दों पर छोटे मोटे अनुबंध करके चले गए और हम मुंह ताक़ते रह गए.

वैसे भी चीन के प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ की भारत यात्रा से ज़्यादा उम्मीदें नहीं थीं. यह यात्रा असहमतियों पर सहमति के साथ ख़त्म हो रही है. जियाबाओ ने तो साफ कह दिया कि दो महान राष्ट्रों के बीच कुछ मसलों पर असहमति स्वाभाविक है. ठीक यही भाव उनका तब भी था, जब उन्होंने कहा कि दुनिया में चीन व भारत दोनों के लिए जगह है. इस पर हमारे प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का स्वर ज़्यादा सकारात्मक था. उन्होंने कहा कि चीन और भारत जैसे दो बड़े देश साथ बोलते हैं तो दुनिया ग़ौर से सुनती है. लेकिन साथ बोलने की हद तक जाने से चीन के प्रधानमंत्री ने इंकार कर दिया. भारत और चीन ने हालांकि छह समझौतों पर हस्ताक्षर किए, लेकिन एक भी ऐसा नहीं है, जो दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाता हो. संयुक्त बयान में भी ऐसा कोई संदेश नहीं है, जिसे दुनिया ग़ौर से सुनकर सार्थक अर्थ निकाले. जो देश आतंकवाद के ख़िलाफ़ साफ संदेश देने को राजी नहीं है, उससे और क्या उम्मीद की जाए. कश्मीर के भारतीय नागरिकों को नत्थी वीजा देने के सवाल पर वेन ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि अधिकारी तय कर लेंगे. ज़ाहिर है एशिया के शक्ति संतुलन में पाकिस्तान अब भी चीन के लिए बड़ा मोहरा है. इसलिए पाक से आतंक के निर्यात की बात हो या कश्मीर विवाद की, वेन जियाबाओ ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे भारत का पलड़ा भारी होता. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के भारत के दावे पर भी चीनी प्रधानमंत्री ने कुछ स्पष्ट नहीं किया.

दोनों देशों के बीच व्यापारिक समझौता ज़रूर हुआ है, जिसे फ़िलहाल 60 अरब डॉलर से 2015 तक 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. हालांकि यह लक्ष्य अव्यवहारिक नहीं है, क्योंकि 2004 में 13.6 अरब डॉलर से बढ़कर 2010 में यह 60 अरब डॉलर हो सकता है, तो अगले पांच सालों में 100 अरब डॉलर होना मुश्किल नहीं होगा. अब इन दो देशों के बीच के व्यापार की सच्चाई भी जान लेनी आवश्यक है. बैलेंस ऑफ़ ट्रेड चीन की ओर झुका हुआ है. यह कुल 16 बिलियन डॉलर है, जो कि भारत के किसी भी देश के साथ बैलेंस ऑफ़ ट्रेड से अधिक है. चीन का मानना है की ऐसा इसलिए है, क्योंकि भारत की कंपनियां चीन में इन्वेस्ट करने से डरती हैं. और ऐसा है भी. फिक्की चीन को लेकर हमेशा से ही संशय में रहा है. इसके कई कारण हैं. समझने और देखने की बात यह है कि गत वर्ष में भारत ने चीन के विरुद्ध डब्लूटीओ में इतनी याचिकाएं और शिक़ायतें डालीं कि यह किसी एक देश द्वारा किसी और देश के ख़िलाफ़ सबसे अधिक थीं. भारत को चीनी खिलौनों से लेकर दूध तक बैन करना पड़ा, क्योंकि इनमें मिलावट बहुत ज़्यादा थी. समझने वाली बात यह है कि चीनी मोबाइल फ़ोनों ने भारतीय सुरक्षा को ही ख़तरे में डाल दिया. इनमें आइएमईआई नंबर नहीं होता है, जिस कारण से इन्हें ट्रैक करना नामुमकिन हो जाता है. इन्हें भी बैन करना पड़ा. चीन ने भारत को अपना सड़ा–गला माल डंप करने का एक आसान ठिकाना बना लिया है. डंपिंग का मतलब होता है कि अपने बाज़ार में बना सस्ता सामान दूसरे देश में फेंक देना. इसी कारण भारत में खिलौनें आदि का लोकल कारोबार आज बदहाली में चला गया है. चीन ने इस बात का फ़ायदा उठाने की कोशिश की, कि उसके यहां गवर्मेंट कि दबंगई की वजह से लेबर क़ानून और भत्ता क़ानून नहीं हैं और वह कम दाम में सस्ता और घटिया सामान बना कर बाहर देशों में भेज सकता है. भारत का हाथ करघा उद्योग जहां आज़ादी के पहले अंग्रेजों से त्रस्त था, वहीं आज चीन की मार झेल रहा है. ग्वांगझो चीन का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और यहां भारत के भी कई कारखाने हैं, जैसे कि गोदरेज तालों की फैक्ट्री. लेकिन अब ट्रेंड बदल रहा है. चीन भी बदल रहा है. अब कारीगर और मज़दूर महंगे हो गए हैं. सालों दुर्दशा सहने के बाद अब ट्रेड यूनियनें भी भड़ास निकाल रहीं हैं. वह अपना हक़ मांगने लगीं हैं. इन सारे कारणों की वजह से मज़दूर की लागत बढ़ गई है, और अब चीनी व्यापारी इस बात पर गहन विचार कर रहे हैं कि अपनी फैक्ट्रियां भारत में उठा लाएं.

वेन की इस भारत यात्रा से यह निष्कर्ष निकालना शायद ग़लत नहीं होगा कि भारत को अपने एक अडिग और हठी पड़ोसी के साथ मित्रता निभाना सीखना ही होगा. इससे इंकार नहीं कि चीनी प्रधानमंत्री की नई दिल्ली यात्रा दोनों देशों के आर्थिक–व्यापारिक संबंधों को गति प्रदान करेगी, लेकिन आपसी विश्वास बढ़ने वाला नहीं है. लगता है कि चीन यह बुनियादी बात समझने के लिए तैयार नहीं कि आपसी विश्वास के अभाव में वास्तविक मैत्री भाव नहीं पनप सकता. यह ख़ेदजनक है कि चीन सीमा विवाद के ज़रिए भारत को उलझाए रखने की नीति पर चलता दिख रहा है. वेन ने सीमा विवाद को जिस तरह इतिहास की देन क़रार देते हुए यह कहा कि इस सवाल का पूरा जवाब खोजना आसान नहीं, उसका अर्थ यही है कि चीन इस मुद्दे को हल करने के प्रति तनिक गंभीर नहीं है. चीन न केवल भारत को कमतर समझ रहा है, बल्कि वह अपनी इस समझ का प्रदर्शन भी कर रहा है. नि:संदेह ऐसा करके चीन अपने अहंकार का प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन बेहतर हो कि वह यह समझे कि दोनों देशों के ऐसे रिश्ते ख़ुद उसके भी हित में नहीं हैं. दोनों देशों में आपसी विश्वास की कमी कभी भी तनाव को जन्म दे सकती है और यह तनाव आर्थिक–व्यापारिक रिश्तों को प्रभावित करने के साथ हथियारों की होड़ को भी जन्म दे सकता है.

अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित ही चीन की एक और पॉलिसी है, जिसे रिंग ऑफ़ पर्ल्स का नाम दिया गया है. यह एक मिलिट्री डॉक्टराइन भी है. चीन अपने पश्चिम एशिया और अफ्रीका से होने वाले व्यापार को और संगठित करने के लिए इंडियन ओशियन से लगे भारत को घेरने वाले देशों के साथ संधि और समझौते कर रहा है, ताकि एक ओर तो व्यापार सुरक्षित हो जाए और दूसरी तरफ़ भारत को सामरिक रूप से घेरा जा सके. इसी जद्दोजहद में चीन ने श्रीलंका, बांग्लादेश, उत्तरी कोरिया और वियतनाम में भारी भरकम पूंजी निवेश किया है. यहां तक कि ईरान में भी चीनी कंपनियों के आगे भारतीय कंपनियां हार गईं. चीनियों को भारत की अमेरिका से दोस्ती भी रास नहीं आ रही है. ओबामा के आने के बाद अब वेन जिआबाओ आ गए भारत. लेकिन उनके आने के बाद ही रिपोर्ट आनी शुरू हो गई कि भारत के नक़्शे से चीन ने 1000 मील लंबा एरिया ग़ायब कर दिया. कुल लब्बोलुआब यह है कि चीन से सावधान रहने की आवश्यकता है. चीन आज भारत के व्यापार को ख़त्म करने पर लगा है. भारत के आतंरिक व्यापार और लघु उद्योगों को चीन के सस्ते माल के आक्रमण से बचाने की ज़रूरत है. साथ ही अब इस तरह लचीले रुख़ से काम नहीं चलने वाला. इसलिए भारत को चाहिए कि वह या तो ख़ुद को चीन से ज़्यादा शक्ति संपन्न करे या अपना रुख़ बदले.

राजीव रंजन/ सिद्धार्थ राय
feedback@chauthiduniya.com

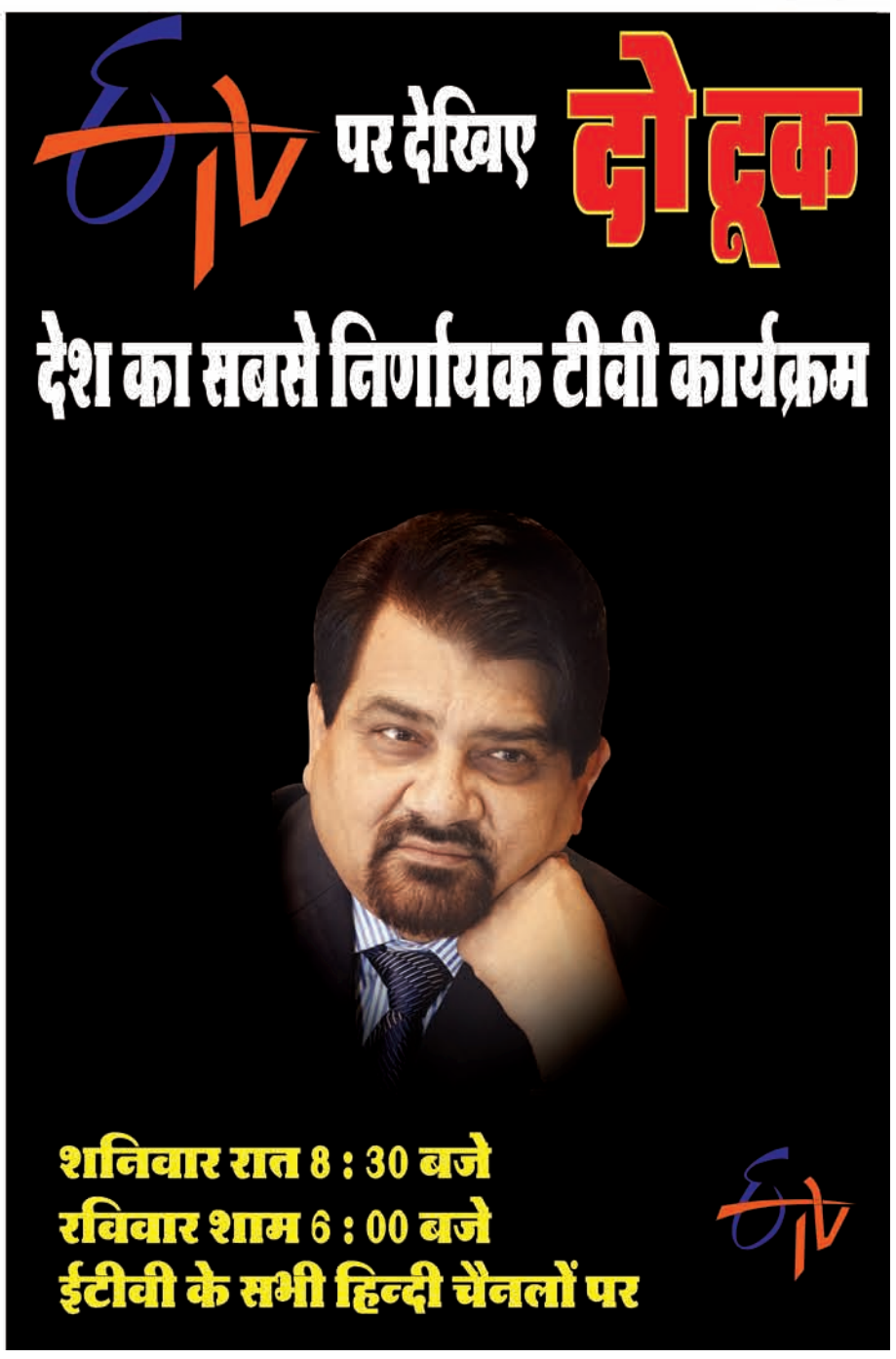

एक से प्यार और दूसरे से नफरत उचित नहीं है. कर्मों का फल तो भोगना ही होगा, सुख या दुःख. इंसान को चाहिए कि वह ऐसे कर्म न करे.

सर्वधर्म समभाव का संदेश

अहमद नगर ज़िले का शिरडी गांव अर्सा पहले केवल पोस्टल पहचान रखता था. वही गांव आज साई बाबा की शिरडी के नाम से दुनिया भर में जाना जाता है. बाबा की शिरडी में भक्तों का मेला हमेशा लगा रहता है. यहां आने वालों की तादाद प्रतिदिन 30-35 हज़ार के क़रीब होती है, वहीं गुरुवार एवं रविवार को यह संख्या दोगुनी हो जाती है. इसी तरह रामनवमी, गुरु पूर्णिमा और विजयादशमी के अवसर पर यहां 2-3 लाख लोग दर्शन को आते हैं, वहीं साल भर में लगभग एक करोड़ से अधिक भक्त यहां हाज़िरी लगा जाते हैं. लगभग डेढ़ सौ साल पहले एक युवा फकीर शिरडी की एक खंडहरनुमा मस्जिद में डेरा डालकर चार घरों की भिक्षा से गुजर-बसर करने लगा. लोगों ने उसे साई बाबा के नाम से पुकारा. उसके द्वारा दी जाने वाली जड़ी-बूटियों एवं अंगारे से लोग भले-चंगे होने लगे. इससे लोगों का विश्वास बढ़ता गया और साई बाबा का यश आहिस्ता-आहिस्ता दुनिया भर में फैल गया.

साई बाबा ने अपनी ज़िंदगी में समाज को दो अहम संदेश दिए. पहला संदेश है, सबका मालिक एक और दूसरा श्रद्धा और सबूरी. साई बाबा के इर्द-गिर्द के तमाम चमत्कारों से परे केवल उनके संदेशों पर ही ग़ौर करें तो पाएंगे कि बाबा के कार्य और संदेश जनकल्याणकारी साबित हुए हैं. इन संदेशों ने केवल कथनी से ही नहीं, बल्कि सीधे कार्य व व्यवहार से सारे समाज को अपना कायल बनाया. फकीर के वेश में मस्जिद में रहने वाले साई की बोली भी उर्दू मिश्रित थी. वह हमेशा अल्ला मालिक सबका भला करेगा कहते थे, लेकिन जिस मस्जिद में उनका निवास था, उसे वह द्वारकामाई कहकर पुकारते थे. साई बाबा का आचार धर्म हिंदू पद्धति का था. बावजूद इसके बाबा ने अपनी जाति एवं धर्म की थाह कभी किसी को लगने नहीं दी. हिंदू-मुस्लिम दोनों ने ही बाबा को अपना माना. उन्होंने सर्वधर्म समभाव और सह अस्तित्व का मार्ग पूरी दुनिया के सामने रखा. सबका मालिक एक, यह संदेश उनके व्यवहार का ही प्रतीक कहा जा सकता है.

साई बाबा ने अपनी ज़िंदगी में समाज को दो अहम संदेश दिए. पहला संदेश है, सबका मालिक एक और दूसरा श्रद्धा और सबूरी. साई बाबा के इर्द-गिर्द के तमाम चमत्कारों से परे केवल उनके संदेशों पर ही ग़ौर करें तो पाएंगे कि बाबा के कार्य और संदेश जनकल्याणकारी साबित हुए हैं.

बाबा के भक्तों में सभी जाति, धर्म एवं पंथ के लोग शामिल हैं. हिंदू बाबा के चरणों में हार-फूल चढ़ाते और समाधि पर दूब रख अभिषेक करते हैं, वहीं मुस्लिम बाबा की समाधि पर चादर चढ़ा सब्ज चढ़ाते हैं. कुल मिलाकर शिरडी सर्वधर्म समभाव के धार्मिक सह अस्तित्व का महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन यहां आने वाले भक्त इन सबसे परे केवल मन में बाबा के प्रति श्रद्धा और विश्वास के चलते खिंचे चले आते हैं. उनके मन में आध्यात्मिक शांति की चाह के साथ सुख की कामना नज़र आती है. इंसान अपनी श्रद्धा को हमेशा निजी सुख-दुःख से जोड़कर देखता आया है. आज के बदलते आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संक्रमण के दौर में अपने इर्द-गिर्द की अस्थिरता, अनिश्चितता के बीच भक्त कभी-कभी कुछ हकबकाहट में साई बाबा के प्रति श्रद्धा की महीन डोर थामे शिरडी चला आता है, जहां उसके तमाम सवालों के जवाब मिल जाते हैं.

साई बाबा द्वारा बताए श्रद्धा और सबूरी शब्दों का इस्तेमाल कई भक्त उनका आशीर्वाद पाने के लिए भी करते हैं. जैसे किसी को कोई नया काम हाथ में लेना हो तो वह श्रद्धा, सबूरी, हां या नहीं जैसी चार चिट्ठियां तैयार कर साई बाबा के सम्मुख रखता है और श्रद्धापूर्वक उसमें से एक चिट्ठी खोलता है. यदि उसमें हां है तो बाबा का आशीर्वाद मान लेता है और यदि जवाब नहीं में मिलता है तो बाबा का इंकार मान नए काम का इरादा छोड़ देता है. यदि चिट्ठी का जवाब श्रद्धा है तो बाबा में श्रद्धा रख काम आगे शुरू किया जाता है, लेकिन यदि जवाब सबूरी हो तो थोड़ा संयम रखें, ऐसा अर्थ निकाला जाता है. बाबा का आशीर्वाद पाने वाले ऐसे कई भक्त शिरडी में मिल जाएंगे. गत ढाई-तीन दशकों से साई बाबा के प्रति लोगों की आस्था में निरंतर इज़ाफ़ा हो रहा है. यही वजह है कि साई बाबा के उत्सव में शामिल होने अमीर-ग़रीब और सभी जाति-धर्म के भक्त बड़ी तादाद में आते हैं. जय श्री साई राम.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

आरती श्री शिरडी के साई बाबा की

आरती श्री साई गुरूवर की, परमानंद सदा सुरवर की
जाकी कृपा विपुल सुखकारी, दुख, शोक, संकट, भयहारी
शिरडी में अवतार रचाया, चमत्कार से तत्व दिखाया
कितने भक्त चरण पर आए, वे सुख शांति चिरतंन पाए
भाव धरे मन में जैसा, पावत अनुभव वो ही वैसा
गुरू की लगावे तन को, समाधान लाभत उस मन को
साई नाम सदा जा गावे, सो फल जग में शाश्वत पावे
गुरूबारसर करि पूजा सेवा, उस पर कृपा करत गुरुदेवा
राम, कृष्ण, हनुमान रूप में, दे दर्शन जानत जो मन में
विविध धर्म के सेवक आते, दर्शन से इच्छित फल पाते
जय बोलो साई बाबा की, जय बोलो अवधूत गुरू की
साईदास आरती को गावे, घर में बसि सुख मंगल पावे.

सुख-दुःख इंसान के रिश्तेदार हैं

असफलता केवल यही सिद्ध करती है कि सफलता के लिए पूरे प्रयास नहीं किए गए.
स्व. मालती कपूर

कई जगह पढ़ने को मिल जाता है कि सुख और दुःख एक सिक्के के दो पहलू हैं. एक बार टीवी पर साई बाबा पर आधारित धारावाहिक आ रहा था. साई बाबा ने कहा कि सुख और दुःख इंसान के दो रिश्तेदार हैं. सुखों से इंसान ख़ुद रिश्तेदारी रखना चाहता है और उन्हें पाने के लिए हर उपाय करता है. दुःख स्वयं ही इंसान के रिश्तेदार बन जाते हैं और उसे रिश्तेदारी निभाने को बाध्य करते हैं. इंसान दुःख से दूर रहने की हरसंभव कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी परछाईं बन जाता है. इंसान बहुत प्रयत्न करता है दुःखों से छुटकारा पाने का, पर दुःख उसका पीछा नहीं छोड़ते. आख़िर इन दुःखों के लिए इंसान ख़ुद ही तो ज़िम्मेदार है. उसके पूर्व जन्मों का फल हैं सुख और दुःख. बाबा ने कहा, इंसान को सुख और दुःख दोनों को समान रूप से देखना चाहिए. एक से प्यार और दूसरे से नफरत उचित नहीं है. कर्मों का फल तो भोगना ही होगा, सुख या दुःख. इंसान को चाहिए कि वह ऐसे कर्म न करे, जिससे उसके खाते में दुःख जमा हों. अब तक जो दुःख जमा हो चुके हैं, वे तो भुगतने ही पड़ेंगे, पर आगे से इंसान को सावधानी बरतनी चाहिए. इंसान को हर समय ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, इससे वह ग़लत कर्म करने से बचा रहेगा. जब ईश्वर उसके ध्यान में होंगे तो ग़लत कर्म तो उससे नहीं हो सकते. ग़लत कर्म तो तब होते हैं, जब इंसान ईश्वर को भूल जाता है और अहंकार वश ख़ुद को बहुत बड़ा समझने लगता है.

बचपन में आपने स्कूल की किताबों में भी पढ़ा होगा:
दुःख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय,
जो सुख में सुमिरन करें तो दुःख काहे को होय.

कितनी सीधी और सच्ची बात है, पर इंसान न जाने किस उलटफेर में लगा रहता है, दुःखों को अपना रिश्तेदार बना लेता है और जीवन भर रोता रहता है. इसलिए अगर दुःख से बचना है तो उसे स्वीकार करना सीखें. फिर आप देखेंगे कि सुख और दुःख एक हवा के झोंके के समान आपके जीवन में आते-जाते रहेंगे.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

साहित्य अकादमी में सौदेबाज़ी का एक भरा पूरा इतिहास रहा है. जब गोपीचंद नारंग का अकादमी के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल ख़त्म हुआ तो उन पर दवाब बना कि वह दूसरी बार चुनाव न लड़ें.

उदय प्रकाश नहीं थे पहली पसंद

अनंत विजय

इस वर्ष के साहित्य अकादमी पुरस्कारों का ऐलान हो गया है. हिंदी के लिए इस बार का अकादमी पुरस्कार यशस्वी कथाकार और कवि उदय प्रकाश को उनके उपन्यास मोहनदास (वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली) के लिए दिया गया. उदय प्रकाश साहित्य अकादमी पुरस्कार डिज़र्व करते हैं, बल्कि उन्हें तो अरुण कमल, राजेश जोशी और ज्ञानेन्द्रपति से पहले ही यह सम्मान मिल जाना चाहिए था. जब मैंने पुरस्कार के ऐलान होने के दो दिन पहले अपने ब्लॉग पर इस बारे में लिखा तो जूरी के सदस्य मुझसे ख़फ़ा हो गए. मैंने अपने ब्लॉग– हाहाकार– पर पुरस्कार के चयन के लिए हुई बैठक में जो बातें हुईं, जो सौदेबाज़ी हुई, उस पर लिखा था. पहले मैंने तय किया था कि इस विषय पर अब और नहीं लिखूंगा, लेकिन जब मुझे परोक्ष रूप से धमकी मिली तो मैंने तय किया कि और बारीक़ी से सौदेबाज़ी को उजागर करूंगा. जो कि न केवल अकादमी के हित में होगा, बल्कि इससे हिंदी का भी भला होगा. इस बार के पुरस्कार के चयन के लिए जो आधार सूची बनी थी, उसमें रामदरश मिश्र, विष्णु नागर, नासिरा शर्मा, नीरजा माधव, शंभु बादल, मन्नू भंडारी और बलदेव वंशी के नाम थे. हिंदी के संयोजक विश्वनाथ तिवारी की इच्छा और घेरेबंदी रामदरश मिश्र को अकादमी पुरस्कार दिलवाने की थी. इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अशोक वाजपेयी, मैनेजर पांडे और चित्रा मुद्गल का नाम जूरी के सदस्य के रूप में प्रस्तावित किया और अध्यक्ष से स्वीकृति दिलवाई. लेकिन पता नहीं तिवारी जी की रणनीति क्यों फेल हो गई. जब पुरस्कार तय करने के लिए जूरी के सदस्य बैठे तो रामदरश मिश्र के नाम पर चर्चा तक नहीं हुई. बैठक शुरू होने पर अशोक वाजपेयी ने सबसे पहले रमेशचंद्र शाह का नाम प्रस्तावित किया. लेकिन उस पर मैनेजर पांडे और चित्रा मुद्गल दोनों ने आपत्ति की. कुछ देर तक बहस चलती रही, जब अशोक वाजपेयी को लगा कि रमेशचंद्र शाह के नाम पर सहमति नहीं बनेगी तो उन्होंने नया दांव चला और उदय प्रकाश का नाम प्रस्तावित कर दिया. ज़ाहिर सी बात है कि मैनेजर पांडे को फिर आपत्ति होनी थी, क्योंकि वो उदय प्रकाश की कहानी पीली छतरी वाली लड़की को भुला नहीं पाए थे. उन्होंने उदय के नाम का पुरज़ोर तरीक़े से विरोध किया. पांडे जी के मुखर विरोध को देखते हुए उनसे उनकी राय पूछी गई. मैनेजर पांडे ने मैत्रेयी पुष्पा का नाम लिया और उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की वकालत करने लगे. मैनेजर पांडे के इस प्रस्ताव पर अशोक वाजपेयी ख़ामोश रहे और उन्होंने चित्रा मुद्गल से उनकी राय पूछी. बजाए किसी लेखक पर अपनी राय देने के चित्रा जी ने फटाक से अशोक वाजपेयी की हां में हां मिलाते हुए उदय प्रकाश के नाम पर अपनी सहमति दे दी. इस तरह से अशोक वाजपेयी की पहली पसंद न होने के बावजूद उदय प्रकाश को एक के मुक़ाबले दो मतों से साहित्य अकादमी पुरस्कार देना तय किया गया. उधर हिंदी भाषा के संयोजक विश्वनाथ तिवारी का सारा खेल ख़राब हो गया और रामदरश मिश्र का नाम आधार सूची में सबसे ऊपर होने के बावजूद उनको पुरस्कार नहीं मिल पाया. यहां यह भी बताते चलें कि उदय प्रकाश और रमेशचंद्र शाह दोनों के ही नाम हिंदी की आधार सूची में नहीं थे. लेकिन यहां कुछ ग़लत नहीं हुआ, क्योंकि जूरी के सदस्यों को यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि वे, जिस वर्ष पुरस्कार दिए जा रहे हों उसके पहले के एक वर्ष को छोड़कर पिछले तीन वर्षों में प्रकाशित कृति प्रस्तावित कर सकते हैं. इस वर्ष दो हज़ार छह, सात और आठ में प्रकाशित कृति में से चुनाव होना था.

मैं पिछले कई वर्षों से साहित्य अकादमी के पुरस्कारों में होने वाली गड़बड़ियों और घेरेबंदी पर लिखता रहा हूं. वहां कई ऐसे उदाहरण हैं, जहां घेरेबंदी कर पुरस्कार दिलवाए गए. जब हिंदी के कवि वीरेन डंगवाल को उनके कविता संग्रह दुष्चक्र में स्रष्टा पर पुरस्कार दिया गया तो उस वक़्त के हिंदी के संयोजक गिरिराज किशोर पर सारे नियम क़ानून ताक पर रखकर डंगवाल को पुरस्कृत करने के आरोप लगे थे. गिरिराज किशोर ने वीरेन डंगवाल को पुरस्कार दिलवाने के लिए श्रीलाल शुक्ल, कमलेश्वर और से. रा. यात्री की जूरी बनाई. जब नियत समय पर जूरी की बैठक होनी थी, उस वक़्त कमलेश्वर बीमार हो गए और श्रीलाल शुक्ल जी को बनारस (अगर मेरी स्मृति मेरा साथ दे रही है तो) से दिल्ली आना था और किन्हीं वजहों से उनका जहाज छूट गया और वह नहीं आ पाए. पुरस्कार का ऐलान करवाने की इतनी जल्दी थी कि से. रा. यात्री को कमलेश्वर के पास भेजकर अस्पताल से उनसे लिखवाकर मंगवाया गया. श्रीलाल जी से फैक्स पर उनकी राय मंगवाई गई और फिर से. रा. यात्री और गिरिराज किशोर ने दोनों की सहमति के आधार पर वीरेन डंगवाल का नाम तय कर दिया. सवाल यह उठा कि गिरिराज जी की क्या बाध्यता थी कि वह पुरस्कार की घोषणा कर दें. अगर आप अकादमी के स्वर्ण जयंती के मौक़े पर प्रकाशित डी.एस. राव की किताब, साहित्य अकादमी का इतिहास देखें तो उसमें कई ऐसे प्रसंग हैं, जहां कि पुरस्कार का ऐलान रोका गया और बाद में उसको घोषित किया गया. वीरेन डंगवाल की प्रतिभा पर किसी को शक़ नहीं था और न ही है, वह हिंदी के एक महत्वपूर्ण कवि हैं, लेकिन जिस तरह से जल्दबाज़ी में जूरी के दो सदस्यों की अनुपस्थिति में उनका नाम तय किया गया, उस वजह से पुरस्कार संदेहास्पद हो गया. हालांकि उस वक़्त विष्णु खरे, भगवत रावत, विजेन्द्र और ऋतुराज भी दावेदार थे, जो किसी भी तरह से वीरेन डंगवाल से कमज़ोर कवि नहीं हैं.

साहित्य अकादमी में सौदेबाज़ी का एक भरा पूरा इतिहास रहा है. जब गोपीचंद नारंग का अकादमी के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल ख़त्म हुआ तो उन पर दबाव बना कि वह दूसरी बार चुनाव न लड़ें. चौतरफ़ा दबाव में उन्होंने चुनाव तो नहीं लड़ा पर अपने कैंडिडेट को अध्यक्ष बनवाने में कामयाब रहे. जब हिंदी भाषा के संयोजक के चुनाव का वक़्त आया तो गोपीचंद नारंग विश्वनाथ तिवारी को बनाना चाहते थे, लेकिन कैलाश जोशी ने फच्चर फंसा दिया और वो भी चुनाव लड़ने को तैयार हो गए. उस वक़्त आपसी समझदारी में यह तय हुआ कि कैलाश जोशी चुनाव नहीं लड़ेंगे, बदले में उनको अकादमी का पुरस्कार दिया जाएगा. उन्हें यह भी समझा दिया गया कि अगर वह भाषा के संयोजक हो जाएंगे तो उनको पुरस्कार नहीं मिल पाएगा. पुरस्कार मिलने के आश्वासन के बाद कैलाश जोशी ने चुनाव नहीं लड़ा और विश्वनाथ तिवारी हिंदी भाषा के संयोजक बन गए. उन्होंने अपने संयोजकत्व में पहला पुरस्कार गोविंद मिश्र को दिया और अगले वर्ष कैलाश जोशी को उनकी कृति हवा में हस्ताक्षर के लिए पुरस्कार मिला. अब वक़्त आ गया है कि अकादमी के पुरस्कारों में पूरी पारदर्शिता बरती जाए और जूरी के सदस्यों के नाम के साथ-साथ उनकी राय को भी सार्वजनिक किया जाए. पहले तो जूरी के सदस्यों का नाम भी गोपनीय रखा जाता था, लेकिन बाद में उसे सार्वजनिक किया जाने लगा. अब तो अकादमी को जूरी की बैठक की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवानी चाहिए, ताकि पारदर्शिता के उच्च मानदंडों को स्थापित किया जा सके. मुझे याद है कि जब साहित्य अकादमी का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जा रहा था तो विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में अकादमी के तत्कालीन अध्यक्ष गोपीचंद नारंग ने अपने भाषण में नेहरू जी को उद्धृत करते हुए कहा था कि मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री अकादमी के कामकाज में दख़ल नहीं देंगे. नारंग के इस मत पर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सहमति जताई थी. उस वजह से ही अकादमी में तमाम गड़बड़ियों के आरोप से घिरे गोपीचंद नारंग अपने कार्यकाल के आख़िर तक डटे रहे थे. लेकिन जहां स्वायत्ता आती है, वहां ज़िम्मेदारी भी साथ-साथ आती है. यह अकादमी के कर्ता-धर्ताओं का दायित्व है कि जहां भी संदेह के बादल छाने लगें, उसे तथ्यों को सामने रखकर साफ़ करें. पुरस्कारों के मामले में तो यह तभी हो सकता है, जब चयन से लेकर जूरी की मीटिंग और उसकी कार्यवाही पूरी तरह से पारदर्शी हो और जो चाहे वह इस बाबत अकादमी से सूचना प्राप्त कर सके. तभी देश की इस सबसे बड़े साहित्यिक संस्था की साख बची रह सकेगी.

(लेखक आईबीएन-7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

ज़िला फर्रूखाबाद के अताईपुर गांव में जन्मे इदरीस निज़ामी पिछले कई सालों से गीत-संगीत के ज़रिए आवाम के बीच सांप्रदायिक सद्भाव और कौमी एकता का पैगाम पहुंचा रहे हैं. उनके इस सफर में उनकी बेगम शाहेदा ख़ान भी हमसफर है. जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण भजन से शुरू हुआ उनका सफर आज देश के कोने-कोने तक पहुंच चुका है. पिछले दिनों वह दिल्ली में थे और उस दौरान चौथी दुनिया संवाददाता शशि शेखर ने उनसे लंबी बातचीत की. पेश हैं मुख्य अंश:

संगीत सच्चा जादू था, है और रहेगा : इदरीस निज़ामी

संगीत के ज़रिए सांप्रदायिक सद्भाव और कौमी एकता का संदेश फैलाने की बात कब आपके जेहन में आई और अब तक का सफर कैसा रहा?

स्टेज पर पहला प्रोग्राम जन्माष्टमी में किया था. फिर मुंबई चला गया. 1986 में शाहेदा ख़ान से शादी हुई. उसके बाद वह भी हमारे हिंदू-मुस्लिम एकता के अभियान से जुड़ गईं. जिस तरह से लोग अपनी-अपनी फैक्ट्रियां लगाते हैं, अपना व्यापार फैलाते हैं, वैसे ही हमने कौमी एकता की जड़ें मज़बूत करने का काम किया है और आज भी कर रहे हैं. हमें फ़क्र है कि हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक गए है. बाघा बॉर्डर पर गए. कभी लखनऊ, इलाहाबाद और बिहार में तो कभी हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र गए. हम हर प्रांत में जाने को तैयार रहते हैं. हमारे कार्यक्रम कौमी एकता के लिए हो रहे हैं. हम भारतीय हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई एकता समिति के प्रेसिडेंट है और उसके माध्यम से हम कार्यक्रम पेश करते रहते हैं.

कभी ऐसा हुआ कि देश में सांप्रदायिक माहौल ख़राब रहा हो और इस दौरान आपने कोई कार्यक्रम किया हो? इससे जुड़ी कुछ यादों के बारें में बताएं?

92 -93 के दौरान जब मुंबई का माहौल ख़राब हुआ था. तब सबसे ज़्यादा हमने ही मुबंई में काम किया. उस दौरान हमारी बेगम मुबंई महानगर पालिका में कॉरपोरेटर थीं. हम दोनों रोड पर आए और संगीत के ज़रिए माहौल को सुधारने की कोशिश की. यह बात पूरा देश जानता है. हमारा हर क़दम देश के लिए है. यह जो अभी मंदिर-मस्जिद का झगड़ा है, मैं समझता हूं कि आने वाले पांच सालों में कोई भी झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि दिलों को मिलाने का काम जितना संगीत करता है, किसी नेता का भाषण नहीं कर सकता. उकता गई है जनता झूठे वादों से. संगीत सच्चा जादू था, है और रहेगा.

क्या कभी देश से बाहर जाकर कार्यक्रम पेश किया है?

देश से बाहर न गए हैं और न ही जाने की तमन्ना है. हमें बहुत से ऑफर आते हैं. कुछ दिन पहले ही कुवैत के लोग आए थे. कहने लगे बहुत सारा पैसा मिलेगा, मैंने कहा, नहीं चाहिए. हीरा-मोती, सोना-चांदी कुछ भी मिले रहने दो, भारत की मिट्टी भारत में रहने दो. जीयो और जीने दो. हमें गर्व है, हमें ख़ुशी है कि हम भारत में पैदा हुए. भारत दुनिया की जन्नत है. हम इसे जन्नत से बेहतर समझते हैं.

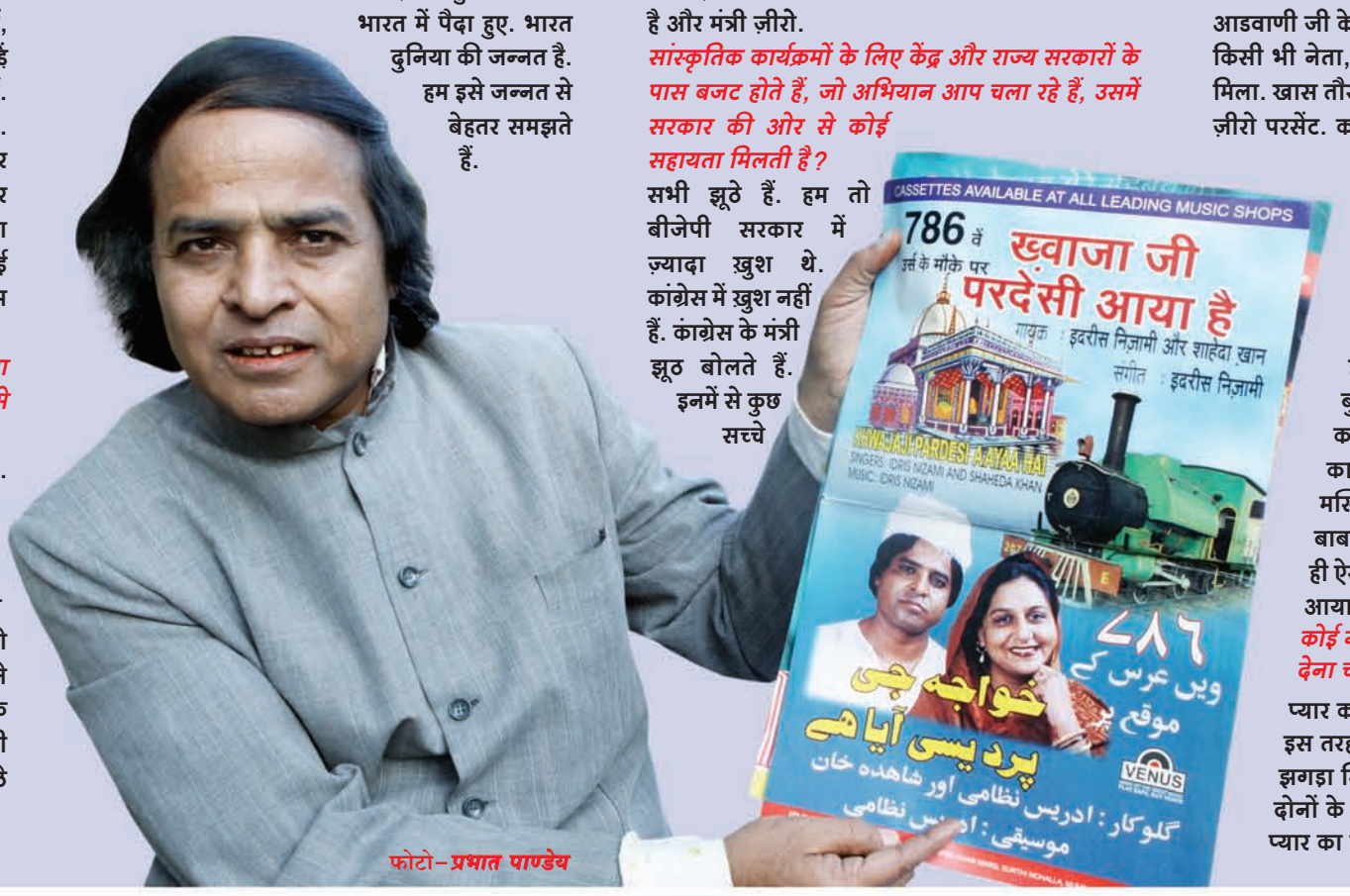

फोटो– प्रभात पाण्डेय

आपने अलग-अलग जगहों पर कार्यक्रम किए हैं, इस दरम्यान राज्य सरकारों का रुख़ कैसा रहा, सहयोग मिला?

राज्य सरकारें तो मुर्दा हैं. बजट आता है तो पता नहीं कहां चला जाता है. हमें तो यही नहीं पता है कि कौन सा मंत्री क्या है, और ये क्या करता है. हमारी नज़र में जनता हीरो है और मंत्री ज़ीरो.

सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के पास बजट होते हैं, जो अभियान आप चला रहे हैं, उसमें सरकार की ओर से कोई सहायता मिलती है?

सभी झूठे हैं. हम तो बीजेपी सरकार में ज़्यादा ख़ुश थे. कांग्रेस में ख़ुश नहीं हैं. कांग्रेस के मंत्री झूठ बोलते हैं. इनमें से कुछ सच्चे हैं. बाक़ी घर में बैठे रहते हैं और कहलवा देते हैं कि मीटिंग में गए हैं. उद्योगपतियों के साथ मीटिंग करते हैं, ग़रीबों के लिए समय नहीं है. ग़रीब आ जाए तो उसे दूर से ही भगा देते हैं. 77 में जब आडवाणी जी सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे तो उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो से हमारे प्रोग्राम के लिए सिफ़ारिश की थी. और वो प्रोग्राम हमें मिले भी. हम जनाब आडवाणी जी के शुक्रगुज़ार थे, हैं और रहेंगे. बाक़ी अभी किसी भी नेता, मंत्री या सरकार का कोई सहयोग नहीं मिला. ख़ास तौर पर कांग्रेस का कोई सहयोग नहीं मिला. ज़ीरो परसेंट. कांग्रेस वालों ने कभी नहीं पूछा कि आप प्रोग्राम कर रहे हो तो पैसे की ज़रूरत है क्या. बीजेपी ने पूछा, शिवसेना वालों ने पूछा, राज ठाकरे ने पूछा हमसे. ये तो खाली वादे करते हैं और साफ मुकर जाते हैं.

आगे की क्या योजनाएं हैं?

हम पूरे देश के शायरों और गायकों को बुलाएंगे. मीटिंग करेंगे. देश भर में अपने कार्यक्रम करते रहेंगे. अब आवाम रोटी और कारोबार के चक्कर में ज़्यादा है. मंदिर मस्जिद के बारे में कोई नहीं सुनना चाहता. बाबा आदम से लेकर आदम हव्वा तक संगीत ही ऐसा जादू है, जो लोगों के दिलों को जोड़ता आया है.

कोई नज़्म, जिसके ज़रिए समाज को कोई संदेश देना चाहते हों?

प्यार का एक नया कानून बनाया जाए,
इस तरह दुनिया से नफरत को मिटाए,
झगड़ा मिटाए मंदिर और मस्जिद का,
दोनों के बीच मयखाना
प्यार का बनाया जाए

शशि शेखर
shashishekhar@chauthiduniya.com

एलजी ने हाल में कंप्यूटर सिस्टम के लिए मॉनीटर ई-90 मॉडल बाज़ार में उतारा है. यह एलजी का अब तक का स्लिमेस्ट मॉनीटर है, जिसकी डेप्थ 7.2 मिलीमीटर है.

बच्चों की फरारी

बच्चों के शौक देखते हुए दुनिया की जानी-मानी लग्ज़री कार निर्माता कंपनी फरारी ने अब बच्चों के लिए एक खास कार पेश की है. खास बात यह है कि इस कार को बच्चे आसानी से चला सकेंगे और इसके लिए किसी भी प्रकार के ईंधन की ज़रूरत नहीं होगी.

बच्चों की दुनिया अब बच्चों सी नहीं रह गई है. उनके खिलौने, उनके कपड़े, उनकी किताबें, उनके शौक, उनके अंदाज़ सब कुछ बदल गए. बच्चों में अब न ट्रेडीशनल व्यवहार है और न रुचि. आज के बच्चे ज़्यादा उत्सुक और स्मार्ट हैं. इनकी दुनिया में थोड़े-थोड़े अंतराल पर अगर कुछ नया न हो तो ये बोर हो जाते हैं. आजकल के बच्चों के शौक देखते हुए दुनिया की जानी-मानी लग्ज़री कार निर्माता कंपनी फरारी ने अब बच्चों के लिए एक ख़ास कार पेश की है. ख़ास बात यह है कि इस कार को बच्चे आसानी से चला सकेंगे और इसके लिए किसी भी प्रकार के ईंधन की ज़रूरत नहीं होगी. गो-कार्टिंग कारों के मॉडलों के आधार पर तैयार की गई. इस खास फरारी एफएक्सएक्स को पैडल से चलाया जाएगा. साथ ही इसमें कई बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स का भी इस्तेमाल किया गया है. स्टाइलिश लुक्स और असल फरारी जैसी फास्ट स्पीड वाली रॉयल कार अब बच्चों के पास भी होगी. बिना किसी खास मुश्किल के बच्चे इसकी राइड एन्जॉय कर पाएंगे. हालांकि यह अभी सभी बच्चों को आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाएंगी, क्योंकि कंपनी ने इस तरह की केवल 29 कारें तैयार की हैं. इस कार में 7 गियर दिए गए हैं. साथ ही स्पीड को मॉनीटर करने के लिए इसमें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगाया गया है. यानी स्पीड की मस्ती के साथ गियर वाली कार चलाने की ट्रेनिंग बच्चे को मिल जाएगी. इस कार की क़ीमत 2260 डॉलर यानी क़रीब एक लाख रुपये है.

एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्ट फोन

मोटोरोला ने एंड्रॉयड पोर्टफोलियो में भारतीय बाज़ार में एक नया मुक़ाम जोड़ दिया है. कंपनी ने हाल में एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल फोन लांच किया है. मोटोरोला क्वेंच भारतीय बाज़ार में एयरसेल नेटवर्क के साथ गठबंधन के तहत पेश किया गया है. इस मॉडल का दूसरा नाम मोटोरोला एक्स टी-5 है. एंड्रॉयड 2.1 एकलेयर के पावर के साथ इस मोबाइल में क्वालकॉम एमएसएम 7227 और 600 मेगाहर्ट्ज प्रोसेसर है. मोटोरोला क्वेंच एक्स टी-5 का बेहतरीन 3.2 इंच टीएफटी कैपिसीटिव टच स्क्रीन डिस्प्ले है. इसमें खास गोरिल्ला ग्लास डिस्प्ले दिया गया है, जिससे यूजर को बेस्ट टच परफार्मेंस मिलती है. अपने ख़ूबसूरत लम्हों को संजोने के लिए इसमें 5 मेगा पिक्सल कैमरा है. साथ ही अंधेरे में फोटो खींचना आसान बनाने के लिए एलईडी फ्लैश लाइट भी है. 256 एमबी रैम के साथ इसमें 512 एमबी इंटरनल मेमोरी है. अगर मोबाइल में ज़्यादा डाटा रखना है तो उसका विकल्प भी इसमें दिया गया है. इसकी मेमोरी को माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 32 जीबी तक एक्सपैंड किया जा सकता है. सभी मल्टी मीडिया फीचर्स के साथ इस मोबाइल फोन में एफएम रेडियो, ब्लुटुथ, ए2डीपी है. यह वाई-फाई को भी सपोर्ट करता है.

इसके दूसरे फीचर्स जैसे यूआई रोटेट के लिए एक्सेलोमीटर सेंसर, ऑटो टर्न ऑफ के लिए प्रोक्सीमिटी सेंसर, लाइव विजेट के साथ मोटोब्लर यूआई और कैपीसीटिव ट्रैकपैड एडवांटेज मोबाइल को खास बनाते हैं. मोटोरोला क्वेंच एक्स टी-5 13,990 रुपये में उपलब्ध है. कुछ अन्य लोकेशन बेस्ड सर्विसेज के साथ कंपनी ग्राहकों को छह महीने तक एयरसेल कंपनी के डाटा यूसेज मुफ्त उपलब्ध कराती है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

एमरॉन की हाईलाइफ बैट्री

अमर राजा बैट्री ने भारत में टेलीकॉम सेक्टर की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए एक विशेष प्रकार की बैट्री लांच की है. एमरॉन वोल्ट हाईलाइफ बैट्री हाई इंटेनसिटी सीरीज की 2-वी बैट्री है. तीन साल के एप्लीकेशन रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट एफर्ट के परिणामस्वरूप यह बैट्री आज बाज़ार में उपलब्ध हो सकी है. यह थ्री जी, बीडब्ल्यूए और मोबाइल इंटरनेट के इस दौर में भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री को स्पेशल स्टोरेज देने वाली बैट्री है. इंडस्ट्री के एप्लीकेशंस में पावर बैकअप की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक बढ़िया क्वालिटी की बैट्री की ज़रूरत थी. 2-वी हाई इंटेनसिटी बैट्री का निर्माण एमरॉन की तरफ़ लेटेस्ट वीआरएलए प्रोडक्ट के तौर पर किया गया है. विश्वसनीय पावर बैकअप वाली यह बैट्री दूरदराज और ग्रामीण इलाक़ों में भी आसानी से इस्तेमाल की जा सकती है. एडवांस फीचर्स के साथ एमरॉन वोल्ट बैट्री टेलीकॉम, ब्रॉडबैंड, आईटी, पावर यूटीलिटी, सोलर पीवी एप्लीकेशंस और फास्ट स्पीडिंग रूरल टेलीकॉम मार्केट को फ़ायदा पहुंचा कर अपनी जगह बनाने में कामयाब होगी. यह जीरो मेंटेनेंस ऑपरेशन पर काम करती है और इसके ज्वाइंट्स लीक प्रूफ हैं, जिससे बैट्री की आधी परेशानी यूं ही दूर हो जाती है. अपने तरह की पहले बैट्री के लांच पर कंपनी के प्रमुख विजयानंद ने कहा कि 1990 के दशक से ही एमरॉन की वीआरएलए बैट्रीज लोगों के जीवन को सुलभ बनाती रही हैं. तबसे कंपनी नए-नए प्रोडक्ट बाज़ार में उतारती रही है. एमरॉन वोल्ट भी कामयाबी के नए शिखर को रोशन करेगी.

एलजी का ई-90 मॉनीटर

एलजी ई-90 आम सीसीएफएल बैकलिट एलसीडी मॉनीटरों से लगभग चालीस प्रतिशत ऊर्जा कम खपत करता है. इसे बनाने में हैलोजन और मरकरी जैसे ख़तरनाक पदार्थ भी कम लगते हैं, जिससे यूजर के बहुत इस्तेमाल के बाद भी स्वास्थ्य को कम नुक़सान पहुंचता है.

यह युग है स्लिम और स्मॉल का, चाहे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कोई हैपनिंग गैजेट और कंप्यूटर तो रेग्युलर इस्तेमाल की चीज है. इसलिए जमाने के हिसाब से कंप्यूटर का मॉडिफिकेशन और स्टाइलिश होना भी ज़रूरी है. एलजी ने हाल में कंप्यूटर सिस्टम के लिए मॉनीटर ई-90 मॉडल बाज़ार में उतारा है. यह एलजी का अब तक का स्लिमेस्ट मॉनीटर है, जिसकी डेप्थ 7.2 मिलीमीटर है. इसमें एक्शन मूवीज और स्पोर्टिंग मैच देखना काफी अच्छा अनुभव देगा. मॉनीटर का डिस्प्ले फास्ट मूविंग एक्शन सिक्वेंस में भी क्लीयर और ब्राइट रहता है. इसका ग्लॉसी बेस किसी भी चीज को ख़ूबसूरत व्यू देता है. इसमें लगे एलजी ईमेज बूस्टर सॉफ्टवेयर से यू ट्यूब या दूसरे स्ट्रीमिंग कंटेंट देखना आसान हो जाएगा. एलजी ई-90 आम सीसीएफएल बैकलिट एलसीडी मॉनीटरों से लगभग चालीस प्रतिशत ऊर्जा कम खपत करता है. इसे बनाने में हैलोजन और मरकरी जैसे ख़तरनाक पदार्थ भी कम लगते हैं, जिससे यूजर के बहुत इस्तेमाल के बाद भी स्वास्थ्य को कम नुक़सान पहुंचता है. एलजी मॉनीटर डिवीजन के वाइस प्रेसिडेंट सी वैन ने कहा कि ई-90 मॉनीटर एडवांस तकनीक और ख़ूबसूरत डिज़ाइन का बेजोड़ मेल है, जो परफेक्ट अलाइनमेंट में आता है. डिज़ाइन और पिक्चर क्वालिटी के अपने बेहतरीन फीचर्स की वजह से ई-90 सुपर एलईडी मॉनीटर स्टाइल और परफार्मेंस का उदाहरण है. इस खास मॉनीटर की क़ीमत लगभग 435 डॉलर है.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

भारतीय टीम में संभावित 30 खिलाड़ियों की सूची में महेंद्र सिंह धोनी के अलावा तीन और खिलाड़ियों को विकेट कीपर के नाम पर शामिल किया गया है.

विश्व कप और टीम इंडिया

कुमार सुशांत

विश्व कप 2007 में भारत सुपर-8 के दौर में भी पहुंचने में असफल रहा था. नतीजतन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टीम के कई सीनियर खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया. इसके बाद बोर्ड ने नए खिलाड़ियों को टीम में मौक़ा देने की योजना बनाई. 2007 में ही बीसीसीआई ने नए युवा खिलाड़ियों की ब्रिगेड तैयार करने का मन बना लिया था. और अब, 3 तीन साल बाद, आईसीसी के निर्देशानुसार, बीसीसीआई को विश्व कप में खेलने वाले 30 संभावित खिलाड़ियों की लिस्ट देनी थी. लिस्ट तैयार करते वक़्त ख़ुद बीसीसीआई को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या न करें. ऐसे में डर था कि कहीं चयन प्रक्रिया में कोई ग़लती न हो जाए. हुआ भी कुछ ऐसा ही. बोर्ड ने अपनी बेतुकी स्मार्ट नीतियों को लागू करते हुए, कुछ ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया, जिन्हें मौक़ा देना विश्वकप में नए एक्सपेरिमेंट जैसा है और कुछ ऐसे खिलाड़ियों को शामिल नहीं किया, जो मुश्किल परिस्थितियों में टीम इंडिया के तारनहार साबित होते रहे हैं. ताज्जुब इस बात का है कि बोर्ड ने भारतीय टीम में राहुल द्रविड़, इरफान पठान और रॉबिन उथप्पा जैसे खिलाड़ियों को अंडर 30 लायक़ भी नहीं समझा, शायद इसीलिए इन्हें विश्वकप के लिए संभावित 30 खिलाड़ियों की सूची में कोई जगह नहीं दी गई.

किसी भी टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है विपक्षी टीम के जल्द से जल्द 10 विकेट झटकना. इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास बेहतरीन तेज़ गेंदबाज़ हों. ऐसे तेज़ गेंदबाज़, जो न केवल गेंद को स्विंग कराने में सक्षम हों, बल्कि गेंदबाज़ी के अनुकूल पिच न होने के बावजूद बल्लेबाज़ों को तेज़ गेंद की धार से परेशान कर सकें. पाकिस्तान के शोएब अख्तर, ऑस्ट्रेलिया के मिशेल जॉनसन, श्रीलंका के लसिथ मलिंगा जैसे धुरंधर गेंदबाज़ अपनी इसी आक्रामकता की वजह से अपनी टीम को कई बार बचाने में सफल साबित होते रहे हैं. कहने का मतलब यह कि शुरुआती खेल में विपक्षी टीम के बल्लेबाज़ों पर अटैक के बाद इन तेज़ गेंदबाज़ों के कुछ ओवर अंतिम खेल के लिए बचाकर रखे जाते हैं, ताकि आख़िर में बल्लेबाज़ों को परेशान किया जा सके. रिकॉर्ड्स पर नज़र डालें तो टीम इंडिया इसी बिन्दु पर अक्सर कमज़ोर पड़ जाती है. इसी का नतीज़ा था कि दक्षिण अफ्रीका के ख़िलाफ़ सेंचुरियन टेस्ट मैच में भारतीय बल्लेबाज़, मोरने मोर्केल और डेल स्टेल जैसे अफ्रीकी तेज़ गेंदबाज़ों से सामने 136 रनों पर ही सिमट गए. हालांकि , पिछले चार सालों में आरपी सिंह, एस श्रीसंत, इशांत शर्मा और इरफान पठान जैसे कुछ गेंदबाज़ों ने भारतीय टीम के लिए एक उम्मीद की किरण जगाई है. लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इरफान पठान को विश्पकप टीम में कोई जगह नहीं मिली. क्या हम स्पिनर की मदद से केवल रन रोकने में सक्षम हो पाएंगे, वह भी तब, जब सेंचुरियन टेस्ट में हरभजन सिंह जैसा स्पिनर 2 विकेट पर 169 रन देकर सबसे महंगा साबित होता है.

टीम इंडिया की बल्लेबाज़ी के लिए सबसे बड़ा परेशानी का सबब है पिच की रुपरेखा.

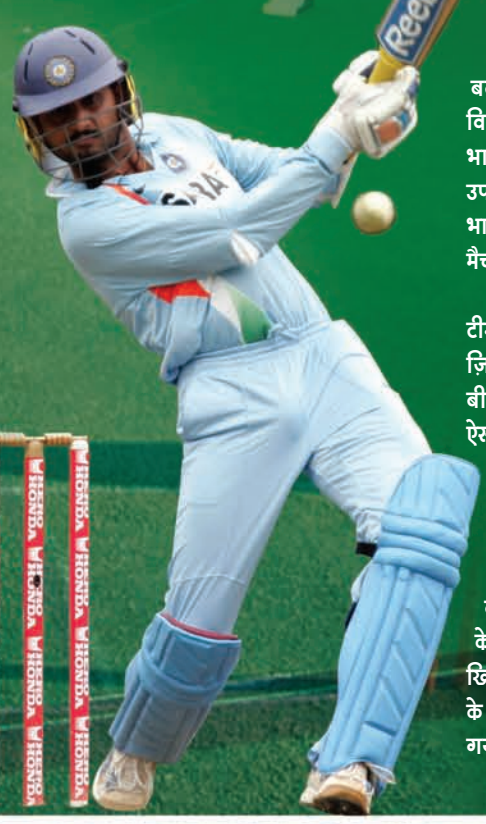

फ्लैट पिच पर तो टीम इंडिया का बैटिंग ऑर्डर ठीक रहता है, लेकिन फास्ट पिच मिलते ही या गेंद थोड़ा स्विंग होते ही भारतीय पारी लड़खड़ाने लगती है. ऐसे में अक्सर वॉल ऑफ द क्रिकेट कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ जैसे बल्लेबाज़ों की ज़रूरत होती है, जो धीरे-धीरे ही सही, लेकिन टीम की डूबती नैय्या को बचाए. लेकिन बीसीसीआई ने द्रविड़ को भी शामिल नहीं किया. जबकि द्रविड़ के विश्वकप रिकॉर्ड्स पर नज़र डालें तो 1999 में हुए विश्व कप में राहुल द्रविड़ सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज़ थे. द्रविड़ ही एक ऐसे बल्लेबाज़ थे, जिन्होंने विश्व कप मैच में लगातार दो शतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है. उन्होंने केन्या के ख़िलाफ़ 110 रन और श्रीलंका के ख़िलाफ़ टोंटन में 145 रनों की धुआंधार पारी खेलकर मैच के रुख़ को कई बार बदला. 2003 के विश्वकप में द्रविड़ भारतीय टीम में बतौर उपकप्तान रहे. इसमें भारत विश्वकप के फाइनल मैच में पहुंचा था.

वैसे स्विंग होने वाली पिच पर टीम इंडिया के बिखरने के पीछे भी ज़िम्मेदार कोई और नहीं , बीसीसीआई है. बोर्ड ने भारत में ऐसी पिच बनाने और भारतीय टीम को उसपर अभ्यास कराने का मौक़ा ही नहीं दिया.

भारतीय टीम में संभावित 30 खिलाड़ियों की सूची में महेंद्र सिंह धोनी के अलावा तीन और खिलाड़ियों को विकेट कीपर के नाम पर शामिल किया गया है. इन खिलाड़ियों में धोनी के अलावा पार्थिव पटेल, दिनेश कार्तिक और रिद्धिमान साहा शामिल हैं. सवाल उठना लाज़मी है कि टीम में एक साथ चार विकेट कीपर को शामिल करने की क्या ज़रूरत थी. किसी भी टीम की सफलता उसकी बल्लेबाज़ी, गेंदबाज़ी और फील्डिंग पर निर्भर होती है. बोर्ड को विकेट कीपिंग के लिए चार विकल्प रखने से अच्छा था कि बल्लेबाज़ी और गेंदबाज़ी को ज़्यादा महत्व देते हुए दो और संभावित खिलाड़ियों को शामिल करना चाहिए था. कम से कम इस आधार पर राहुल द्रविड़ टीम में आ जाते.

टीम में फिटनेस को लेकर अगर कुछ खिलाड़ियों का चयन हुआ है, तो यह भी बिल्कुल निराधार है, क्योंकि फिटनेस के आधार पर तो कई भारतीय क्रिकेटर टांय- टांय फिस्स हो जाते हैं. इसी साल भारतीय कोच गैरी कर्स्टन ने युवराज सिंह, ज़हीर ख़ान और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों की फिटनेस पर भी सवाल उठाए थे. इसके अलावा आशीष नेहरा और रविंद्र जडेजा की फिटनेस पर भी सवाल उठे थे. कर्स्टन ने कहा था कि 42 की उम्र में भी वह कई भारतीयों खिलाड़ियों से ज़्यादा फिट हैं. ऐसे में फिटनेस और रिकॉर्ड के आधार पर अगर चयन नहीं हुआ तो फिर चयन-प्रक्रिया का आधार क्या था. इसमें कोई संदेह नहीं कि बोर्ड हमेशा से राजनीति का अखाड़ा रहा है. इसी राजनीति का असर है कि टीम में खिलाड़ियों के प्रदर्शन से ज़्यादा इस बात पर नज़र रखी जाती है कि कौन खिलाड़ी किस खेमे से हैं. बोर्ड के गठन के शुरुआती साल से ही इसकी चयन प्रक्रिया पर सवाल उठते रहे हैं. दरअसल, बीसीसीआई को पता है कि विश्वकप क्रिकेट का मतलब है बहुत सारा पैसा. बड़े पैसे का मतलब है बड़ी राजनीति. ऐसे में जिस तरह आईपीएल घोटाला सामने आया, उसी तरह बीसीसीआई को और भी बहुत सारे मामलों पर जवाब देना है. ऐसे में टीम इंडिया और विश्वकप से सिर्फ़ उम्मीदें ही लगाई जा सकती हैं.

फोटो– *प्रभात पाण्डेय*

kumarsushant@chauthiduniya.com

देश का पहला इंटरनेट टीवी

हर दिन 50,000 से ज़्यादा दर्शक

- दो टूक–संतोष भारतीय के साथ
- ब्लैक एंड व्हाइट रोज़ाना 1 बजे
- पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया
- स्पेशल रिपोर्ट
- नायाब हैं हम-उर्दू के मशहूर शायरों, गीतकारों के साथ मुलाक़ात
- साई की महिमा

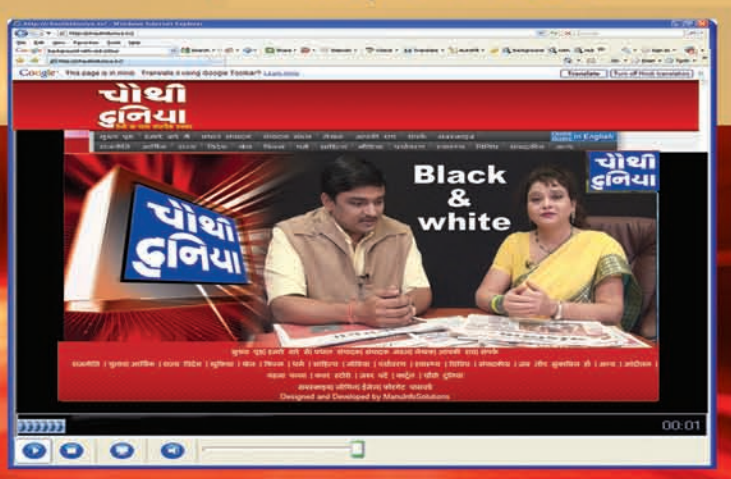

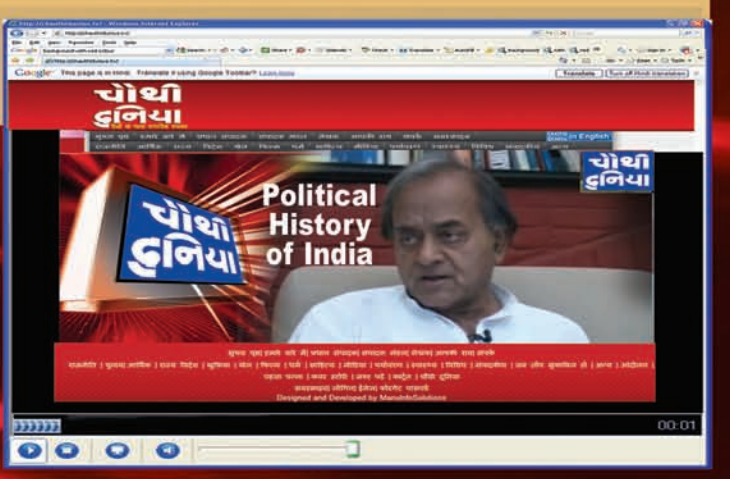

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301 www.chauthiduniya.tv

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

चौथी दुनिया

दिल्ली, 03 जनवरी 2011–09 जनवरी 2011

नलिन इस बात से बेहद नाराज़ थे कि पुलिस अमीषा के ख़िलाफ़ शिक़ायत दर्ज करने में आनाकानी कर रही थी.

कैसा रहा बॉलीवुड का बीता साल

प्रियंका प्रियम तिवारी

बॉलीवुड के लिए साल 2010 मिला-जुला रहा. 2009 की तुलना में 2010 में फिल्में ज़्यादा हिट हुईं. मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी जैसे हिट आइटम नंबर्स के साथ कई निर्माता-निर्देशकों के ड्रीम प्रोजेक्ट वाली फिल्मों की रिलीज ने इस साल को बॉलीवुड के लिए फ्रूटफुल बनाया. इस साल लगभग 180 फिल्में रिलीज हुईं. इनमें हिट फिल्मों की फ़ेरहिस्त में दबंग, गोलमाल 3, राजनीति जैसी कुछ फिल्में हैं, लेकिन और भी कई फिल्में है जो व्यवसायिक तौर पर तो उतनी कामयाब नहीं रहीं, पर दर्शकों की पसंद पर ज़रूर खरी उतरीं. बड़े बजट की फिल्में जैसे वीर, काईट्स और माई नेम इज ख़ान मुनाफ़ा कमाने में सफल रहीं, जबकि कम बजट वाली फिल्में, जैसे आमिर ख़ान की फिल्म पीपली लाइव, अतिथि तुम कब जाओगे, तेरे बिन लादेन, फंस गए रे ओबामा, वेल डन अब्बा, उड़ान, लाहौर और दो दूनी चार दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचने में सफल रहीं. व्यवसायिक फ़िल्मों की श्रेणी में अरबाज़ ख़ान प्रोडक्शन की फिल्म दबंग ने बॉक्स ऑफिस पर आमिर ख़ान की फिल्म थ्री इडियट्स से कहीं ज़्यादा 145 करोड़ रुपए की कमाई की. सलमान ख़ान बिहारी अंदाज़ में चुलबुल पांडे के किरदार में दर्शकों को ख़ूब भाए. सफलतम फिल्मों की श्रेणी में फिल्म गोलमाल-3, दबंग के बाद दूसरे नंबर पर रही. पॉलीटिकल ड्रामा पर बनी फिल्म राजनीति ने बढ़िया कारोबार किया. फिल्म माई नेम इज़ ख़ान में 90 के दशक की सफलतम जोड़ी शाहरुख़ और काजोल ने सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की. जन्म से ही एस्पर्जर सिन्ड्रोम से ग्रस्त युवक की भूमिका में शाहरुख़ केअभिनय को दर्शकों ने काफी सराहा. साजिद ख़ान की कॉमेडी फिल्म हाऊसफुल ने भी बढ़िया कारोबार किया. इमरान ख़ान और सोनम कपूर स्टारर आई हेट लव स्टोरीज शुरुआती सप्ताह में ही युवाओं के बीच छा गई थी. अपराध और कॉमेडी का कॉकटेल इश्किया को सभी वर्ग के दर्शकों ने सराहा. साइंस फिक्शन पर आधारित तेलुगु फिल्म एंधीरन के हिंदी रूपांतरण रोबोट ने व्यवसायिक दृष्टि से अपार सफलता हासिल की. इस साल कुछ नए निर्देशकों की फिल्में भी आईं, जिससे बॉलीवुड को कुछ और हिट फिल्में मिल गईं.

इनमें हबीब फैसल की दो दूनी चार, दानिश असलम की ब्रेक के बाद, अभिषेक चौबे की इश्किया, अनुषा रिजवी की पीपली लाइव, अभिषेक शर्मा की तेरे बिन लादेन, सुभाष कपूर की फंस गए रे ओबामा, पुनीत मल्होत्रा की आई हेट लव स्टोरीज, विजय लालवानी की कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, फारुक कबीर की अल्लाह के बंदे, अभिनव कश्यप की दबंग, संजय पूरन सिंह चौहान की लाहौर, और परमीत सेठी की बदमाश कंपनी है.

priyanka@chauthiduniya.com

खो गया माधुरी का चार्म

काफी इंतज़ार के बाद धक धक गर्ल माधुरी अपने दर्शकों के सामने तो आ गई हैं, लेकिन उनकी बहुप्रतीक्षित वापसी दर्शकों को प्रभावित नहीं कर पाई. हालांकि उनकी मुस्कान ज़रूर अब भी मोहक लगती है, लेकिन उनका प्रजेंस पहले की तरह जादू नहीं जगाता. माधुरी ने अपना वह टच खो दिया है, जो दर्शकों को दीवाना बना देता था. शूटिंग के दौरान सेट पर मौजूद एक दर्शक का कहना था कि माधुरी का साड़ी लुक बोरिंग और शो की को-जज मलाइका अरोरा ख़ान की तुलना में काफी घरेलू था. सोनी टीवी के डांस बेस्ड रियलिटी शो झलक दिखला जा के ज़रिए माधुरी दीक्षित की वापसी हुई है. 43 वर्षीय माधुरी टेलीविज़न डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा में नज़र आ रही हैं. बॉलीवुड में वापसी और फिल्म नच ले के ज़्यादा न चल पाने के बारे में माधुरी कहती हैं, किसी फिल्म की नाकामी का मैं अफसोस नहीं करतीं. जब आप एक फिल्म में काम करते हैं तो यह सोचते हैं कि सभी चीजें ठीक रहेंगी और आपकी फिल्म कामयाब रहेगी, परंतु जब फिल्म अच्छा नहीं करती तो आप कुछ नहीं कर सकते. ऐसे में मुझे इसका अफसोस क्यों करना चाहिए?

माधुरी इस समय अमेरिका के डेनेवर शहर में रहती हैं. पेशे से डॉक्टर श्रीराम नेने से विवाह करने के बाद वह बॉलीवुड से लगभग अलग हो गईं. अब उनके दो बेटे आरिन (7) और रयान (5) हैं. लेकिन अब माधुरी अलग तरह के किरदार निभाना चाहती हैं. उन्होंने कहा, मैं उन्हीं पटकथाओं को पसंद करूंगी, जिनमें मेरी भूमिका मेरे मुताबिक़ होगी. मैं अलग-अलग तरह की भूमिकाएं करना चाहूंगी. आजकल अलग-अलग तरह की फिल्में बन रही हैं. अब बॉलीवुड भी मेरे लिए पहले जैसा नहीं रहा. अब मुझ पर कई और ज़िम्मेदारियां हैं. मुझे भारत और अपने दोस्तों की कमी महसूस होती है. अब मेरे दो घर हैं. जब मैं भारत में होती हूं तो अपने पति और बच्चों की कमी महसूस करने लगती हूं. माधुरी के नृत्य की मिसाल अब तक दी जाती है. हमको आजकल है, एक-दो-तीन, चोली के पीछे, धक-धक, चने के खेत में, दीदी तेरा देवर दीवाना, मेरा पिया घर आया जैसे गाने आज भी लोगों की ज़ुबान पर चढ़े हुए हैं. उनकी उम्र आज भी उनके चेहरे से पता नहीं लगती. ख़ुद को शेप में रखने के लिए वह घर पर कथक करती हैं. इसके अलावा वह योग भी करती हैं. ख़ैर, रुपहले पर्दे पर लंबे समय तक जलवा बिखेरने वाली माधुरी दीक्षित की फिल्म आ जा नच ले भले ही नाकाम रही हो, लेकिन उनके कद में कोई कमी नहीं आई. अब वह छोटे पर्दे पर जलवा दिखा रही हैं. हम तो यही कहेंगे कि माधुरी जी, अब पल्लू समेट कर दोबारा जलवा दिखाने का समय आ गया है.

बैले डांस करेंगी सोनाक्षी

बॉलीवुड के अघोषित नियमों के मुताबिक़, अगर किसी नई अभिनेत्री की फोटो के साथ छेड़छाड़ करके उसे इंटरनेट पर सार्वजनिक कर दिया जाए तो इसका मतलब है कि उसे लंबा सफर तय करने वाले के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन सोनाक्षी सिन्हा के लिए यह छेड़छाड़ काफी असहज स्थिति पैदा कर चुकी है. पुरुषों की एक पत्रिका के कवर पर सोनाक्षी का बिकनी में फोटो प्रकाशित हुआ है. सोनाक्षी का कहना है कि उन्होंने कभी भी बिकनी में फोटो शूट नहीं कराया है, जबकि पत्रिका के प्रकाशक का कहना है कि उनकी नीति ही नहीं है कि फोटो के साथ छेड़छाड़ करके उसे प्रकाशित किया जाए.

इस घटना से सोनाक्षी का परिवार खासा आहत है. सोनाक्षी भी कई बार कह चुकी हैं कि वह बिकनी में कभी भी पोज नहीं देंगी. यही वजह है कि रेस-2 में कुछ दृश्यों को करने से उन्होंने साफ इंकार कर दिया, लेकिन अब उनका बिकनी में फोटो चर्चा में है. सूत्रों के मुताबिक़, सोनाक्षी ने बहुत ही विनम्रता से रेस-2 में काम करने से मना कर दिया. वह इस फिल्म में हॉट सीन्स और एक्सपोजिंग कपड़े पहनने में सहज नहीं थीं. सोनाक्षी ने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था और रैंप पर डिज़ायनर्स के लिए वॉक करती थीं. उस वक़्त उन्हें एक्टिंग का ख्याल तक नहीं आया था. उन्हें डांस करना पसंद है, लेकिन किसी एक डांस शैली पर ध्यान केंद्रित करना उन्हें काफी मुश्किल लगता है, इसलिए उन्होंने कई डांस फॉर्म सीखे, जैसे हिप होप, बॉलीवुड और कत्थक. ख़बर है कि अपने पति शिरीष कुंदर द्वारा निर्देशित फिल्म जोकर में फराह ख़ान सोनाक्षी से बैले डांस कराएंगी. इसमें सोनाक्षी के साथ अक्षय कुमार होंगे और यह फिल्म थ्री डायमेंशनल होगी.

अमीषा की एडवेंचरस लाइफ

बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल इन दिनों फिल्मों की वजह से नहीं, बल्कि अपनी निजी ज़िंदगी की वजह से ज़्यादा सुर्ख़ियां बटोर रही हैं. हाल में अमीषा पर उनके एक रिश्तेदार ने उसकी ग़ैर मौजूदगी में घर में घुसकर चोरी करने का आरोप लगाया है. अमीषा के अंकल नलिन रजनी पटेल ने पुणे के जिमखाना पुलिस स्टेशन में अपनी भांजी अमीषा पटेल के ख़िलाफ़ शिक़ायत दर्ज कराई. उन्होंने आरोप लगाया कि अमीषा ने मनाली अपार्टमेंट स्थित उनके बंद फ्लैट को डुप्लीकेट चाबी से खोला और घर में रखे कई घरेलू सामान चुरा लिए. वह उस समय नासिक में थे. उन्हें इसका पता तब चला, जब एक नौकर ने उनके भाई को अमीषा एवं कुछ अन्य लोगों द्वारा घर में घुसकर ऐसा किए जाने के बारे में बताया.

नलिन इस बात से बेहद नाराज़ थे कि पुलिस अमीषा के ख़िलाफ़ शिक़ायत दर्ज करने में आनाकानी कर रही थी. पुलिस ने उन्हें सलाह दी कि वह बातचीत के ज़रिए यह मामला सुलझा लें. जब इस बारे में अमीषा से पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ़ इतना कहा कि उन्हें उनके वकील ने कुछ भी बोलने से मना किया है. अमीषा अपने निजी जीवन में काफी एडवेंचरस हो गई हैं. वह लिएंडर पेस के साथ रोमांस करने वाली हैं. लिएंडर की डेब्यू बॉलीवुड मूवी राजधानी एक्सप्रेस में अमीषा उनकी नायिका का किरदार निभाने जा रही हैं. यह फिल्म जल्द ही फ्लोर पर जाने वाली है. निर्देशक अशोक कोहली द्वारा निर्देशित इस फिल्म के लिए लिएंडर पेस को साइन करने के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि इसमें उनकी नायिका कौन बनेगी. नायिका के किरदार के लिए कई अभिनेत्रियों के नामों पर विचार किया गया, लेकिन आख़िर में अमीषा के नाम पर सहमति बन गई. वह फिल्मों में नए सिरे से अपना करियर संवारना चाहती हैं. पिछले दिनों राजकुमार संतोषी की एक्शन-पैक्ड मल्टी स्टारर फिल्म पावर साइन करने वाली अमीषा ने अशोक कोइली की इस फिल्म के लिए सहमति दे दी है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

प्रीव्यू

नो वन किल्ड जेसिका

यह फिल्म मॉडल जेसिका लाल की हत्या पर आधारित है. वर्ष 1999 में हरियाणा के एक राजनीतिज्ञ के बेटे मनु शर्मा ने एक नाइट क्लब में गोली मारकर जेसिका लाल की हत्या कर दी थी. फिल्म का निर्माण यूटीवी स्पॉट ब्वॉय के बैनर पर हुआ है. यह सात जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. फिल्म में अभिनेत्री विद्या बालन ने जेसिका की बड़ी बहन सबरीना की भूमिका निभाई है. रानी एक टीवी समाचार संवाददाता मीरा गेटी के किरदार में हैं. बॉलीवुड में कई तरह की भूमिकाएं निभाने के बाद अब रानी मुखर्जी दर्शकों के सामने नए अंदाज़ में नज़र आएंगी, जिसमें वह सिल्वर स्क्रीन पर सिगरेट पीने और गालियां देने वाली एक पत्रकार का किरदार निभा रही हैं. हालांकि रानी मुखर्जी का कहना है कि हाई प्रोफाइल जेसिका लाल हत्याकांड पर बनी उनकी फिल्म नो वन किल्ड जेसिका में उनका टीवी रिपोर्टर का किरदार काल्पनिक है. रानी ने कहा कि इस फिल्म में सिवाय उनके किरदार के बाक़ी सब कुछ असली है. हालांकि उनके किरदार में सच्चाई का पुट ज़रूर है. रानी के अनुसार, जेसिका लाल हत्याकांड मामले में न्याय कराने के लिए मीडिया ने जो भूमिका निभाई, उससे यह साबित होता है कि अगर मीडिया की ताक़त को सही दिशा में लगाया जाए तो बहुत कुछ बदल सकता है. इस फिल्म में गवाहों के मुकरने के बाद मीडिया का जो रोल रहा, वह मेरे माध्यम से दिखाया गया है. निर्देशक राजकुमार गुप्ता ने जिस तरह इसमें मीडिया की सही और तार्किक भूमिका लिखी, वह काबिले तारीफ़ है.

आम तौर पर ज़्यादातर कलाकारों की ख्वाहिश होती है कि उनकी फिल्मों को यू/ए प्रमाणपत्र मिले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन्हें देख सकें, लेकिन रानी मुखर्जी चाहती थीं कि उनकी नई फिल्म नो वन किल्ड जेसिका को ए प्रमाणपत्र मिले. इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि मैं अपनी भतीजी को भी यह फिल्म नहीं दिखा सकती, क्योंकि मुझे लगता है कि यह उसके लिए नहीं है. इसलिए हम वास्तव में नहीं चाहते कि कोई भी बच्चा इस फिल्म को देखे. मुझे लगता है कि यह फिल्म बच्चों के देखने के लायक़ नहीं है और इसे ए प्रमाणपत्र मिलना ही सही है. फिल्म में अभद्र भाषा के प्रयोग को लेकर निर्देशक राजकुमार गुप्ता कहते हैं कि गालियों का प्रयोग किरदार के रवैये को दर्शाने के लिए किया गया है, न कि अपमानजनक रूप में. रानी के किरदार को प्रभावी बनाने के लिए यह प्रयोग अनिवार्य था. वैसे भी आजकल गालियों का प्रयोग संवाद का एक हिस्सा है, इसलिए इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए. फिल्म 7 जनवरी को रिलीज होगी.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 03 जनवरी 2011-09 जनवरी 2011

www.chauthiduniya.com

बहाली पर बवाल

बिहार की एक ख़ास पहचान यहां के ऊर्जावान युवा भी हैं. लेकिन दुःख की बात यह है कि राज्य सरकार इस ऊर्जा का इस्तेमाल कर पाने में असफल रही है. तुर्रा यह कि नौकरी मांगते युवाओं पर लाठीचार्ज करना बिहार पुलिस का नया शगल बन गया है. शिक्षक, दरोगा, सिपाही और नर्स. कोई भी बहाली, बिना लाठीचार्ज के पूरी नहीं हो पा रही है.

सरोज सिंह

रोज़ी-रोटी का इंतजाम युवाओं का सबसे बड़ा सपना होता है. यही इंतजाम अगर उन्हें अपने प्रदेश या फिर अपने शहर और गांव में मिल जाए तो क्या कहने. रेलवे और बैंक में घटती नौकरियों के दौर में नीतीश कुमार की सरकार ने प्रदेश के युवाओं को इसी तरह का सपना दिखाया. इस सपने को साकार करने की बड़ी मुहिम भी शुरू की, लेकिन इस मुहिम में जब पिछले पांच सालों में सरकार के हाकिम व बाबू ही छेद करने लगे तो बेरोज़गारों की फ़ौज को कई बार पटना की सड़कों पर उतरना पड़ा. शायद ही कोई ऐसा प्रदर्शन गुज़रा हो, जिस पर पुलिस की लाठियां न बरसी हों. ठेके पर बहाल होने वाले शिक्षकों को तो कई दफ़ा पुलिसिया प्रकोप झेलना पड़ा. शिक्षा मित्रों से जो सिलसिला शुरु हुआ, वह पुलिस में बहाल होने की आशा रखने वाले युवाओं तक जारी है. इस बीच आशा कार्यकर्ताओं, होमगार्ड जवानों, जननी से जुड़ीं महिलाओं, दरोगा बहाली से जुड़े छात्रों की पीठ भी पटना की सड़कों पर पुलिस ने सीधी कर दी. मतलब जो भी विरोध जताने सड़कों पर उतरा, उसकी ख़ैर नहीं. आख़िर क्या वजह है कि छात्रों की जायज़ बात सुनी नहीं जाती और विरोध जताने के लिए उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ता है. इसकी एक मात्र वजह बहाली प्रकिया का स्पष्ट न होना और इसी कारण प्रक्रिया का शक़ के घेरे में आ जाना है. शिक्षकों की बहाली हो या फिर पुलिस की, दोनों ही मामलों में शक़ की ऐसी बुनियाद पड़ गई कि सरकार की लाख सफ़ाई के बावजूद छात्र समझने को तैयार नहीं हैं. इस बात को लेकर सरकार की बहुत आलोचना भी हुई कि शिक्षकों की बहाली तो डिग्री देखकर हो रही है, पर पुलिस की बहाली के लिए लिखित परीक्षा ली जा रही है. ताज़ा विवाद पुलिस बहाली को लेकर है. सड़क पर उतरे छात्रों का आरोप है कि सफल होने के बावजूद उन्हें योगदान करने के लिए नहीं कहा गया है. जबकि उनसे कम अंक पाने वालों की लिस्ट जारी कर दी गई है. बताया जाता है कि इस तरह की शिकायत करने वालों की संख्या तीन हज़ार से ज़्यादा है. ऐसे छात्रों की मांग है कि जब वे सफल हो गए हैं तो उन्हें सेवा में क्यों नहीं लिया जा रहा है. इस पर पुलिस मुख्यालय का कहना है कि विज्ञापन के तहत सात हज़ार सिपाहियों की ही बहाली होनी है. भर्ती बोर्ड ने लिखित व शारीरिक परीक्षा के आधार पर लगभग साढ़े दस हज़ार लोगों को सफल घोषित कर दिया. इन सफल परीक्षार्थियों की सूची से मेरिट लिस्ट के आधार पर सात हज़ार लोगों की ही बहाली होनी है. अब सवाल है कि साढ़े तीन हज़ार छात्रों का क्या होगा. इसके अलावा छात्रों का कहना है कि मेरिट लिस्ट बनाने में भी अनियमितता बरती गई है. कम अंक वाले छात्रों को योगदान करने के लिए कहा गया है. यही वजह रही कि हाईकोर्ट ने नए लोगों के योगदान पर रोक लगा दी है. अपनी इसी पीड़ा को लेकर छात्र पहले जनता दरबार में गए और जब वहां उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो वे सड़कों पर उतर गए, जहां पुलिस ने उन पर जमकर लाठियां बरसाईं. पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारियों का कहना है कि आंदोलन पर आमादा छात्रों को यह आश्वासन भी नहीं दिया जा सकता है कि उन्हें आगे की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी. बहरहाल, मुख्यमंत्री ने डीजीपी को पूरे मामले को देखने के लिए कहा है. अब बात शिक्षकों की बहाली की कर लेते हैं. नीतीश कुमार ने अपने पिछले कार्यकाल में सवा दो लाख शिक्षकों को बहाल किया. अभी तीन लाख शिक्षकों को और बहाल करना है. अनिवार्य शिक्षा क़ानून के तहत केवल प्रशिक्षित शिक्षक ही बहाल हो सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 34540 प्रशिक्षित शिक्षकों को बहाल करना है. इस मामले में बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार भी लग गई है. सरकार की लापरवाही का आलम यह रहा कि जन्म से पहले ही कुछ लोगों को बीएडधारी बना दिया गया. कोर्ट ने इस पर गहरी नाराज़गी जताते हुए सरकार से पूछा कि क्या इसी तरह से मेधा सूची बनाई जाती है. सरकार को संशोधित सूची सौंपने को कहा गया है. मतलब यह है कि सरकार के हाकिम व बाबू अपनी लापरवाही या फिर अन्य कारणों से शक़ की बुनियाद डाल देते हैं और छात्रों को सड़कों पर उतरने को मजबूर कर देते हैं. अब आप ही बताइए कि जन्म लेने से पहले ही कोई बीएड की डिग्री कैसे ले सकता है. यह एक छोटा सा उदाहरण है, जो बहाली जैसे छात्रों के जीवन से जुड़े संवेदनशील मामले में सरकार की लापरवाही को दिखाता है. अब एक बार फिर सरकार ने घोषणा कर दी कि तीन लाख नए शिक्षक बहाल होंगे. केंद्र सरकार कहती है कि प्रशिक्षितों को ही बहाल करना होगा.

शिक्षकों की बहाली हो या फिर पुलिस की, दोनों ही मामलों में शक़ की ऐसी बुनियाद पड़ी कि सरकार की लाख सफ़ाई के बावजूद छात्र समझने को तैयार नहीं हैं. इस बात को लेकर भी सरकार की तीख़ी आलोचना हो रही है कि शिक्षकों की बहाली तो डिग्री देखकर हो रही है, पर पुलिस की बहाली के लिए लिखित परीक्षा क्यों ली जा रही है. ताज़ा विवाद पुलिस बहाली को लेकर है. सड़क पर उतरे छात्रों का आरोप है कि सफल होने के बावजूद उन्हें योगदान करने के लिए नहीं कहा गया है. जबकि उनसे कम अंक पाने वालों की लिस्ट जारी कर दी गई है.

बिहार में एनसीटीई से मान्यता प्राप्त मात्र 57 बीएड संस्थान हैं. इसमें साल भर में केवल 5500 और 36 प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में एक साल में करीब तीन हज़ार छात्रों को ही प्रशिक्षित किया जा सकता है. अब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तीन लाख शिक्षकों की बहाली का क्या होगा. सरकार की एक कोशिश है कि केंद्र सरकार से आग्रह किया जाए कि केवल टीईटी में सफल छात्रों को बहाल करने की अनुमति दी जाए. बहाली के बाद धीरे-धीरे उन्हें प्रशिक्षित कर दिया जाएगा. केंद्र सरकार ने इस पर बिहार सरकार से लिखित प्रस्ताव मांगा है. मतलब शिक्षकों की बहाली की घोषणा राज्य सरकार ने कर दी, लेकिन गेंद केंद्र सरकार के पाले में है. अब केंद्र सरकार ने किसी नियम क़ानून का हवाला दिया तो राज्य सरकार कहेगी कि हम क्या कर सकते हैं, केंद्र सरकार ही अड़चन लगा रही है. अब छात्र उस समय सड़कों पर उतरेंगे तो फिर डंडों से स्वागत होगा. बड़ी मुश्किल है, सरकार बंपर बहाली की घोषणा कर वाहवाही तो लूटना चाहती है, पर जब पेंच फंसता है तो छात्रों पर डंडों की बौछार शुरू कर देती है. कोर्ट ने सिपाही बहाली के मामले को जिस तरह स्टे किया है, उससे साफ़ है कि कहीं न कहीं कुछ बात ज़रूर है. सफल छात्र अगर योगदान नहीं कर पाए तो उनके भविष्य का क्या होगा. क्या अगले साल एक बार फिर उन्हें एक कठिन दौर से नहीं गुज़रना होगा. कुछ छात्रों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया है कि इस बात की क्या गारंटी है कि अगली बार भी अगर वे सफल हो गए तो उन्हें सेवा में ले ही लिया जाएगा. इन छात्रों का कहना है कि सरकार को ईमानदारी से पूरी बहाली प्रकिया की जांच करानी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके. उन्होंने कहा कि सरकार डंडों से छात्रों को नहीं डरा सकती है. उनको विश्वास है कि कोर्ट से उन्हें न्याय ज़रूर मिलेगा.

बिहार एक बढ़ता हुआ राज्य है और इसमें युवा शक्ति का सही उपयोग न होना बाधा डाल सकता है. नीतीश कुमार ख़ुद कई बार कह चुके हैं कि 2015 तक बिहार को विकसित राज्य बनाना है. यह वादा धरातल पर तभी उतरेगा, जब प्रदेश के युवाओं की पूरी ताक़त विकास के कामों में लगेगी. अगर यह ताक़त सही जगह लग जाए तो 2015 तक बिहार का कायाकल्प कर सकती है. लेकिन अगर यह ताक़त सड़कों पर पुलिस से मार खाने में बर्बाद हुई तो फिर पांच साल बाद इस राज्य की दशा व दिशा कुछ और ही होगी. नीतीश जी, ज़रूरत बस हाकिमों व बाबुओं के दिलों में थोड़ी सी ज़िम्मेदारी व ईमानदारी से काम करने का जज्बा जगाने की है. सच मानिए, अगर सही हाथों को सही काम मिल गया तो बिहार को विकसित प्रदेश बनने से कोई नहीं रोक सकता.

feedback@chauthiduniya.com

सारण ज़िले की जनसंख्या क़रीब 38 लाख है. इस हिसाब से ज़िले में 110 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए.

सड़क बनने के बाद से ही जगह-जगह उखड़ने लगी. इस पर स्थानीय ग्रामीणों ने पटना के वरीय पदाधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराई थी.

एक नज़र इधर भी

पत्नी की भी नही सुनेंगे भीम सिंह

ग्रामीण कार्य मंत्री भीम सिंह ने कहा है कि समय पर काम उनकी पहली प्राथमिकता है. कोई लापरवाही नही चलेगी. कहते हैं कि मैंने अपने विभाग में साफ कह दिया है कि अगर मेरी पत्नी भी किसी की पैरवी करे, नहीं मानी जाए. उनके मुताबिक़ जनता के जनादेश के बाद उन्हें कम समय में ज्यादा काम करके दिखाना है. इसलिए पैरवी नहीं चलेगी, चलेगा तो सिर्फ़ काम.

छड़ और अलकतरा गिरवाता

पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ऐसी बात भी कर जाते हैं, जिसे शायद बोलना ही न चाहते हों. विभाग पर बहस चल रही थी कि एक मित्र ने गिरिराज सिंह से कहा कि आप अपने घर पर बकरी पालते थे, शायद तभी आपको पशुपालन विभाग का मंत्री बनाया है. इतना सुनते ही गिरिराज जी कहने लगे, अरे मित्र यह बात आपने पहले क्यों नहीं बताई. अगर यही मापदंड था तो मैं तो अपने घर पर छड़ और अलकतरा ही गिरवाता.

मेहनताना मिलने की आस

विधानसभा चुनाव में जदयू के लिए दिन रात एक कर देने वाले अशोक सिंह के दिल में अब मेहनताना मिलने की आस जग गई है. ख़बरों पर भरोसा करें तो, लगता है कि उन्हें पार्टी ज़िला संगठन में या फिर किसी कमेटी में जल्द ही बड़ा ओ-हदा मिल सकता है. उनके नाम पर मोटे तौर पर सहमति भी बन गई है. ग़ौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में जमुई ज़िले में भूमिहार वोटों को गोलबंद करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी. इस मसले पर अशोक सिंह कहते हैं कि मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं, पार्टी जो ज़िम्मेदारी देगी, उसे पूरी क्षमता से निभाने की कोशिश करूंगा.

पंडित जी के चक्कर में टली बैठक

लोजपा विधानसभा चुनाव में अपनी हार की समीक्षा बीस दिसंबर को करने वाली थी. सारी तैयारी थी. तय हुआ कि एक-एक सीट को लेकर प्रत्याशियों व संगठन से जुड़े लोगों की राय ली जाएगी. लेकिन बताया जाता है कि लोजपा के शीर्ष नेताओं को किसी पंडित जी ने राय दी कि यह साल आप लोगों के लिए अच्छा नहीं रहा. इसलिए नए साल में समीक्षा बैठक करें. बस क्या था, बैठक स्थगित कर दी गई.

अफसरशाही ख़त्म करूंगी

महिला पार्षद महजबी नाज विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में व्याप्त अनियमितता के लिए सरकारी सिस्टम को दोषी मानतीं हैं. ज़िला परिषद की बैठकों में सर्वाधिक प्रश्नों की बौछार करने वाली महजबी नाज को दुख है कि ज़िला परिषद सदस्यों को आज तक ज़िला परिषद की परिसंपत्तियों का विवरण उपलब्ध नहीं कराया जा सका है. अपने घर मोतीपुर स्थित एक आंगनबाड़ी केंद्र की हक़ीक़त बयां करते हुए बताती है कि संचिकाओं एवं कागजों में केन्द्र सं.-66 का संचालन स्थानीय मकतब में होता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि पिछले कई वर्षों से स्थानीय लोगों ने कभी इस आंगनबाड़ी केंद्र को चलते नहीं देखा. कहती हैं कि आगामी चुनाव में जनता ने मौका दिया तो अफसरशाही ख़त्म करने के साथ-साथ सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई की बेहतर व्यवस्था के लिए संघर्ष करूंगी.

-संजीव कुमार सिंह

टॉल प्लाजा बना परेशानी का सबब

गया ज़िले के आमस प्रखंड अंतर्गत जीटी रोड पर बना टॉल प्लाजा स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बना है. कारण है कि आमस प्रखंड का क्षेत्र शेरघाटी अनुमंडल कार्यालय तक आता है. इसलिए चार पहिया रखने वाले आमस प्रखंड के विभिन्न गांवों के सैकड़ों लोगों को प्रतिदिन अपने गांव-बाज़ार से कई बार आना-जाना पड़ता है. टॉल प्लाजा के सुरक्षा कर्मी यह जानते हुए भी कि ये स्थानीय लोग हैं, टॉल प्लाजा कर्मी टॉल टैक्स लेने के लिए हर बार राशि की मांग करते है. इस बात को लेकर लोगों में आक्रोश है.

- मिथलेश कुमार सिंह

एन एच 156 का काम अधूरा

गया ज़िले के डुमरिया से पटना के रानी तलाब तक जाने वाले फोरलेन राष्ट्रीय उच्च पथ 156 का कार्य बंद होने से करमाईन से गुरुआ आने जाने वाले वाहनो को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है. नक्सली गतिविधियों के कारण खोखर कंपनी इस सड़क का निर्माण कार्य अधूरा छोड़ कर चली गई थी. लेकिन गेमैन इंडिया ने इसके निर्माण का जिम्मा लिया है. काम सुस्त गति से चलने के कारण वाहनों का आना जाना कम हो रहा है .

-डॉ. प्रमोद कुमार वर्मा

बिहार पेपर मिल के दिन बदलेंगे

बिहार पेपर मिल बैजनाथपुर के दिन शायद बदलने वाले हैं. उद्योग मंत्री डॉ. रेणु कुमारी कुशवाहा ने अधिकारियों के साथ मिल का निरीक्षण किया. श्रीमति कुशवाहा के मुताबिक़ राज्य में बंद कारखानों को पुनर्जीवित करने के काम सरकारी स्तर पर शुरू कर दिए गए हैं. अगर यह मिल चालू हो जाती है तो पलायन रुकने के साथ-साथ रोज़ी-रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे.

- अमितलाल

खाने में कीड़े देख भड़के छात्र

ज़िले के रोसड़ा प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय के छात्र एनजीओ द्वारा उपलब्ध कराये गए मध्यान भोजन में कीड़े मिले, जिसे देख छात्र और अभिभावकों ने जमकर बवाल मचाया. मामले की जानकारी पाकर मुखिया शीला कुमारी विद्यालय पहुंचीं. इस संबंध में विद्यालय प्रधान रामनारायण महतो ने अभिभावकों को बताया कि गत अक्टूबर-नवंबर माह में मध्यान भोजन दिया ही नहीं गया. इस माह की 8 दिसंबर से मध्यान भोजन दिया जाने लगा है, लेकिन इसके तीन दिनों के बाद ही मध्यान भोजन में पिल्लू दिख रहे हैं. इसकी जानकारी संकुल समन्यवक प्रदीप कुमार सतरा द्वारा विभागीय अधिकारियों को दे दी गई. ज़िले के एक मात्र अनुसूचित अंबेडकर आवासीय विद्यालय के छात्रों की गुहार पर रोसड़ा के अनुमंडल पदाधिकारी सुनील कुमार ने विद्यालय में बैठक आयोजित कर छात्रों के समस्याओं की जानकारी ली. छात्रों ने एसडीओ को बताया कि यहां रह रहे आवासीय छात्रों को निम्न स्तर का भोजन दिया जाता है साथ ही विद्यालय के प्रधानाध्यापक अधिकांश ग़ायब ही रहते हैं. इसकी शिकायत करने पर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है. एसडीओ ने मौके पर उपस्थित मेस प्रभारी को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिया, साथ ही छात्रों की शिकायत एवं व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन ज़िलाधिकारी को भेज दिए हैं.

-चौथी दुनिया ब्यूरो

सेना सेवा कोर स्थानांतरण

गया के लिए ख़तरे की घंटी

सुनील सौरभ

गया में 35 साल पहले स्थापित सेना सेवा कोर केंद्र (उत्तर) को बंगलूर स्थानांतरित किए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है. इस पर राजनीति भी गर्म हो गई है. सेना सेवा कोर केंद्र (उत्तर) बचाव संघर्ष समिति तथा शहर के कथित बुद्धिजीवियों की ओर से नवगठित आर्मी सेंटर (नॉर्थ) बचाओ अभियान समिति की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. इस मामले पर गया से लेकर दिल्ली तक धरना प्रदर्शन किया जा चुका है. [illegible] सबसे बड़ी बात है कि सेना सेवा कोर केंद्र को गया से हटाने का यह आदेश चौथी बार है.

अब सेना सेवा कोर की विभिन्न यूनिटों को बंगलूर भेजा जा रहा है. सेना सेवा कोर केंद्र (उत्तर) की स्थापना पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम के प्रयास से 1976 में हुई थी. उस समय गया मध्य बिहार की राजनीति का केंद्र था. [illegible] लेकिन पिछले एक दशक से इस केंद्र को गया से स्थानांतरित करने का प्रयास किया जा रहा है.

इस बार का आदेश महामहिम राष्ट्रपति के निर्देश पर रक्षा मुख्यालय द्वारा दिया गया है. इससे पूर्व 2001, 2005 तथा 2008 में भी सेना सेवा कोर केंद्र (उत्तर) को गया से बंगलूर स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया था. [illegible]

[illegible] में शामिल होने वाले बाद में स्थानांतरण का विरोध करने लगे हैं. फिलहाल फरवरी से सेना सेवा कोर केंद्र के स्थानांतरण किए जाने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहां सैन्य प्रशिक्षण अकादमी का निर्माण कार्य शुरू हो गया है.

feedback@chauthiduniya.com

सारण

एक अस्पताल के भरोसे पूरा ज़िला

ज़िले में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाएं

सदर अस्पताल	-	01
रेफरल अस्पताल	-	03
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	-	15
नवसृजित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	-	05
अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	-	43
नवसृजित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	-	90
उपस्वास्थ्य केंद्र	-	413
नवसृजित उपस्वास्थ्य केंद्र	-	254
चिकित्सक	-	80
आयुष चिकित्सक-	17	
संगणक	-	15
लिपिक	-	08
नेत्र सहायक	-	06
प्रयोगशाला टेक्नीशियन	-	09
एक्स-रे टेक्नीशियन	-	02
फार्मासिस्ट	-	09
महिला स्वास्थ्य परिचारिका	-	21
परियोजना श्रेणी (ए)	-	10
स्वच्छता निरीक्षक	-	05
बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता	-	58
पुरुष परिवार कार्यकर्ता	-	16
महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	-	02
परिधापक	-	05
चतुर्थ वर्गीय कर्मी	-	141
ऐलोपैथिक चिकित्सक (संविदा)	-	45
ज़िला कार्यक्रम प्रबंधक (संविदा)	-	01
ज़िला नोडल व अनुश्रवण पदाधिकारी	-	01
प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक	-	14
प्रखंड लेखापाल	-	15
ए.एन.एम. (श्रेणी ए)	-	26
ए.एन.एम.	-	71
ए.एन.एम. (आर)	-	137
ममता	-	166
आशा	-	2763
चालक	-	15

बिजेंद्र कुमार

आम आदमी की बुनियादी सुविधाओं में स्वास्थ्य और चिकित्सा बेहद महत्वपूर्ण होती है. इसकी ज़रूरत कब पड़ जाए, कहना मुश्किल है. धनी लोग तो ज़्यादातर निजी चिकित्सालयों में जाना मुनासिब समझते हैं, मगर ग़रीबों के लिए तो सरकारी अस्पताल ही एकमात्र सहारा होता है. ऐसे में उनकी उम्मीदें सरकार और चिकित्सा व्यवस्था पर ही टिकी रहती है. इस पर भी यदि सरकारी चिकित्सा व्यवस्था 50 साल पुराने मानकों पर चलते हों, तो आमलोगों का कितना भला हो सकता है, यह सोचने वाली बात है.

नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 के मानक के अनुसार सरकार ने जनसंख्या के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उपकेंद्र, सामुदायिक व रेफरल अस्पतालों की संख्या निर्धारित की. इसमें प्रत्येक 30 हज़ार की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 10 हज़ार की आबादी पर एक स्वास्थ्य उपकेंद्र और 80 हज़ार की आबादी पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्धारण किया गया है. बहरहाल, सारण ज़िले की जनसंख्या क़रीब 38 लाख है. इस हिसाब से ज़िले में 110 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए. जबकि ज़िले में इनकी संख्या मात्र 15 है. इन केंद्रों की सहायक एजेंसियों की चिकित्सा का लाभ पंचायत स्तर पर भी लोगों को मिले, इसके लिए उपकेंद्र बनाये गए, जो प्रत्येक 10 हज़ार की संख्या के हिसाब से 3800 होने चाहिए. लेकिन ये महज 413 ही हैं.

ज़िले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की एक भी यूनिट न होने के कारण रोगियों को अपने इलाज के लिए सदर अस्पताल पर ही निर्भर रहना पड़ता है, जिसके चलते ज़िला मुख्यालय स्थित सदर अस्पातल में अव्यवस्था का आलम बना रहता है. नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 के मानक के अनुसार प्रत्येक 80 हज़ार की जनसंख्या पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का होना लाजिमी है. इस हिसाब से ज़िले में 80 यूनिटें होनी चाहिए. लेकिन एक भी नहीं है. इसका खामियाज़ा सदर अस्पातल व इसके कर्मियों को उठाना पड़ता है. साथ ही आमजन को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ. संजीव रंजन के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ही वास्तव में रेफरल अस्पताल होता है, जहां मरीजों की बेहतर प्राथमिक चिकित्सा कर उसे सीधे मेडिकल कॉलेज हॉस्पीटल रेफर कर दिया जाता है. इसके अलावा पल्स पोलियो उन्मूलन व एड्स सरीखी बीमारियों की रोकथाम के लिये चलाए जा रहे कार्यक्रमों से सदर अस्पताल के कर्मियों पर काम का बोझ बढ़ा है. फ़िलहाल, ज़िले में सरकारी स्तर पर उपलब्ध कराई गईं सुविधाएं, आबादी के लिहाज़ से ऊंट के मुंह में जीरे के समान है.

feedback@chauthiduniya.com

काम के नाम पर खानापूर्ति

सरकार जनता का जीवन स्तर सुधारने के लिए उन्हें सड़क, पेयजल, बिजली, नाला, पुल जैसी मूलभूत सुविधा देने के लिए चाहे लाख कल्याणकारी योजनाएं बना ले, लेकिन सही मायने में ऐसी योजनाएं उसी के कारिंदों की कारस्तानी के कारण पूरी तरह से धरातल पर उतरती नज़र नहीं आ रही है. इस स्थिति का अंदाज़ा पूर्णिया शहर में ज़िला शहरी विकास अभिकरण के द्वारा बनाए जा रहे नाले, सड़कों को देखकर लगाया जा सकता है. मालूम हो कि विगत कुछ महीने से पूर्णिया शहर को साफ़-सुथरा रखने के उद्देश्य से विभिन्न मोहल्लों में पीसीसी ढलाई सड़क व उसके अंदर अंडरग्राउंड नाले का निर्माण कराया जा रहा है. लेकिन इस प्रकार के गुणवत्ताविहीन कार्यो को लेकर आए दिन मोहल्लावावासियों एवं संवेदकों के चेलों के बीच झड़प देखने को मिल रही है. चेले-चपाटों का कहना है कि बाबू साहब को मलाई खिलाकर हमलोग काम करवा रहे हैं इससे बेहतर गुणवत्ता वाले काम की आशा आप कैसे कर सकते हैं. इस प्रकार की भाषा से आमजन भौचक्का रह जाता है. ऐसे में इस प्रकार के कार्यो को लेकर सवाल खड़ा होना लाजिमी है जो आमजनों को अंधेरे में रखकर कराया जा रहा है. सर्वप्रथम किसी कार्य का प्राकलन राशि, कार्य प्रारंभ की तिथि, कार्य समाप्ति की तिथि, कार्य एजेंसी व संवेदक का नाम उल्लेखित बोर्ड कार्यस्थल पर लगा होना चाहिए, जो कहीं भी नही लगया गया है. गुलाबबाग सरदार टोला के फंटूस, छोटू, विष्णु चौधरी जैसे कई युवकों ने जानकारी दी की उनके मोहल्ले में नाला सह पीसीसी ढलाई सड़क बन रही है, जिसमें प्राकलन राशि का बोर्ड नहीं है. नाले में सीवर वाले गड्ढे का प्रावधान है जो ठेकेदार द्वारा अपने मन के अनुसार कुछ जगहों पर बनया गया जबकि अधिकतर जगहों पर छोड़ दिया गया. नाले में दो नंबर की ईंट लगाई गई है व गहराई डेढ़ से दो फीट खोदा गया है, वहीं छड़ का जिक्र तक नहीं है. ऐसे में किसी भारी वाहन के प्रवेश करने पर सड़क का धंसना लाजिमी है और इस प्रकार के नाले से वर्षा का पानी तो क्या घर के चापाकल का पानी निकलना भी मुश्किल है. जूनियर इंजीनियर से लेकर ठेकेदार तक को एस्टीमेट दिखाने को कहा गया, लेकिन सभी ने पल्ला झाड़ लिया जब इस संवाददाता ने कार्यस्थल का अवलोकन किया तो जनता की अवाज़ में दम नज़र आया क्योंकि इस प्रकार की गुणवत्ताविहीन सड़क साल दो साल में घटना का सबब बन सकती है. इसी प्रकार से शास्त्रीनगर गुलाबबाग के कार्य में भी भारी पैमाने पर अनियमितता किये जाने की शिकायत उभर कर सामने आई है. यहां भी नालेयुक्त पीसीसी ढलाई सड़क का निर्माण कराया जा रहा है. जिसको लेकर पवन ठाकुर, मनोज, बबलू, विक्की जैसे अनेक युवकों ने सवाल खड़ा करते हुए जानकारी दी की पाईप के द्वारा नाला बनया गया है जिसके नीचे पुराने ईंट ढलाई की गई है मोहल्ले में भारी वाहन के प्रवेश से इस प्रकार के नाले का टूटना लाजिमी है. साथ ही डेड़ से दो फीट मोटाई वाले पाईप से पूरा मोहल्ला क्या दो चार घरों का पानी भी निकल जाए तो काफी है. वैसे शुरुआत में राममोहनी चौक से अंदर की ओर लगभग 100 फीट तक बिना ढलाई किये ही पाईप को बिछा दिया गया है. सड़क से उखड़े टूटे-फूटे पुराने ईंट का उपयोग पूरे नाले में किया गया है. इस प्रकार के नाले से पानी किधर निकलेगा. यह एक अनुत्तरित सवाल है अत: निश्चित है कि आने वाले समय में इस प्रकार का कार्य विकास नहीं तो विनाश का घोतक जरूर होगा. यहां भी प्राकलन संबंधी कोई बोर्ड नहीं लगा है. जब कार्यपालक अभियंता अशोक पासवान से इन कामों के बारे में जानकारी मांगी गई और इस ओर ध्यान दिलाया गया तो उन्होंने गेंद सहायक अभियंता व जेई के पाले में फेंक दी. साथ ही जानकारी दी की सरदार टोला के काम की प्राकलन राशि पचास लाख व शास्त्री नगर की सैंतीस लाख है.

(पूर्णिया)

-नीरज कुमार सिंह

नवहट्टा - दक्षिण भारतीय कला का गवाह

(सहरसा)

कोसी क्षेत्र में मठ व मंदिरों की कमी नहीं है. इसके बावजूद प्रखंड नवहट्टा में अप्रवासी भारतीय मिश्राबंधु परिवार राजेश्वर मिश्र, हेम मिश्र व सतीश मिश्र अपने पिता स्व. गुंजन मिश्र की स्मृति में माता बाबूदाय देवी के करकमलों से तकरीबन दस करोड़ की लागत से न सिर्फ आधुनिक दुर्गा मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं, बल्कि दक्षिण भारतीय कला को भी कोसी की पावन भूमि पर स्थापित कर रहे हैं. मिश्राबंधु परिवार के तीनों भाई चीन में व्यवसाय कर अपने गांव को सजाने- संवारने का भी मन बनाए हुए हैं. इतना ही नहीं गांव के मुरादपुर, अंग्रेजीपार मुसहरी व शाहीडीह के मल्लिक टोला में भी मंदिर का निर्माण कार्य शुरु है. मिश्राबंधु परिवार की पूज्य मां बाबूदाय देवी भी सामाजिक कार्यो में गहरी अभिरुचि रखती हैं और उनकी परिकल्पना है कि कोसी क्षेत्र के बच्चों के लिए सर्व सुविधा उपलब्ध विद्यालय हो. वह अपने तीनों पुत्रों को हर समय समाज सेवा की भावना से ओतप्रोत करने में जुटी रहती हैं. कोसी क्षेत्र में मिश्राबंधु परिवार के इन समाजिक व धार्मिक कार्यों को सभी वर्गों में सराहा जा रहा है. लोगों की भी इच्छा है कि अगर बच्चों की उच्चस्तरीय शिक्षा हेतु विद्यालय का निर्माण हो जाए तो इन इलाकों के बच्चों को देहरादून, दार्जिलिंग, कोटा आदि नहीं जाना पड़ेगा.

मिश्राबंधु परिवार के तीनों भाइयों का कहना है कि सरकार अगर सहयोग करे तो वे कोसी क्षेत्र में उद्योग की भी स्थापना भी कर सकते हैं. लेकिन इस दिशा में पहले सरकार को सकारात्मक पहल करनी होगी. उन्होंने बताया कि कोसी का इलाका अभी भी काफ़ी पिछड़ा है. यहां आने वाली सालाना बाढ़ से हालात और भी बिगड़ जाते हैं. हम लोग चाहते हैं कि हालात बदलें.

-विकास सिंह

ऐसी सड़क बनेगी तो फिर क्या बोलिएगा

(रोहतास)

सड़क को लेकर नीतीश कुमार की लाख चिंता के बावजूद ज़िलों में विभाग के अधिकारी नियम क़ानून ताक पर रखकर अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं. रोहतास ज़िले में बनाए जा रहे ग्रामीण पथों में भारी अनियमितता देखी जा रही है. पथ निर्माण में कम सामग्री लगने की वजह से सड़क तुरंत उखड़ गई. ग्रामीणों द्वारा शिकायत किये जाने के बाद पटना से पहुंची विजिलेंस टीम ने एनएच 30 से बड़हुतीकला गांव तक नवनिर्मित पथ की गुणवत्ता की जांच की. टीम में शामिल अधिकारियों ने गहन जांच करने के बाद टूटी सड़क व नाले को मरम्मत कराने का निर्देश दिया है. बताते चलें कि ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, सासाराम द्वारा नावार्ड योजना के तहत एनएच 30 से बड़हुतीकला गांव तक 1 करोड़ 24 लाख 78 हज़ार 541 रुपये की लागत से करीब दो किलोमीटर पथ का निर्माण कराया गया था. सड़क बनने के बाद ही जगह-जगह उखड़ने लगी. इस पर स्थानीय ग्रामीणों ने पटना के वरीय पदाधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराई थी. इसी आलोक में यहां विजिलेंस की टीम द्वारा सड़क की गुणवत्ता की जांच की गई. कार्यपालक अभियंता प्रमोद कुमार सिन्हा ने बताया कि उक्त पथ की गुणवत्ता की जांच कर ली गई है और रिपोर्ट विभाग को सौंप दी जाएगी. इसे पुन: सुदृढ़ कराने का निर्देश कार्यपालक अभियंता रामनारायण यादव को दिया गया. स्थानीय लोगों का आरोप है कि उक्त पथ निर्माण में विभाग के अधिकारियों द्वारा बंदरबाट हुइ है और कम गुणवत्ता की सामग्री से पथ का निर्माण कराया गया है. ग्रामीणों का कहना है कि जब सड़क बन रही थी और गुणवत्ता में कमी देखी गई, उसी वक्त वरीय पदाधिकारियों से शिकायत की गई थी, लेकिन उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई. विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उक्त पथ के निविदा के समय भी काफी हेराफेरी के आरोप लगाए गए थे. पूरे मामले पर कार्यपालक अभियंता रामनारायण यादव का कहना है कि सड़क में जो भी खराबी आ गई थी, उसे ठीक करने के निर्देश दे दिए गए हैं. उन्होंने निविदा के निपटारे में किसी भी तरह की गड़बड़ी से इंकार किया है. लेकिन सवाल यह उठता है कि जब यह सड़क बन रही थी तो उस समय विभाग के लोगों ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया. सड़क जब बनने के साथ ही उखड़ने लगी तो ग्रामीणों ने हंगामा मचाया और पटना तक अपनी बात रखी. अगर सब कुछ नियम के अनुसार ही होता तो नई सड़क का हाल इतना बुरा नहीं होता.

चौथी दुनिया ब्यूरो

एक नज़र इधर भी

संसाधनविहीन पावर सब-स्टेशन

गया ज़िले के गुरारू पावर सब-स्टेशन मे संसाधनों की कमी तथा जर्जर तारों के कारण बिजली आपूर्ति बाधित है. रफीगंज से आने वाले बिजली लाइन के तार भी जर्जर हो गए हैं. साथ ही यहां बिजली कर्मियों की भी कमी है. सर्किट, व्रिकस्पिन, स्टूलेटर, यूज तार, तेल और दस्ताने न होने से बिजली कर्मी जान पर खेल कर काम करते हैं .

- सुदर्शन कुमार

बालश्रम सभ्य समाज के लिए कलंक

यूनीसेफ एवं बचपन बचाओ आंदोलन द्वारा भागलपुर के विकास भवन सभागार में बाल श्रम उन्मूलन के बने धावा दल को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया. प्रशिक्षण शिविर में सदर एसडीओ राजेश कुमार ने कहा कि बाल श्रम सभ्य समाज के लिए कलंक है. ग़रीबी और अशिक्षा के कारण बाल श्रम की समस्या बढ़ रही है. बचपन बचाओ आंदोलन के प्रदेश पुनर्वास संयोजक घूरण महतो ने कहा कि आर्थिक पिछड़ेपन और अशिक्षा के कारण बच्चे बाल श्रमिक बन रहे हैं.

-स्मृति

अभिजीत व डोंगफेंग में समझौता

झारखंड में पावर और स्टील सेक्टर की औद्योगिक इकाईयों की स्थापना में जुटी निजी क्षेत्र की ख्यातिप्राप्त कंपनी अभिजीत ग्रुप ने सफलता के नये आयाम गढ़ते हुए चीन की कंपनी डोंगफेंग इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन के साथ एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है. डोंगफेंग विद्युत उपकरण बनाने वाली चीन की सबसे बड़ी कंपनी है. अभिजीत ग्रुप ने डोंगफेंग कंपनी के साथ 660 मेगावाट के 10 यूनिटों के लिए विद्युत उपकरण, अभियांत्रिकी सामग्रियों की आपूर्ति के लिए 250 करोड़ डॉलर का करार किया है. डोंगफेंग द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले उपकरण विश्वस्तरीय व आधुनिकतम तकनीकों पर आधारित हैं. गत दिनों दिल्ली में चीन के प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ की उपस्थिति में अभिजीत ग्रुप के चेयरमैन मनोज जायसवाल और डोंगफेंग के चेयरमैन सी जुफेम ने इस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए. मालूम हो कि अभिजीत ग्रुप झारखंड के चंदवा में 1740 मेगावाट का पावर प्लांट और सरायकेला में 2.5 मिलियन टन के स्टील प्लांट के अलावा बिहार के बांका ज़िले में 3960 मेगावाट का पावर प्लांट लगा रहा है. चीन की कंपनी डोंगफेंग के साथ हुए समझौते पर खुशी ज़ाहिर करते हुए अभिजीत ग्रुप के सीईओ अरुण गुप्ता ने कहा कि इस सफलता का श्रेय कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जाता है.

विकलांगों को सहायता राशि देने की मांग

एकमा प्रखंड विकलांग संघ के अध्यक्ष शिव कुमार महतो का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकलांगों के जीवनयापन के लिए 400 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने की घोषणा की थी, जिसकी आस में विकलांग समाज के लोग टकटकी लगाए हुए हैं. मगर उक्त घोषणा आजतक हवा-हवाई साबित हो रही है. इसके अलावा ग़रीब व असहाय व्यक्तियों के लिए राज्य सरकार प्रदत्त वृद्धावस्था पेंशन राशि भी समय पर नहीं मिलती. उन्होंने ज़िला प्रशासन से वृद्धावस्था पेंषन की राशि समय पर भुगतान करने की मांग की है.

-प्रेम कुमार

प्रवासी पक्षियों की देखरेख बनेगा मुद्दा

नरकटियागंज के केहुनिया का विशाल जलाशय में इन दिनों प्रवासी पक्षियों का आना पूरे ज़िले में चर्चा का विषय बना हुआ है. इस क्षेत्र से जुड़ी पंचायतों के संभावित प्रत्याशियों ने इस जलाशय की सुरक्षा का दावा अपने क्षेत्रों में करना प्रारंभ कर दिया है, ताकि आने वाले पंचायत चुनाव में उन्हें वोट मांगने का यह नायाब आधार मिल सके. केहुनिया के रामजानकी मंदिर के आगे इस विशाल जलाशय में प्रवासी पक्षी पधार चुके हैं. गैरी, चकवा, कौआर आदि पक्षियों के आगमन से माहौल गुलजार हो चुका है, वहीं नेताओं ने हमेशा की तरह इस जलाशय की देखरेख को लेकर बयानबाज़ी भी शुरू कर दी है.

-रोशन कुमार

वेतन के लिए तरसे चौकीदार

पांच माह से वेतन के लिए तरस रहे चौकीदारों की सुध लेने वाला कोई नहीं है. उनके परिजनों के आगे भुखमरी की स्थिति हो गई है, लेकिन इस मामले में कोई भी आवाज उठाने वाला नहीं है. आदापुर की कई पंचायतों में अभी से ही इस मसले को लेकर लोगों में गोलबंदी शुरू हो गयी है. आगामी पंचायत चुनाव में यह मुद्दा बन सकता है. आदापुर निवासी अरविंद, साकेत, रघुवीर और रत्नेश ने इस मामले को लेकर शीघ्र ही वेतन अदायगी की मांग की है. साथ ही इन लोगों ने यह भी कहा है कि आगामी पंचायत चुनाव के पहले अगर वेतन भुगतान हो गया तो वोट का रुख उसी ओर होगा. हालांकि सीओ अजय कुमार मिश्र ने आश्वासन दिया है कि वेतन विपत्र बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है .

-नीरज गुप्ता

बदहाल है महनार का पशु अस्पताल

महनार का पशु चिकित्सालय अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है. सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद पशुपालन विभाग की नींद नहीं टूट पा रही है. इस चिकित्सालय में एक डॉक्टर व तीन कर्मचारी पदस्थापित हैं, लेकिन यहां दो कर्मचारी ही दिखाई देते हैं. डॉक्टर के न रहने से लोग सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं. पशुओं में डकहा, मुंहपकवा, सरहा रोगों से दुधारू पशुओं की आए दिन मौत हो रही है. पशुपालक नवल सिंह उर्फ वीरप्पन, अखिलेश सिंह, अफजल खान, मनीष जायसावल, विश्वनाथ राय इत्यादि ने मुख्यमंत्री से अविलंब हस्तक्षेप कर पशु चिकित्सक पर कार्रवाई का आग्रह करते हुए पर्याप्त मात्रा में दवा और चिकित्सा सामग्री देने की मांग की है.

-अंजुम परवेज

महिला कॉलेज का स्थानांतरण अधर में

समस्तीपुर अंतर्गत ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई महिला कॉलेज का स्थानांतरण पुरानी मंडल कारा परिसर में किए जाने की योजना धरी की धरी ही रह गई है. मुख्यमंत्री के फैसले पर तत्कालीन कुलपति ने लाखों रुपये ख़र्च कर पुरानी जेल भवन का कायाकल्प कर उसे महिला कॉलेज के संचालन लायक बनाया. इतनी प्रक्रिया होने के बाद जेल परिसर में चलाए जा रहे कर्पूरी बस पड़ाव अन्यत्र ले जाने की भी योजना बनी, लेकिन महिला कॉलेज का स्थानांतरण पुरानी मंडल कारा में नहीं हो सका. साथ ही जेल परिसर में आज भी कर्पूरी बस पड़ाव का संचालन होता है. छात्राओं की सुरक्षा के मद्देनजर महिला कॉलेज का स्थानांतरण पुरानी जेल परिसर में करने की योजना को मूर्त रूप नहीं मिलने के कारण महिला सशक्तिकरण अभियान में शामिल महिलाओं में क्षोभ है.

स्मारक स्थलों की उपेक्षा

नीतीश राज में भी समस्तीपुर ज़िला मुख्यालय स्थित कर्पूरी स्मारक स्थल में जननायक की प्रतिमा जहां छतरी विहीन है, वहीं स्मारक परिसर में वर्षो से लगी हाई मास्क लाइट की मीनार सिर्फ़ देखने की चीज बनकर रह गई है. यही हाल भगत सिंह स्मारक स्थल का भी है, जहां हाई मास्क लाइट की व्यवस्था तो ज़रूर है, लेकिन लोगों ने इसकी रोशनी कभी देखी नहीं. ज़िला मुख्यालय में संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा छतरी विहीन है और इन सारी प्रतिमाओं पर गंदगी का अंबार लगा रहता है. इनकी साफ़-सफाई सिर्फ इनकी जन्मतिथि या पुण्यतिथि पर ही होती है. जिला मुख्यालय के अंदर ऑफिसर्स कॉलोनी चौक पर गोलंबर का निर्माण कराया गया और गोलंबर परिसर में रोशनी के लिए हाई मास्क लाइट लगाई गई हैं, लेकिन ज़िला प्रशासन की अनदेखी के कारण यहां भी आज तक रोशनी नहीं हो सकी है.

भुसुंडा पशु मेला हुआ फीका

सोनपुर पशुमेले की तर्ज पर ही प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा पर परंपरा से फलगु नदी के तट पर मानपुर मे भुसुंडा सलेमपुर पशुमेला लगता आ रहा है. कुछ वर्षों पूर्व तक इस मेले में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों के पशु व्यवसायी अच्छी नस्ल के पशुओं, विशेष कर गाय-भैंसों को लेकर आते थे. इस दौरान मेले में सर्कस, खेल तमाशे वाले भी आते थे. एक महीने तक सभी व्यवसायी अच्छी कमाई कर अपने राज्य को लौट जाते थे, लेकिन पिछले डेढ़ दशक से इस पशुमेले की रौनक फीकी हो गई है.

- अजय कुमार सिंहा

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

वन प्रमंडल पदाधिकारी ने बिहार सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा, जो किसानों की बर्बादी की दास्तां को बयां कर रहा है.

देश-विदेश तक फैली

गया

तिलकुट की सोंधी सुगंध

उत्तर भारत का सांस्कृतिक नगर गया मौसमी मिष्ठानों के लिए चर्चित रहा है. यहां लगभग हर ऋतु के अनुसार मिष्ठानों के निर्माण की परंपरा आज भी बरकरार है. बरसात के मौसम में अनरसा, गर्मी में लाई एवं जाड़े में तिलकुट का कारोबार उफान पर रहता है. तिलकुट को गया के प्रमुख सांस्कृतिक मिष्ठान के रूप में देश–विदेश में जाना जाता है. लेकिन अपनी विशिष्टता के कारण राष्ट्रीय–अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच बनाने वाला तिलकुट सरकार की उपेक्षा व ज़िला उद्योग केंद्र के असहयोगात्मक रवैये का शिकार है. इस कारण, इसका अपेक्षा के अनुरूप फैलाव नहीं हो पा रहा है. इसकी प्रसिद्धि का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि देश की राजधानी दिल्ली में प्रति वर्ष लगने वाले अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में तिलकुट के स्टॉल लगाने के लिए यहां के कई तिलकुट व्यवसायी दिल्ली जाते हैं.

भौगोलिक दृष्टि से गया की जलवायु इस उद्योग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है. यहां के बने तिलकुट न केवन खास्ता होते हैं, बल्कि इसे नमी से बचाकर रखा जाए तो काफी दिनों तक खास्ता ही रह सकते हैं. मकर संक्रांति जैसे महापर्व पर अपने देश में तिल की बनी वस्तुओं के दान व खाने की धार्मिक परंपरा रही है. इसी महत्व को ध्यान में रखकर यहां तिलकुट का निर्माण किया जाता है. गया में तिलकुट का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ, इसका कोई प्रमाणिक मत तो नहीं है, लेकिन सर्वमान्य धारणा है कि आज से करीब डेढ़ सौ वर्ष पूर्व गया शहर के रमना मोहल्ले में तिलकुट बनना शुरू हुआ था. तिलकुट की शुरुआत करने वाले लोगों के वंशज ही आज इस मौसमी कुटीर उद्योग को आगे बढ़ा रहे हैं. अब तो शहर के टेकारी रोड़, कोयरीबारी, राजेंद्र आश्रम, चांदचौरा, रामपुर, सरकारी बस स्टैंड, स्टेशन रोड आदि में भी तिलकुट का निर्माण किया जा रहा है. कुछ व्यावसायी तो तिलकुट को पैक कर दूर–दराज के क्षेत्रों में भी भेजने का कारोबार बड़े पैमाने पर कर रहे हैं. तिलकुट में उपयोग होने वाली सामाग्रियों को शुरू में बाहर से मंगाया जाता था. उस जमाने में चीनी भी यहां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं थी, लेकिन गया के आसपास के क्षेत्रों में गन्ना की खेती होने के कारण गुड़ आसानी से उपलब्ध हो जाता था और अखरा तिल पड़ोस के पलामु जिले के डालटेनगंज से मंगाया जाता था. शुरू में गुड़ का तिलकुट ही बनता था. लेकिन गुरारू में चीनी मिल की स्थापना हुई और चीनी आसानी से उपलब्ध होने लगी. तबसे चीनी का तिलकुट अधिक बनने लगा. पहले बड़ी मेहनत से तिलकुट को बनाया जाता था. अखरा तिल को ढेकीं में छटाई–कुटाई करने के बाद इसे कपड़े में लपेटकर अंत:सलिला फल्गु नदी के पानी में भिगोया जाती थी. फिर पीटकर इसका छिलका हटाया जाता था. इसके बाद धूप में सुखाया जाता था. फिर गुड़ या चीनी की चाश्नी बनाकर, इसे ठंडाकर टुकड़ों में बांट दिया जाता था. तिल को बड़े पात्रों में भूनकर चाश्नी के ठंडे टुकड़ों के साथ मिलाकर कूटकर तिलकुट तैयार किया जाता था. लेकिन अब इन प्रक्रियाओं के बदले आसान तरीका अपनाया जाता है. देशी गुड़ की जगह चीनी का अधिक प्रयोग किया जाता है. अब तिल को बिना धोए ही प्रयोग में लाया जाता है. इस वजह से तिलकुट का स्वाद अब पहले की तरह नहीं रहा. लेकिन, अभी भी यहां निर्मित तिलकुट का देशभर में कोई सानी नहीं है. जाड़े में गया शहर के तिलकुट बाजार में तिलकुट कूटने की धम–धम की मधुर आवाज तथा सोंधी महक से सारा माहौल उठता है. शहर की दुकानों में अब सालभर तिलकुट उपलब्ध रहता है. तिलकुट का मौसम जाड़े को माना जाता है. इसी समय तिलकुट की खपत सर्वाधिक होती है. मकर संक्रांति के अवसर पर तो तिलकुट की खपत चरम पर होती है. एक अनुमान के मुताबिक़ इस अवसर पर दस हजार क्विंटल से अधिक तिलकुट की बिक्री होती है. मकर संक्रांति के बाद तिलकुट का व्यवसाय धीरे–धीरे कम होने लगता है. तिलकुट बाज़ार में इसका शोर मद्धम होने लगता है. तिलकुट के बारे में बताया जाता है कि इसका इपयोग आयुर्वेदिक दवा के रूप में भी किया जाता है. तिलकुट का ज्यादा सेवन जाड़े में इसलिए किया जाता है, क्योंकि तिल की तासीर गर्म होती है. जाड़े में इसका सेवन अच्छा माना जाता है. इसके नियमित सेवन से कब्ज की बीमारी नहीं होती है. गया के अलावा इस ज़िले के टिकारी तथा मोहनपुर प्रखंड के डंगरा बाज़ार के गुड़ का तिलकुट अपनी अलग पहचान बना चुका है. यहां का तिलकुट बिहार के शहरों के अलावा पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र आदि राज्यों के छोटे–बड़े शहरों में भेजा जाता है. इस व्यवसाय से गया में करीब दस हजार लोग जुड़े हुए हैं. जाड़े में तिलकुट के कारीगरों को अच्छी मजदूरी मिल जाती है. इसके बाद ये बेकार हो जाते हैं. बाद के दिनों में आलू–कचालू, आइसक्रीम बेचकर और रिक्शा चलाकर अपनी जीविका चलाते हैं. पहले तिलकुट व्यवसाय से तीन और व्यवसाय ताड़ के पत्ते का दोना, बांस से बनी डलिया और लकड़ी का बक्सा और कागज का ठोंगा जुड़े थे. तिलकुट के साथ इन चीजों को इसलिए जोड़ा गया था क्योंकि तिलकुट थोड़ा भी दबाव सहने की स्थिति में नहीं होता है. इतना खास्ता और मुलायम कि हल्का झटका लगने पर भी चूर–चूर हो जाता है. दोने और डलियों आदि में किलो–दो किलो तिलकुट लोग सुरक्षित घर ले जाते थे. लेकिन अब इन सबकी जगह पॉलीथीन, कूट का डिब्बा आदि इस्तेमाल होता है.

सुनील सौरभ
feedback@chauthiduniya.com

पू. चं पा र ण

फ़सल पर नील गायों का क़हर

प्रतिवर्ष बाढ़ और सुखाड़ जैसी आपदा से लहूलुहान किसान वन विभाग की लापरवाही की वजह से भी परेशानियों का सामना कर रहे हैं. नीलगायों की बढ़ती संख्या से फ़सलों की बर्बादी इस कदर बढ़ गई है कि किसानों के चेहरे मायूस हो गए हैं. वन प्रमंडल पदाधिकारी ने बिहार सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा, जो किसानों की बर्बादी की दास्तां को बयां करता है. भेजे गये प्रस्ताव के अनुसार पूरे ज़िले में 18 लाख 31 हजार 847 आबादी नीलगायों से त्रस्त हैं. एक लाख 51 हजार हेक्टेयर भूमि में लगी फसलें प्रतिवर्ष नीलगायों की भेंट चढ़ रही हैं. इस प्रकार सालाना 626 करोड़ का नुक़सान किसानों को हो रहा है. इधर मामले को लेकर जब ज़िला पदाधिकारी नर्मदेश्वर लाल से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि इस मसले की गंभीरता को लेकर सरकार ने कई तरह की योजनाएं बनायी हैं, जिससे संबंधित प्रखंडों में अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है. किसान लक्ष्मण पटेल, देवेंद्र सिंह, सुखदेव द्विवेद्वी रामअयोध्या सिंह, संजय यादव, विनोद सिंह, राजकिशोर सिंह, चंदकिशोर राय, नगीना सिंह, मुनीलाल साह, संजय चौधरी , संतोष सिंह, शंभू यादव , जिकरूल्लाह खां, ब्रजनारायण सिंह, अवधेश सिंह, भरत सिंह, जवाहरलाल प्रसाद, राजदेव सहनी व अनिरुद्ध प्रसाद ने गुहार लगाते हुए प्रशासन से अपील की है कि हमारी लंबी लड़ाई को अब विराम दिया जाए और इस समस्या से हमारी धरती को मुक्त कराया जाए.

नीलगायों से संबंधित कुछ तथ्य

1. नीलगाय, हिरण जाति का सबसे बड़ा जानवर है. इसका आकार घोड़े के बराबर होता है.
2. इनकी जनसंख्या बढ़ने का एक कारण यह भी है कि ये अन्य जीवों के विपरीत साल भर सहवास करते हैं.
3. इनकी औसत आयु 21 साल है.
4. बिहार के पटना, भोजपुर, बक्सर, औरंगाबाद, सासाराम, सीवान, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय व मधुबनी ज़िले में नीलगायों का आतंक है.
5. नीलगाय शाकाहारी होती हैं. ये खास तौर से दलहनी फसल, चना, मटर, अरहर और बैगन, फूलगोभी, पत्तागोभी, लोबिया भिंडी आदि को अधिक नुक़सान पहुंचाती हैं. साथ ही धान गेहूं आदि फसलों को खाने के साथ पैंरों से रौंदकर नुक़सान पहुंचाती हैं.
6. नीलगाय की समस्या के समाधान के लिए कई राज्यों समेत पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश में नीलगाय से प्रभावित पंचायतों को सीमित शिकार के लिए अनुज्ञा दी गई है.

किसानों द्वारा किए जा रहे उपाय

1. खड़ी फ़सल पर गौमूत्र तथा गोबर के घोल का छिड़काव.
2. नील गाय, जिस दिशा से उनके खेतों की तरफ आती हैं उस तरफ सफ़ेद चादर टांगकर.
3. फसलचक्र में सुगंधित पौधे जैसे लेमनग्रास, पामारोजा, मेंथा आदि फसलों को लगाना.
4. जला हुआ मोबिल और मिर्च पाउडर मिलाकर भीगे हुए जूट के बोरे को खेत के बाड़ों पर रखना आदि.

मनोज कुमार राव
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड

दिल्ली, 03 जनवरी 2011-09 जनवरी 2011

www.chauthiduniya.com

ज़मीन पर क़ब्ज़ा

यह नेताओं का नया धंधा है

भ्रष्टाचार की काली कमाई से भी पेट नहीं भरा. सो, इन नेताओं ने अब एक नया धंधा शुरु कर दिया है. यह धंधा, ग़रीबों की ज़मीन हड़पने का है. ख़ासकर बुंदेलखंड के उन ग़रीबों की ज़मीन पर क़ब्ज़ा, जिनके लिए दो वक़्त की रोटी का जुगाड़ कर पाना भी आसमान से तारे तोड़ लाने के बराबर है. और इस धंधे में कई ताक़तवर मंत्री तक शामिल हैं. सर्वजन हिताय की बात करने वाली मुख्यमंत्री मायावती को क्या इसकी ख़बर है?

इसरार पठान

प्रदेश की राजनीति पर अपराधीकरण की छाप का असली चेहरा देखना है तो बुंदेलखंड का रुख करना पड़ेगा. यह वही बुंदेलखंड है जो पलायन, भुखमरी, सूखे और किसानों की आत्महत्याओं की वजह से बीते कई वर्षों से सूबे के राजनीति का केंद्र बिंदु है. बुंदेलखंड का प्रदेश की राजनीति में इस बात से भी अहम स्थान है कि सरकार के ख़ेमे का एक बड़ा तबका इसी क्षेत्र से बावस्ता है. सरकार में गहरी दख़ल रखने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बाबू सिंह कुशवाहा के अलावा मंत्री दद्दू प्रसाद, बादशाह सिंह, रतनलाल अहिरवार, भगवती सागर और हरिओम उपाध्याय सरीखे कद्दावर नेता बुंदेलखंड से हैं. श्रम संविदा बोर्ड के चेयरमैन गयाचरन दिनकर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष चैन सुख भारती, समाज कल्याण बोर्ड की सदस्य श्रीमती हीरादेवी, विधान परिषद सदस्य श्रीमती हुसना सिद्दीकी सहित नामित राज्यसभा सदस्यों गंगाचरन राजपूत और ब्रज लाल खाबरी को मिला दें तो सरकार में बुंदेलखंड से प्रतिनिधित्व करने वालों की एक बड़ी कतार उभरकर सामने आती है. अधिकारियों से वसूली, चहेतों को ठेकेदारी और सरकारी योजनाओं का धन डकारने के बाद भी जब इनके भ्रष्ट मनसूबे पूरे नहीं हुए तो इन नेताओं ने ग़रीब जनता को निशाने पर ले लिया. बसपा सरकार के बुंदेलखंडी सिपहसलार भूमाफिया बन चुके हैं. इनके रिश्तेदार और क़रीबी ग़रीबों की बेशक़ीमती भूमि हथिया रहे हैं. इनके मंसूबों को पूरा करने में प्रशासन भी पूरी सहभगिता निभा रहा है. बसपा सरकार के इन नुमाइंदों में वैसे तो कोई किसी से कम नहीं, लेकिन इस मामले में श्रम मंत्री बादशाह सिंह और बहन जी के सबसे चहेते काबीना मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी सबसे आगे हैं. श्रम मंत्रीजी की हमीरपुर तथा महोबा दोनों जनपदों में बादशाहत कायम हैं. इनके इस ग़ैर कानूनी धंधे को इन्हीं का सगा भाई ज्ञान सिंह संचालित करता है. ज्ञान सिंह ने अपने मंत्री भाई की पदवी का इस्तेमाल करते हुए महोबा में करोड़ों की ज़मीन कौड़ियों में ख़रीद ली है. चर्चा है कि इस काम में कुछ भू-माफिया भी उसकी मदद करते हैं, जिसके बदले में उन्हें भी माननीय का बरदहश्त हासिल है. ऐसे लोगों में महमूद नामक एक कपड़ा व्यवसायी और हमीद राईन नाम के भू-माफिया का नाम उछल रहा है. इधर बादशाह सिंह से दो क़दम आगे काबीना मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिये. उन्होंने अपने भाई भतीजों और चमचों को किसी भी हद तक जाने की छूट दे दी है. इनके गृह जनपद बांदा में आज किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं कि वह माननीय के परिजनों की मनमानी का विरोध कर सके.

बांदा जनपद के स्योढ़ा गांव में एक किसान के घर जन्मे नसीमुद्दीन सिद्दीकी जब मायावती सरकार में आधा दर्जन विभागों के मुखिया बनाये गये तो बांदा की जनता उनसे बेशुमार आशाएं बांध बैठी, लेकिन जल्दी ही जनपद वासियों की वह आस टूट गई. उनकी सरपरस्ती में लोगों का जीना हराम हो गया. किसी की ज़मीन छीन लीं तो कहीं नियमों के विपरीत क्रशर स्थापित कर किसानों को बर्बाद करने का बंदोबस्त कर दिया. बांदा निवासी 85 वर्षीय वृद्ध भगवानदीन यादव इसकी बानगी हैं. इस बूढ़े की भूमि को क़ब्ज़ियाने के लिये बेहद ख़ौफ़नाक हथकंडे अपनाए गए. बूढ़े कृषक की बेशक़ीमती ज़मीन माननीय के भाई की नज़र में गड़ गई, फिर उसे हासिल करने के लिये पुलिस को हथियार बनाया गया. भगवानदीन पर सारी जोर-जबरदस्ती की गई, पुलिस उसे और उसके दो बेटों को उठाकर ले गई, जिन्हें बाद में एक भैंस की ख़रीदारी को लेकर दलित के साथ मार-पीट व गाली गलौज करने जैसे आरोप लगाकर जेल में ठूंस दिया गया. अदालत ने भगवानदीन की वृद्धावस्था और दयनीय हालत को देखते हुए उसे शीघ्र जमानत तो दे दी. लेकिन इसके बाद मंत्री के भतीजों की ओर से भगवानदीन को डकैती में फंसाने की धमकियां दी जाने लगी, यह क्रम तब तक चलता रहा जब तक वह अपने मंसूबों पर क़ामयाब नहीं हो गये. हालांकि माननीय के भाई जमीरउद्दीन ने भूमि हथियाते समय क़ानूनी दांव-पेंचो का पूरा ख्याल रखा. भगवानदीन की ज़मीन पहले उपमा गुप्ता के नाम क्रय की गई और मात्र बीस दिन के अंदर ही उस ज़मीन को अकरमी बेगम और उनकी बहू अर्शी के नाम हस्तांतरित कर दिया गया. भूमि उपमा गुप्ता के नाम पर ख़रीदी गई, उपमा गुप्ता सिंचाई विभाग में कार्यरत माननीय के एक बेहद क़रीबी इंजीनियर की पत्नी हैं. इस प्रकरण से मंत्री लाख पल्ला झाड़ें, लेकिन समूचा घटनाक्रम उनकी संलिप्तता की ओर खुला इशारा कर रहा है. कुछ देर के लिए यदि मान भी लिया जाये कि भगवानदीन के साथ हुए अन्याय का मंत्री से कोई कनेक्शन नहीं तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि उपमा गुप्ता ने महज बीस दिन पूर्व ख़रीदी ज़मीन को इतने अल्प समय में बेच दिया और वह भी दाम के दाम? बता दें कि उपमा गुप्ता ने यह भूमि महज़ पांच लाख में ख़रीदी थी और इतने ही रुपयों में अकबरी बेगम आदि को विक्रय भी कर दी. सवाल यह है कि भगवानदीन को सरकारी रेट के मुताबिक़ साठ लाख की बेशक़ीमती भूमि को मात्र पांच लाख में क्यों बेचना पड़ा? नसीमुद्दीन और उनके परिजनों की ज़्यादती के शिकार भगवानदीन इकलौते व्यक्ति नहीं हैं, यह दंश बांदा के कई दिलों को भेद रहा है.

मंत्री और उसके भाई-भतीजों की दबंगई ने किसी का आशियाना उजाड़ दिया, तो किसी के जीवन भर की गाढ़ी कमाई लूट ली. भगवानदीन के वकील अदित्य सिंह कहते हैं कि मंत्री के भाई-भतीजों का यही काम है. उनके मुताबिक़ नसीमुद्दीन के पास जो मंत्रालय हैं, उनसे अवैध धन उगाही और उस धन की देख-भाल का सारा जिम्मा परिवार के सदस्यों को सौंपा गया है. ऐसे ही एक मामले में परेशान बांदा निवासी सैनिक परिवार को तो अपनी ज़मीन बचाने के लिए देश के रक्षा मंत्री एके एंटनी से गुहार लगानी पड़ी. इस सैनिक का आरोप है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के भाई जमीरुद्दीन और उसके बेटे ने उसकी ज़मीन पर क़ब्ज़ा कर रखा है. फौजी दीनदयाल मौजूदा समय में बंगलौर में तैनात है और इसका भाई एलओसी पर डटा देश की रक्षा कर रहा है. बांदा के हर छोटे बड़े अफसर को फौजी के साथ हुई नाइंसाफ़ी की जानकारी है, पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं. बांदा के राजेंद्र और सुधीर की ज़मीनों पर भी इन्हीं का क़ब्ज़ा है, ज़मीन हथियाने के लिये मंत्री के गुर्गे किस हद तक जा सकते हैं इसकी बानगी लखनऊ के वरिष्ठ वकील के घर पर हुए नाजायज क़ब्ज़े से मिलती है. हाईकोर्ट के वकील माधव मुकुंद अस्थाना की फैजाबाद रोड स्थित कोठी पर एके-47 असलहों से लैस नसीमुद्दीन सिद्दीकी के गुर्गों ने अचानक क़ब्ज़ा कर लिया. अस्थाना को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी. हाईकोर्ट ने अर्जेंट बेंच गठित कर दबंगों से कोठी खाली करवाने के लिए सख्त आदेश दिए, तब कहीं जाकर अस्थाना को अपना हक़ वापिस मिल सका. लेकिन बांदा के किसान न तो अस्थाना इतने सोर्सफुल हैं और न ही उनके अंदर दबंगों से मुक़ाबला करने की हिम्मत. लिहाजा वह मुंह बंद किए उस दिन के इंतजार में बैठे हैं, जब बसपा सरकार का कार्यकाल समाप्त होगा और वह उसे और उसकी कैबिनेट के इन माननीयों को अपनी असल ताक़त का एहसास कराएंगे.

feedback@chauthiduniya.com

अब माननीय के निशाने पर कलमकार

बसपा के कद्दावर मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी बांदा जनपद के पत्रकारों को निशाना बना रहे हैं. मंत्री के ख़िलाफ़ लिखने वालों को हर एक प्रकार से सबक सिखाया जा रहा है. कुछ एक पत्रकार तो अपनी नौकरी भी गवां चुके हैं. एक दैनिक समाचार पत्र से जुड़े बांदा ब्यूरो प्रमुख इसी कड़ी का एक हिस्सा हैं, जिन्हें मंत्री की शिकायत के कारण नौकरी गंवानी पड़ी. यहां से निकलने वाले एक अखबार को तो बांदा से अपने इलाहाबाद संस्करण का कार्यालय ही बंद करना पड़ा. वजह उसने मंत्री के परिजनों की कारगुजारियों को ख़बर बनाने की हिमाकत की थी. अखबारनवीसों पर इन कार्रवाइयों ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर तो सवालिया निशान लगाए, साथ में उन अख़बारों के मालिकानों तथा प्रबंधन को भी कठघरे में खड़ा कर दिया जो मात्र व्यावसायिक लाभ के लिये बग़ैर सोचे समझे अपने ही कर्मचारियों पर तलवार चला देते हैं. हद तब हो गई जब सरकार के इस कद्दावर नुमाइंदे के इशारे पर प्रशासन ने स्थानीय स्तर पर प्रकाशित तीन साप्ताहिक अखबारों को अनैतिक ढंग से बंद करने का फरमान सुना दिया. उच्च न्यायालय की शरण में जाने पर इन अखबार के मालिकानों को राहत तो मिल गई, लेकिन अब उन्हें दूसरे ढंग से चुप कराने की जमकर धमकियां मिल रहीं है. बांदा से प्रकाशित साप्ताहिक बेबाक इंडिया के संपादक कहते हैं कि पत्रकारिता एक मिशन है और इसमें ख़तरा तो बना ही रहता है. ख़तरे के डर से दबंगों के सामने नतमस्तक हो गए तो जनता का लोकतंत्र के अन्य खंभों की भांति इस पर से भी विश्वास उठ जाएगा.

कांगेस विधायक ने खोला मोर्चा

बुंदेलखंड में बसपाइयों की मनमानी के ख़िलाफ़ बांदा के सदर विधायक विवेक सिंह ने ऐलान-ए-जंग कर दिया है. चौथी दुनिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश की दशा देखकर नहीं लगता कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में सांस ले रहे हैं. किसानों पर अत्याचार की बाबत उन्होंने कहा कि वह किसी भी क़ीमत पर ऐसा नहीं होने देंगे. चाहे इसके लिए कोई क़ीमत चुकानी पड़े. भगवानदीन यादव के मामले में बात करने पर अफसोस जताते हुए कहते हैं कि मंत्री के परिजनों का यह कृत्य आगे चलकर उन्हीं के लिए नासूर बन जाएगा. उनकी माने तो आज मंत्री और उनके परिवार वालों के पास इतनी ज़मीन है, जितनी शायद बांदा के नवाबों के पास भी नहीं रही होगी. बांदा में जितने बड़े-बड़े ठेके उठ रहे हैं, वह सब मंत्री के लोग ही उठा रहे हैं. इनके पारिवारिक मानचित्र का खाका खींचते हुए बताते हैं कि इनके एक भाई का नाम हसन सिद्दीकी है. कहने को तो यह रेलवे में टीटी हैं लेकिन इनके पास संपत्ति अरबों की है. उनकी गाड़ियां, कोठी और रहन-सहन देखकर नहीं लगता कि यह एक सरकारी मुलाज़िम हैं. विवेक कुमार सिंह कहते हैं कि अभी तो इनके दहशत की बादशाहत कायम है. चुनाव आने दीजिए. मतदाता ईंट का जवाब वोट रूपी पत्थर से देगा.

अस्सी नब्बे के दशक में जितनी महिला डकैत हुईं, उनमें से अधिकतर डकैत गिरोहों के सरदारों द्वारा अपहरण कर लाई गई थीं.

श्रवण को लेकर जब राजा दशरथ उनके माता पिता के पास पहुंचे तब तक श्रवण मर चुके थे. आहत श्रवण के माता पिता ने पुत्र वियोग में दशरथ को श्राप दे डाला.

कल चमन था आज वीरान हुआ चंबल

ये डकैत थे या बाग़ी

रिज़वान चंचल

चंबल जो कि ख़ूंखार डकैतों के शरण स्थली के रूप में जाना जाता था, आजकल वीरान सा है. उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के ज़्यादातर दस्यु गिरोहों के ख़ात्मे के चलते दस्युओं का ख़ौफ़ जो ग्रामीणों के सिर चढ़कर बोलता था अब नज़र नहीं आता, चंबल के निकट बसे ग्रामीण अधिकतर डकैतों को डकैत नहीं बल्कि बाग़ी कहना ज़्यादा पसंद करते हैं. ग्रामीणों के मुताबिक़ चंबल के डाकुओं के अपने आदर्श और सिद्धांत हुआ करते थे, अमीरों को लूटना और ग़रीबों की मदद करना चंबल के डाकुओं का शगल हुआ करता था. अन्याय और शोषण के ख़िलाफ़ विद्रोह करने वाले दस्यु भले ही पुलिस फाइलों में डकैत के नाम से जाने जाते हों, लेकिन उनके नेक कामों से लोग उन्हें सम्मान से बाग़ी ही मानते हैं. डकैत मान सिंह ग़रीबी और ज़मीन बंटवारे व भेद भाव के कारण अपराध का रास्ता अपनाया. 1939 और 1955 के बीच मान सिंह पर क़रीब 1112 डकैती और (32 पुलिस अधिकारियों की हत्या सहित) 185 हत्याओं का आरोप था.

चंबल के पुरानी पीढ़ी के डकैत महिलाओं का बहुत सम्मान करते थे. पहले के डकैत महिलाओं को हाथ नहीं लगाते थे, महिलाओं का मंगलसूत्र कभी नहीं लूटते थे. पहली और दूसरी पीढ़ी के डकैत इस सिद्धांत और आदर्श को मानते थे. तब गिरोह में किसी महिला सदस्य का प्रवेश वर्जित था. लेकिन तीसरी पीढ़ी के डाकुओं ने अपने आदर्श बदल लिए. चंबल के बीहड़ों में लंबे समय तक कार्यरत रहे एक पूर्व पुलिस अधिकारी के मुताबिक़ तीसरी पीढ़ी के डकैत महिलाओं को अगवा कर बीहड़ों तक भी ले गए. अस्सी नब्बे के दशक में जितनी महिला डकैत हुईं, उनमें से अधिकतर डकैत गिरोहों के सरदारों द्वारा अपहरण कर लाई गई थीं. चंबल में पुतली बाई का नाम पहली महिला डकैत के रूप में दर्ज़ है. ग़रीब मुस्लिम परिवार में जन्मी गौहरबानो को परिवार का पेट पालने के लिए नृत्यांगना बनना पड़ा. ख़ूबसूरत पुतलीबाई पर सुल्ताना डकैत की नज़र पड़ी. वह गिरोह के मनोरंजन के लिए पुतली को जबरन बुलाने लगा. पुतलीबाई अपना घर-बार छोड़ कर सुल्ताना के साथ बीहड़ों में रहने लगी. पुलिस इनकाउंटर में सुल्ताना के मारे जाने के बाद पुतलीबाई गिरोह की सरदार बनी. 1950 से 1956 तक बीहड़ों में उसका ज़बरदस्त आतंक रहा. पुतली बाई की गिरोह के सरदार के रूप में सबसे ज़्यादा पुलिस से मुठभेड़ हुई. बीहड़ में अपनी निडरता और साहस के लिए जानी जाने वाली पुतली बाई 23 जनवरी, 1956 को शिवपुरी के जंगलों में पुलिस द्वारा इनकाउंटर में मारी गई. पुराने दस्यु सरगनाओं में तहसीलदार सिंह, मोहर सिंह और माधो सिंह का नाम भी आता है. मोहर सिंह और माधो सिंह 1972 में 511 डकैतों के साथ आत्मसमर्पण के बाद समाज सेवा में जुट गए. पुतली बाई के बाद फूलन देवी व कुसमा नाइन को ख़ूंखार दस्यु सुंदरियों के रूप में जाना जाता है. विक्रम मल्लाह का साथ फूलन ने और फक्कड़ का साथ कुसमा ने अंत तक नहीं छोड़ा. गिरोह बंटने पर कुसमा नाइन कुछ दिनों लालाराम गिरोह में भी रही किंतु सीमा परिहार से लालाराम की निकटता के चलते वह राम आसरे उर्फ फक्कड़ के साथ जुड़ गई. सालों फक्कड़ के साथ बीहड़ों में बिताने के बाद 8 जून, 2004 को भिंड में मध्य प्रदेश पुलिस के सामने उसने आत्म समर्पण कर दिया. फ़िलहाल दोनों जेल में हैं. दस्यु फूलन देवी के द्वारा 14 फरवरी 1981 को किए गए बेहमई कांड में फूलन ने एक साथ क़रीब 22 ठाकुरों को लाइन में खड़ा कर मौत के घाट उतार दिया था, जिसका बदला कुसमा ने 23 मई को उत्तर प्रदेश के औरैया ज़िले के मईअस्ता गांव के 13 मल्लाहों को लाइन में खड़ा कर फुलन के तर्ज़ पर ही गोलियों से भून कर लिया था. 1976 से 1983 तक चंबल में फूलन ने राज किया और 12 फरवरी, 1983 को मध्य प्रदेश पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की उपस्थिती में क़रीब 10 हज़ार जनता व 300 से अधिक पुलिसकर्मियों के सामने आत्मसमर्पण करने वाली फूलन ने सरकार के सामने पांच मांगें रखीं थीं. जिसमें अपने भाई को सरकारी नौकरी व पिता को आवासीय प्लाट तथा मृत्युदंड न होना और 8 साल से अधिक जेल न होना प्रमुख थीं. बाद में वह 1994 में पैरोल पर आई तथा एकलव्य सेना का गठन किया. महात्मा गांधी व दुर्गा को आदर्श व पूज्य मानने वाली फूलन ने राजनीति में रुचि ली और सांसद भी बनीं. लेकिन 25 जुलाई, 2001 को दिल्ली के सरकारी निवास पर उनकी हत्या कर दी गई. सीमा परिहार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था. फूलन की तर्ज़ पर चलने वाली सीमा परिहार भी दस्यु सुंदरी के रूप में बीहड़ों में काफ़ी चर्चित रहीं. दस्यु सरगना लालाराम सीमा परिहार को उठा कर बीहड़ लाया था और बाद में लालाराम ने गिरोह के एक सदस्य निर्भय गुर्जर से सीमा की शादी करवा दी. लेकिन दोनों जल्दी ही अलग हो गए. सीमा परिहार के मुताबिक़ उसे लाला राम से प्रेम हो गया था, फिर उसने लाला राम से शादी कर ली जिससे उसे एक बेटा भी है. 18 मई, 2000 को कानपुर देहात में पुलिस मुठभेड़ में लालाराम के मारे जाने के बाद 30 नवंबर, 2000 को सीमा परिहार ने भी आत्म समर्पण कर दिया. फ़िलहाल वह जमानत पर रिहा हैं और औरैया में रहते हुए राजनीति में सक्रिय है. सीमा फूलन देवी के ही चुनाव क्षेत्र मिर्ज़ापुर से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुकी हैं. अपनी कहानी पर बनी एक फिल्म में भी वे अपना किरदार निभा चुकी है, साथ ही रियलिटी शो बिग बॉस में भी काम कर चुकी है. इन दस्यु सुंदरयों में रज्जन गुजर के साथ रही लवली पांडे का भी काफी आतंक था. लवली उत्तर प्रदेश के इटावा के भरेह गांव की रहने वाली थी. 1992 में लवली की शादी हो गई थी, लेकिन पति ने उसे तलाक दे दिया. पिता की मौत और पति द्वारा ठुकराए जाने से आहत लवली की मुलाकात दस्यु सरगना रज्जन गुर्जर से हुई और दोनों में प्यार हो गया. रज्जन से रिश्ते को लेकर लवली को गांव वालों के भला-बुरा कहने पर रज्जन ने भरेह के ही एक मंदिर में डाकुओं की मौजूदगी में लवली से शादी कर ली. आतंक की पर्याय बनी 50 हज़ार की इनामी यह दस्यु सुंदरी 5 मार्च 2000 को अपने प्रेमी रज्जन गुर्जर के साथ पुलिस मुठभेड़ में मारी गई. श्याम जाटव को डकैत निर्भय गुर्जर ने अपना दत्तक पुत्र घोषित किया था. औरैया की रहने वाली नीलम गुप्ता का निर्भय ने 26 जनवरी, 2004 को अपहरण कर लिया था. महिलाओं के शौकीन निर्भय ने नीलम को अपना रखैल बना लिया, लेकिन जवानी व अल्लहड़पन में खोई दस्यु सुंदरी नीलम को बाबाओं की तरह दाढ़ी रखे निर्भय पसंद नही आए और उसने निर्भय के दत्तक पुत्र से ही आखें चार करनी शुरू कर दीं. नीलम और श्याम जाटव का प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि दोनों ने निर्भय के ख़ौफ़ के बावजूद शादी कर ली. बाद में निर्भय ने दोनों की हत्या के काफ़ी प्रयास भी किए, लेकिन निर्भय से बचने के लिए दोनों ने उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. फ़िलहाल दोनों जेल में हैं, जबकि निर्भय क़रीब डेढ़ दशक पूर्व मारा गया. पुलिस रिकार्ड कहते हैं कि दस्यु निर्भय लगभग 239 गंभीर अपराधों में आरोपित था. हत्याएं, अपहरण, जबरन वसूली, सशस्त्र डकैती के सैकड़ों वारदातों को अंजाम दे चुका था.

इधर एसटीएफ द्वारा दस्यु ददुआ और दस्यु ठोकिया को मुठभेड़ में मार गिराया गया. हाल ही में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पुलिस ने 40 हज़ार रुपये के ईनामी डकैत शंकर कोल को भी चित्रकूट ज़िले में पुलिस ने मुठभेड में मार गिराया. इन सबके अलावा सलीम गूजर-सुरेखा, चंदन यादव-रेनू यादव, मानसिंह-भालो तिवारी, सरनाम सिंह-प्रभा कटियार, तिलक सिंह-शीला, जयसिंह गुर्जर-सुनीता बाथम, बंसती पाडेय की जोड़ियां बीहड़ों में काफ़ी चर्चित रहीं. इनमें से सीमा परिहार और सुरेखा तथा रेनू यादव ने तो अपने प्रेमियों की निशानी के रूप में बच्चे को भी जन्म दिया. हत्या, अपहरण, लूट और डकैती जैसे 70 से ज़्यादा जघन्य अपराधों के आरोपी और 15 सालों से तीन राज्यों की पुलिस को नाको चने चबाने वाले दुर्दांत डकैत जगन ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया ताकि वह अपनी प्रेमिका और दस्यु सुंदरी कोमेश केसाथ रह सके. राजस्थान के धौलपुर ज़िले के पूर्व सरपंच छीतरिया गुर्जर की बेटी कोमेश अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए बंदूक उठा कर बीहड़ों में आई. गिरोह में साथ-साथ रहने के बाद जगन और कोमेश एक दूसरे के क़रीब हो गए. साढ़े चार फुट लंबी 28 वर्षीय कोमेश गिरोह में जगन की ढाल मानी जाने लगी. पिछले साल नवंबर में मध्य प्रदेश की मुरैना पुलिस केसाथ मुठभेड़ में गोली लगने से कोमेश घायल हो गई. जगन उसे पुलिस की नज़रों से बचा कर अपने साथ ले गया. लेकिन राजस्थान के धौलपुर के समरपुरा के एक नर्सिंग होम में 5 नवंबर, 2008 को इलाज करा रही कोमेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. कोमेश की जुदाई जगन से बर्दाश्त नहीं हुई और उससे मिलने को बेचैन जगन ने 31 जनवरी, 2009 को राजस्थान के करौली ज़िले के कैमरी गांव के जगदीश मंदिर में राजस्थान से सांसद सचिन पायलट के सामने इस शर्त पर आत्मसमर्पण कर दिया कि उसे और कोमेश को एक ही जेल में रखा जाए. आत्मसमर्पण के समय जगन ने भावुक हो कर कहा, वह अब आम आदमी की तरह सामाजिक जीवन जीना चाहता है. पुलिस फाइलों में इन दस्यु सरगनाओं व महिला डकैतों के अपराधों के किस्से तो दर्ज़ हैं, लेकिन, उनके प्रेम और समर्पण की मिसालें नहीं. कई बार चंबल में दस्यु सरगनाओं के बीच गुटबंदी व दस्यु सुंदरियों के बीच पनपे सौतिया डाह को लेकर भी गोलियों की तड़तड़ाहट हुई. कभी सीमा परिहार को ठिकाने लगाने का मन कुसमा नाइन ने बनाया तो कभी बसंती ने नीलम को. आज चंबल में न तो दस्यु सुदरियों की चूड़ियां खनकती हैं और न ही अब गोलियों की तड़तड़ाहट ही सुनाई पड़ती है. शीर्ष के ज़्यादातर डकैत मारे जा चुके हैं. कुछ छोटे गिरोह जो बचे भी हैं वे चुपचाप गिरोह को मज़बूती देने में लगे हैं.

feedback@chauthiduniya.com

दस्यु फूलन देवी के द्वारा 14 फरवरी 1981 को किए गए बेहमई कांड में फूलन ने एक साथ क़रीब 22 ठाकुरों को लाइन में खड़ा कर मौत के घाट उतार दिया था, जिसका बदला कुसमा ने 23 मई को उत्तर प्रदेश के औरैया ज़िले के मईअस्ता गांव के 13 मल्लाहों को लाइन में खड़ा कर फूलन के तर्ज़ पर ही गोलियों से भून कर लिया था.

नए साल में होंगे नए सियासी पैंतरे

उत्तर प्रदेश की सियासत में नए वर्ष 2011 का आगाज़ सियासत की शतरंजी चालों से होगा. बसपा सरकार अपनी छवि सुधारने और जनहित में कराए गए कार्यों के महिमा मंडन करने की शुरुआत करेगी तो विरोधी उसमें मीन मेख निकालेंगे. वर्ष 2010 राजनीतिक दलों ख़ासतौर पर बसपा और सपा के लिए खट्टी-मीठी यादों का सफ़र रहा. सत्ताधारी बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को तो यह साल जाते-जाते लालबत्तियों की सौगात दे गया. ज़िला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में जीते अधिकांश नेता बसपा मंत्रियों और विधायकों के रिश्तेदार जो ठहरे. इन चुनावों के बाद गंवई राजनीति में बसपा का पलड़ा साफ़ तौर पर भारी हुआ है. साल ख़त्म होते-होते सपा ने लखीमपुर और निधौलीकलां विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव जीतकर ख़ुद को मुख्य विपक्षी दल साबित किया तो उसके पुराने साथी आजम ख़ान घर वापस आ गए. इन सबके बीच कांग्रेस और भाजपा की स्थिति तमाशबीन से ज़्यादा नहीं रही. उमा भारती को यूपी में प्रोजेक्ट कर लालकृष्ण आडवाणी ने एक हंगामा पैदा करने की कोशिश तो की लेकिन उसकी हवा ख़ुद उमा ने निकाल दी. उमा ने ख़ुद के उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ने की चर्चा को इस साल का सबसे बड़ा मज़ाक क़रार दिया. इसके बाद भाजपा नेताओं को सफ़ाई देते नहीं सूझ रहा है. राजनीति के इस सफ़र में नया वर्ष सभी दलों की चुनावी रणनीति को अमल में लाने का होगा, इसमें किसी को तनिक भी संदेह नहीं है. कांग्रेस और भाजपा की चुनावी तैयारी भले ही ख़ास न दिख रही हो लेकिन इन दोनों ही दलों ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव समय से पहले होने की संभावना ज़ाहिर कर दी है. सपा भी इससे इनकार नहीं कर रही है. ऐसे में तय है कि वर्ष 2011 यूपी की राजनीति में मतदाताओं को गोलबंद करने और खास तौर पर जातीय गणित फिट करने का होगा.

जातीय गोलबंदी और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराने की कोशिशें नए साल में हों तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए. बिहार के चुनावी परिदृश्य और नतीजों से सीख लेते हुए राजनीतिक दल विकास की बातें तो कर रहे हैं लेकिन इसका कोई एजेंडा उनके पास दिखाई नहीं देता है. धर्मनिरपेक्ष दल होने का दावा करने वाली कांग्रेस हो या फिर बसपा और सपा, सभी की नज़र मुस्लिम वोटों पर है. आजम ख़ान की घर वापसी के लिए सपा की छटपटाहट इसी वजह से थी. अब आजम सपा में आ चुके हैं और उनकी पूरी कोशिश मुलायम को एक बार फिर मुल्ला मौलाना मुलायम बनाने की है. कांग्रेस भी अपने इस पुराने वोट बैंक को वापस पंजे की ओर खींचने की कोशिश करेगी. बसपा सुप्रीमो मायावती को पूरा भरोसा है कि मुस्लिम उनके साथ मज़बूती से खड़ा है. इसी 15 जनवरी को मायावती का जन्मदिन है जो अपने ख़ास राजनीतिक आयोजन के लिए भी जाना जाता है. नए साल में विधानसभा चुनावों की पदचाप सुनाई देने का असर ही है कि मायावती ने कार्यकर्ताओं को इस बार उपहार देने से परहेज बरतने की सख्त ताकीद दी है. सत्तारूढ़ बहुजन समाज पार्टी को अपने दलित, अति पिछड़े, मुस्लिम और ब्राह्मण मतदाताओं के भरोसे सरकार में वापसी का पक्का विश्वास है. मुस्लिमों के बाद इस बार ब्राह्मण मतदाता सभी दलों की नज़र में हैं. मायावती पिछले चुनावों में ब्राह्मणों का आशीर्वाद हासिल कर पूरे बहुमत से मुख्यमंत्री बनने में सफ़ल रहीं थी. पिछड़ों की राजनीति करने वाले मुलायम सिंह यादव को भी ब्राह्मण मतदाताओं की नाराज़गी ख़त्म करने की चिंता है. इसके मद्देनज़र ही सपा ने ब्राह्मण प्रत्याशियों को अधिक टिकट दिए जाने का संकेत भी दिया है. सपा के सामने सबसे बड़ी दिक्कत सर्वमान्य ब्राह्मण नेता का अभाव है. जनेश्वर मिश्र के निधन के बाद सपा के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिससे वह ब्राह्मणों को साइकिल की सवारी करा सके. अमर सिंह के जाने के बाद राजा भैय्या को अपने पाले में खड़ा कर मुलायम ने ठाकुर मतदाताओं को रिझाने की सफ़ल कोशिश ज़रूर की है. भाजपा नए साल में हिंदुत्व का कार्ड खेलने से परहेज नहीं करेगी. उमा भारती भले ही अभी कुछ बयान दे रही हों लेकिन आख़िर में वह भी संघ और भाजपा की पैरवी करती नज़र आएंगी. राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी की मंजूरी मिलने के बाद 14 जनवरी से भाजपा अपने अभियान में लग जाएगी. इसके अगले ही दिन मुख्यमंत्री मायावती अपना जन्मदिन मनाएंगी और इस मौक़े पर होने वाले राजनीतिक आयोजन के ज़रिए बसपा कार्यकर्ताओं को भी संदेश मिल जाएगा. वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ कल्याण सिंह भी थे. इस बार कल्याण सिंह भाजपा के ख़िलाफ़ ताल ठोंकते नज़र आएंगे. राजनीतिक गलियारों की चर्चा पर विश्वास करें तो भाजपा को कमज़ोर करने के लिए बसपा अपरोक्ष रूप से कल्याण को बल प्रदान करने में लगी है. इन चर्चाओं में अगर थोड़ा सा भी दम है तो यह भाजपा के लिए बड़े ख़तरे की घंटी है. वहीं कांग्रेस नए साल में सोनिया, राहुल और प्रियंका की तिकड़ी के सहारे अपना खोया जनाधार पाने की कोशिश एक बार फिर करेगी. ब्राह्मण मतदाताओं को लुभाने के लिए ही लाख विरोध के बावजूद रीता बहुगुणा जोशी को अध्यक्ष पद की बागडोर दोबारा सौंपी गई. पार्टी के पास प्रमोद तिवारी के रूप में एक ऐसा चेहरा है जो लगातार विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा हैं. पिछड़े वर्ग के नुमाइंदों में रामनरेश यादव, बेनी प्रसाद वर्मा जैसे कई चेहरे हैं. इन सबके बावजूद इन कांग्रेसियों को यह चिंता भी नहीं है कि यूपी में पार्टी संगठन समाप्त हो चुका है. बूथ स्तर पर कार्यकर्ता तलाशे नहीं मिलते. ऐसे में चुनावी नैया कैसे पार होगी, इस पर कांग्रेस के नेता विचार मंथन करने को तैयार नहीं है.

विजय यादव
feedback@chauthiduniya.com

2011 में मीडिया मार्केटिंग का फंडा

बहुजन समाज पार्टी की सरकार नए वर्ष में मीडिया मार्केटिंग का फंडा भी इस्तेमाल करने जा रही है. सरकार की मंशा के मद्देनज़र सूचना विभाग ने कमर कस ली है. आम जनता के बीच मायावती सरकार की छवि अच्छी बनाने के लिए जनहित से जुड़ी ख़बरों को स्टोरी के रूप में प्रकाशित कराने का लक्ष्य रखा गया है. ज़िला सूचना अधिकारियों से कहा गया है कि वह केवल बयान जारी करने तक ख़ुद को सीमित न रखें. बल्कि यह तय करें कि उनके ज़िले में विकास के जो कार्य हुए हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी अख़बारों में प्रकाशित हो सके. इसके लिए प्रत्येक ज़िला सूचना अधिकारी को सक्सेस स्टोरी का प्रारूप बनाकर उसे सूचना निदेशक के पास भेजने को कहा गया है ताकि उसे अख़बारों में प्रकाशित कराकर माया सरकार का गुणगान किया जा सके. असल में सरकार की चिंता इस बात को लेकर भी है कि विरोधी दल तरह-तरह के आरोप लगाकर मीडिया में सुर्ख़ियां पा जाते हैं और सरकार के कार्यों और उपलब्धियों का प्रचार नहीं हो पा रहा है. बिहार में नीतीश कुमार के कार्यों का जिस तरह से मीडिया के ज़रिए प्रचार हुआ, उसके सफ़ल परिणाम माया सरकार को दिखाई दे चुके हैं. ऐसे में सरकार ने अब मीडिया से दूरी समाप्त करने का मन बना लिया है. नए साल से इस दोस्ती को परवान चढ़ाने की कोशिश होगी जो चुनाव तक हर हाल में जारी रहेगी. इसके मद्देनज़र ही सभी ज़िलाधिकारियों को अपने अपने ज़िले के संवाददाताओं से अच्छे संबंध स्थापित करने और सामंजस्य बनाने को कहा गया है. ज़िला सूचना अधिकारियों से यह तक कहा गया है कि जो भी ज़िलाधिकारी अपने स्थानीय संवाददाताओं से मिलने में कतराते हैं, उसकी जानकारी सूचना निदेशक के ज़रिए शासन को दी जाए ताकि मीडिया से बढ़ती दूरी को कम किया जा सके. इसे देखते हुए एक बात तो तय है कि चुनाव में सरकार को कोई फ़ायदा हो या नहीं लेकिन मीडिया को सत्ता के क़रीब आने का मौक़ा ज़रूर मिल गया है.

बदहाल उत्तर प्रदेश में बेहाल शिक्षा

अरविंद जयतिलक

हाल ही में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बीएल जोशी ने शिक्षा के गिरते स्तर और अराजक होते शैक्षिक माहौल से निपटने के लिए राज्य भर के विश्व विद्यालयों के कुलपतियों के साथ गहन चिंतन-मनन किया. राज्यपाल की चिंता इस संदर्भ से जुड़ी थी कि उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय गुणवत्तापरक शिक्षा देने में विफल हो रहे हैं, साथ ही अनुशासन बना पाने में भी नाकाम सिद्ध हो रहे हैं. सच्चाई यह है कि प्रदेश में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा भी गर्त में जाती ही दिख रही है. और इसके लिए कहीं न कहीं यूपी की सरकार ही ज़िम्मेदार है. देश के अन्य राज्यों में शिक्षा का अधिकार क़ानून तक़रीबन लागू हो गया है लेकिन यूपी की सरकार शिक्षा अधिकार क़ानून को अमली जामा पहनाने के लिए प्रस्तावित आदर्श नियमावली ही मंजूर नहीं कर पाई है. ग़ौरतलब है कि शिक्षा अधिकार क़ानून इसके तहत 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलनी है. लेकिन अभी भी यूपी और केंद्र सरकार के बीच इस पर ख़र्च होने वाली धनराशि को लेकर ही किचकिच मची है. यूपी में शिक्षा अधिकार क़ानून लागू करने के लिए 18000 करोड़ रुपए की ज़रूरत होगी. इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा यह योजना बनाई गई थी कि 55 फ़ीसदी हिस्सा उसका होगा और 45 फ़ीसदी हिस्सा राज्य सरकारों को ख़र्च करना होगा. लेकिन यूपी सरकार इतनी धनराशि ख़र्च करने को तैयार नहीं दिखी. नतीजतन केंद्र सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा कि वह शिक्षा अधिकार क़ानून लागू करने के लिए 55 फ़ीसदी के बजाए 65 फ़ीसदी हिस्सा ख़र्च करेगी और राज्य सरकारों को अब 35 फ़ीसदी ही हिस्सा ख़र्च करना होगा. लेकिन इसके बावजूद यूपी की माया सरकार इस दिशा में सार्थक पहल नहीं कर रही है.

वह केंद्र सरकार से यह आश्वासन लेना चाहती है कि सन 2014 के बाद भी वह अपनी 65 फ़ीसदी की हिस्सेदारी बनाए रखेगी कि नहीं. हर रोज माया सरकार के अफसरान केंद्र सरकार से पत्र व्यवहार करने में ही जुटे पड़े हैं. बजाए इसके कि कैसे शिक्षा अधिकार क़ानून को अमल में लाया जाए. उत्तर प्रदेश में शिक्षा अधिकार क़ानून लागू करने के लिए जो खाका तैयार किया गया है उसके तहत लगभग 4596 नए विद्यालयों की ज़रूरत पड़ेगी और 2349 नए अपर प्राथमिक विद्यालयों की भी दरकार होगी. इसके लिए यूपी सरकार को तक़रीबन 3800 करोड़ रुपए ख़र्च करने होंगे. तीन लाख पच्चीस हज़ार नए अध्यापकों की भर्ती करनी होगी. अपर प्राथमिक विद्यालयों के लिए 67000 नियमित और 44000 पार्टटाइम शिक्षकों की ज़रूरत पड़ेगी. तब जाकर अनिवार्य शिक्षा का ढांचा खड़ा होगा. लेकिन इस दिशा में सरकार कोई सार्थक पहल करती नहीं दिख रही है. प्राथमिक शिक्षा की ही तरह माध्यमिक शिक्षा की भी स्थिति बदतर ही बनी हुई है. यूपी में सरकारी और अनुदानित विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाने के लिए तकरीबन दो लाख से अधिक अध्यापकों की ज़रूरत पड़ती है. लेकिन आज अध्यापकों की भारी कमी है. यूपी में अनुदानित विद्यालयों की संख्या सर्वाधिक है. इन्हीं के भरोसे माध्यमिक शिक्षा का वजूद भी है. अनुदानित विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन किया गया है. लेकिन एक दशक का इतिहास यही बताता है कि शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अपने उद्देश्यों में असफ़ल ही साबित रहा है. कारण यह है कि इसके सदस्यों के चयन की प्रक्रिया पूरी तरह से राजनीतिक हो गयी है. सत्ता में बैठे हुए लोग अपने प्रियजनों को ही वहां नियुक्त करना उचित समझते हैं. दूसरी अहम बात यह कि अध्यापकों की नियक्ति में इतनी लेटलतीफी है कि जितने अध्यापकों की नियक्ति होती है उससे कहीं अधिक अध्यापक सेवानिवृत्त हो जाते हैं. ऐसे में अध्यापकों की किल्लत बराबर बनी रहती है. माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड में यदाकदा भ्रष्टाचार की भी बातें सुनने को मिलती रही है. अगर माध्यमिक विद्यालयों में पठन-पाठन पर गौर फरमाया जाए तो सरकार की लचर नीतियों के कारण स्थिति बिगड़ती ही जा रही है.

सरकारी और अर्धसरकारी विद्यालयों में छात्रों की संख्या लगातार कम होती जा रही है जो यह बताने के लिए काफ़ी है कि शैक्षिक गुणवत्ता को लेकर सरकार की चिंता कितनी है. पिछले दिनों यह बात भी सुनने को मिला था कि शिक्षा विभाग संभाल रहे मंत्रीगण विद्यालयों को मान्यता देने के नाम पर करोड़ों की वसूली कर रहे हैं. यह स्थिति भयंकर है. जहां केंद्र की सरकार उच्च शिक्षा की बेहतरी के लिए नित नए प्रयोग में जुटी पड़ी है, वहीं यूपी में उच्च शिक्षा का मसला अराजकता की भेंट चढ़ता जा रहा है. उच्च शिक्षा में सुधार के नाम पर यूपी सरकार का एक सूत्री कार्यक्रम महाविद्यालयों की संख्या बढ़ाना मात्र रह गया है. सही अर्थो में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सार्थक प्रयास नहीं किया जा रहा है. सच्चाई यह है कि गुणवत्ता पैदा करने के लिए महाविद्यालयों को स्वायत्तशासी और ज़रूरी संसाधनों से लैस करना भी ज़रूरी होता है. लेकिन सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं है.

आज यूपी में महाविद्यालयों की संख्या हज़ारों में पहुंच गयी है. लेकिन इनकी स्थिति पर गौर फरमाया जाए तो ये कहीं से भी महाविद्यालय होने का मानक पूरा नहीं करते. इन महाविद्यालयों के पास न तो ज़रूरत भर ज़मीन है और न ही भवन. हज़ारों की संख्या में इन महाविद्यालयों को सीमित विश्वविद्यालयों से जोड़ दिया गया है. संबद्ध महाविद्यालयों की परीक्षा कराना और उसका समय से परिणाम तैयार करना आज विश्व विद्यालयों के लिए चुनौती भरा कार्य हो गया है. पिछले दिनों देखा गया कि यूपी में बीएड परीक्षा को लेकर कितनी अफरा-तफरी मची रही. एक बार तो पेपर लीक हो जाने से परीक्षा की तिथि में ही परिवर्तन करना पड़ा. अब यूपी सरकार बीएड परीक्षा कराने की जिम्मेदारी किसी एक विश्व विद्यालय को देने के बजाए अलग-अलग विश्वविद्यालयों के कंधे पर डालेगी. लेकिन सवाल परीक्षा कराने तक ही सीमित नहीं है बल्कि उसकी शुचिता को लेकर भी है. विश्वविद्यालयों में रोज नए घोटाले सुनने को मिल रहे हैं. आज आलम यह है कि अभी तक बीएड नामांकन की प्रक्रिया तक पूरी नहीं हो पायी है. ऐसी स्थिति में सत्र को कैसे नियमित किया जा सकता है. अगर यूपी सरकार द्वारा सार्थक शिक्षा नीति बनाकर महा विद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान की जाए तो काफ़ी हद तक इस जटिल समस्या से मुक्ति पाई जा सकती है. लेकिन यूपी सरकार महा विद्यालयों को स्वायतता देने के बजाय कुकुरमत्ते की तरह महा विद्यालय खोलने पर ही उतारू है. आज स्थिति यह है कि यूपी में छोटे-छोटे महा विद्यालय जिनके पास न तो भवन हैं और न ही उचित संसाधन वे भी सरकार की कृपा से इंजीनियरिंग और मेडिकल की कक्षाएं चला रहे हैं. यह उच्च शिक्षा के साथ एक भद्दा मजाक नहीं तो और क्या है. कुकुरमत्ते की तरह उग आये धन के बल पर मान्यता प्राप्त इन महा विद्यालयों में न तो प्रशिक्षित अध्यापक हैं और न ही प्रायोगिक कार्यों के लिए ज़रूरी संसाधन ही उपलब्ध हैं. एक आंकड़े के अनुसार आज यूपी में 85 प्रतिशत इंजीनियरिंग और 40 प्रतिशत मेडिकल कॉलेजों पर सरकार का नियंत्रण नहीं के बराबर है. यह सब निजी क्षेत्र के हैं. शिक्षा के निजीकरण का ही आलम है कि गुणवत्तापरक शिक्षा अब दूर की कौड़ी बनती जा रही है. अगर सरसरी निगाह से देखा जाए तो मेडिकल और इंजीनियरिंग से संबंधित अधिकांश महाविद्यालय उन राजनीतिकों के हैं जिनकी सत्ता में गहरी पैठ है. इसकी बानगी यूपी की राजधानी लखनऊ में ही देखी जा सकती है. एक से एक धन्नासेठों द्वारा इंजीनियरिंग और मेडिकल कालेज चलाए जा रहे हैं, ये न तो ज़रूरी मापदंडों को पूरा कर रहे हैं और न ही क़ानून का डंडा ही इनके ऊपर असर दिखा पाता है. ये महाविद्यालय अपने राजनीतिक रसूख का फायदा उठाकर सिर्फ़ डिग्रियां ही बांटने में लगे हैं और उसके एवज में मोटी धनराशि वसूल रहे हैं. यही कारण है कि आज टेक्निकल शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों की संख्या यूपी में बढ़ती ही जा रही है. एक आंकड़े के अनुसार अकेले कानपुर में ही इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल किए पांच लाख बेरोजगारों की फौज मौजूद है. अगर वाकई यूपी सरकार उच्च शिक्षा के प्रति गंभीर है तो उसे कुछ कड़वे फैसले लेने होंगे. मसलन सबसे पहले शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकना होगा. आजकल केंद्र सरकार की तरह यूपी सरकार भी शिक्षा को बढ़ावा देने के नाम पर नया हथकंडा यानी पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप को आजमाना चाह रही है. सच तो यह है कि सरकार की यह मंशा शिक्षा को आम आदमी की पहुंच से दूर ही करेगा. सरकार को इस पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है. यूपी सरकार को चाहिए कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की संख्या तो बढ़ाए लेकिन उन्हें आधुनिक संसाधनों से लैस भी करे. आम तौर पर देखा जाता है कि निजी क्षेत्र के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रशिक्षित अध्यापक नहीं होते हैं. सिर्फ खानापूर्ति ही की जाती है. और सरकार भी अपनी आंखें मुंदे रहती है. वह दिन दूर नहीं जब यूपी में शिक्षा अपनी बदतर स्थिति में होगी.

feedback@chauthiduniya.com

हत्या के श्राप से आज भी उपेक्षित अंधी-अंधा आश्रम

मातृ-पितृ भक्ति के इकलौते उदाहरण श्रवण कुमार

जन श्रुतियों में श्रवण हत्या के श्राप का दंश झेल रहे क्षेत्रवासी क्या यह मिथक तोड़कर अंधी-अंधा आश्रम का जीर्णोद्धार करवा सकेंगे और क्षेत्र के विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकेंगे? यह यक्ष प्रश्न आज भी जवाब की तलाश में भटक रहा है.

राकेश कुमार यादव

श्रवण आश्रम फैजाबाद जनपद से 16 किलोमीटर दक्षिण फैजाबाद रायबरेली रोड के पश्चिमी सिरे पर अवस्थित है. यह आश्रम पौराणिक धरोहर के रूप में भले ही वर्ष में एक बार पूर्णिमा को क्षेत्रीय मेले के रूप में गुंजायमान होता हो, लेकिन स्वयं में आश्रम स्थल विकास का अंश भी नहीं छू पाया है. पौराणिक मान्यता के अनुसार अयोध्या नरेश राजा दशरथ वन्य जीवों के आखेट के लिए इस क्षेत्र में गए हुए थे, वहीं वारूनी झील में अंधे माता-पिता की प्यास बुझाने के लिए श्रवण अपना पात्र डुबा रहे थे. इस ध्वनि को किसी जंगली जीव की आहट समझकर दशरथ ने हृदयभेदी बाण चला दिया. घायल श्रवण को लेकर जब राजा दशरथ उनके माता पिता के पास पहुंचे तब तक श्रवण मर चुके थे. आहत श्रवण के माता पिता ने पुत्र वियोग में दशरथ को श्राप दे डाला. पुत्र शोक में श्रवण के माता पिता की भी वहीं मृत्यु हो गई. दशरथ ने श्रवण व उनके माता-पिता के शवों को तमसा-विसुही नदी के संगम पर अंतेष्ठि कर दी. वह स्थान अब श्रवण क्षेत्र के रूप जाना जाता है. पर आज भी यह ऐतिहासिक जगह न तो चर्चित हो सकी है और न ही विकसित.

813 एकड़ के क्षेत्रफल में फैले अंधी-अंधा आश्रम पर लगभग 6 मीटर की परिधि में यहां पर अंजान विरवा नामक वृक्ष फैला हुआ है. आश्रम में लगे तेंदू के वृक्ष का प्रयोग यहां के लोग औषधि के रूप में करते हैं. पीती-रामा नामक सरोवर में स्नान लोगों को चर्मरोगों से मुक्ति दिलाने का सुलभ साधन माना जाता है. अंजान विरवा के सामने गड़ा पुराना पाषाण शिलालेख जिस पर हिंदी और अंग्रेजी में श्री-1001 श्रवण आश्रम लिखा हुआ है. इन स्मृतियों का साक्षी है कई सौ साल पुराना कुआं निकटस्थ पीपल का वृक्ष तथा छोटे-छोटे तीन मंदिर जिनमें से एक में माता-पिता सहित श्रवण की प्रतिमा स्थापित है, जो क्षेत्र वासियों के लिए पूज्य व दर्शनीय है.

जहां तक यहां के विकास का प्रश्न है तो क्षेत्रीय लोगों की यह मान्यता निश्चित ही प्रभावी दिखती है कि यह क्षेत्र श्रवण हत्या के श्राप से ग्रस्त है और इसका कभी विकास नहीं हो सकता. गांव के लोग व्यक्तिगत-पारिवारिक विकास के नाम पर इस गांव से पलायन का दंश झेलते-झेलते आजिज आ चुके हैं. बीते तीन दशकों में मिल्कीपुर के कथित महारथी राजनीतिज्ञ पूर्व सांसद विधायक मित्रसेन यादव, व 75 करोड़ का पैकेज ले चुके राम चंदर यादव, भाजपा नेता पूर्व विधायक मथुरा तिवारी, कथित धर्म धुरंधर राष्ट्रीय भाजपा नेता पूर्व सांसद विनय कटियार ने भी इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं किया. स्थानीय क्षेत्रवासियों के नाम पर बारून बाज़ार की नई पीढ़ी ने अब जिस तरह एकजुट होकर वारूनी झील के तट पर स्थित दशरथ तालाब एवं हनुमान मंदिर के जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण से लेकर अंधी-अंधा स्थान को नया रूप देने की योजना बनाकर अमली जामा देने का कार्य शुरू किया है, वह निश्चित ही इस क्षेत्र के श्राप ग्रस्त मिथक को तोड़ने की कड़ी साबित होता प्रतीत हो रहा है.

क्षेत्र के स्थानीय लोगों की मानें तो वह इस क्षेत्र के विकास को लेकर कुछ करना चाहते हैं, जिसमें स्थानीय युवा उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष चंद्र किशोर कौशल जहां जन-जन को इस मातृ-पितृ भक्ति के उदाहरण स्थल अंधी-अंधा आश्रम के प्रति श्रद्धावान होकर अपने-अपने माता-पिता की पुण्य स्मृति में एक नाम अंकित शिलालेख लगवाने की मार्मिक अपील करते हैं. वहीं पूर्व अध्यक्ष एवं जगन्नाथ प्रसाद जायसवाल इंटर कॉलेज के प्रबंधक संजय जायसवाल हर हाल में इस स्थान के प्रति श्रद्धा और आस्था का प्रतीकात्मक कार्य किये जाने हेतु हर व्यक्ति से अपेक्षा करते हैं. अंधी-अंधा संपर्क मार्ग पर स्थित अमन आई केयर सेंटर के चिकित्सक डॉ. मस्त राम यादव इस स्थान के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए ख़ासे चिंतित होकर क्षेत्रवासियों की सुसुप्त भावनाओं को जागृत करने के लिए दृढ़संकल्प नज़र आते हैं. स्थानीय लोकप्रिय युवा समाजसेवी रिंकू उर्फ़ राकेश कौशल पौराणिक और सांस्कृतिक धरोहर अंधी-अंधा स्थान को आज के परिप्रेक्ष्य में मौन परीक्षा लेते देखते हैं. भविष्य के नाम पर वह यह भी कहने में कोई संकोच नहीं करते कि राम रहीम की बात बड़ी संजीदगी से करने वाले लोग आज भी अपने ही माता-पिता के नाम पर चिंतनहीन और संवेदनहीन नज़र आते हैं.

feedback@chauthiduniya.com

शुभकामनाएं

चौथी दुनिया उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड संस्करण के शुभारंभ पर हार्दिक शुभकामनाएं
वेद प्रकाश गुप्ता (प्रदेश अध्यक्ष सपा व्यापार मंडल)
मुलायम सिंह यादव (राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी)

चौथी दुनिया उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड संस्करण के शुभारंभ पर हार्दिक शुभकामनाएं
निर्मल खत्री (सांसद, फैजाबाद)
मुलायम सिंह यादव (राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी)

चौथी दुनिया उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड संस्करण के शुभारंभ पर हार्दिक शुभकामनाएं
गिरीश कुमार पाडेय (डिपुल जिला पंचायत सदस्य, मसौधा फैजाबाद)
मुलायम सिंह यादव (राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी)

चौथी दुनिया उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड संस्करण के शुभारंभ पर हार्दिक शुभकामनाएं
भोला नाथ भारती (सदस्य जिला पंचायत मिल्कीपुर-फैजाबाद)
मुलायम सिंह यादव (राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी)

चौथी दुनिया उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड संस्करण के शुभारंभ पर हार्दिक शुभकामनाएं
जयशंकर पाडेय (जिलाध्यक्ष फैजाबाद)
मुलायम सिंह यादव (राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी)

चौथी दुनिया उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड संस्करण के शुभारंभ पर हार्दिक शुभकामनाएं
तेज नरायन पाडेय (पवन) (युवा सपा नेता फैजाबाद)
मुलायम सिंह यादव (राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी)

चौथी दुनिया उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड संस्करण के शुभारंभ पर हार्दिक शुभकामनाएं
मस्तराम यादव (अमन आई केयर सेंटर एवं आकाश मेडिकल स्टोर श्रवण आश्रम अंधी-अंधा मोड बारून बाजार, फैजाबाद)
मुलायम सिंह यादव (राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी)

चौथी दुनिया उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड संस्करण के शुभारंभ पर हार्दिक शुभकामनाएं
श्याम किशोर कौशल (अध्यक्ष, उद्योग व्यापार मंडल बारून-फैजाबाद)
मुलायम सिंह यादव (राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी)

चौथी दुनिया उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड संस्करण के शुभारंभ पर हार्दिक शुभकामनाएं
संजय जायसवाल, प्रबंधक (जगन्नाथ प्रसाद जायसवाल इंटर कॉलेज देवरिया बारून-फैजाबाद संचालित लोक शिक्षण संस्थान लखनऊ)
मुलायम सिंह यादव (राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी)

चौथी दुनिया उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड संस्करण के शुभारंभ पर हार्दिक शुभकामनाएं
अब्बास अली जैदी रूशदी (विधायक, रूदौली-फैजाबाद)
मुलायम सिंह यादव (राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी)

चौथी दुनिया उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड संस्करण के शुभारंभ पर हार्दिक शुभकामनाएं
राकेश कौशल उर्फ रिंकू (अध्यक्ष जय हनुमान सेवा संस्थान (पंजी0) बारून-फैजाबाद)
मुलायम सिंह यादव (राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी)

चौथी दुनिया उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड संस्करण के शुभारंभ पर हार्दिक शुभकामनाएं
सहदेव उपाध्याय (प्रबंधक, देवा पब्लिक आवासीय स्कूल इसरू अमौना, रानीबाजार-फैजाबाद)
मुलायम सिंह यादव (राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी)

चौथी दुनिया उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड संस्करण के शुभारंभ पर हार्दिक शुभकामनाएं
धर्मेंद्र पाठक (प्रधानाचार्य, माधव सर्वोदय इंटर कालेज अमौना, रानीबाजार-फैजाबाद)
मुलायम सिंह यादव (राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी)